

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1990

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 15 मार्च, 1990

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(4)25
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(4)28

<p>ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—</p> <p>भाहबाद सहकारी चीनी मिल द्वारा प्रयोग किए गए पानी की निकासी के कारण फसलो के नष्ट होने संबंधी</p>	(4)31
<p>वक्तव्य—</p> <p>सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी</p>	(4)32
<p>सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र</p>	(4)34
<p>वर्ष 1990-91 के बजट पर सामान्य चर्चा</p>	(4)34
<p>वाक आउट</p>	(4)71
<p>वर्ष 1990-91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)</p>	(4)72

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 15 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 09.30 बजे हुई। (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Video Coach/Deluxe Buses

***393. Shri Kailash Chand Sharma:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) The number of Video Coach/Deluxe Buses with the Haryana Roadways at present gether with details of routes on which these are plied;

(b) the number of buses, out of these referred to in part (a) above, which have completed their prescribed kilometers; and

(c) whether there is any proposal of the Govt to ply Video Coaches from all district head-quarters in the State?

Home Minister (Prof. Sampat Singh):

(a) 27.

These are being plied on the following routes:-

Chandigarh Delhi	-
Chandigarh Shimla	-
Chandigarh Jaipur	-
Delhi Jaipure	-
Delhi Shimla	-
Yamuna Nagar - Delhi	

(b) 21 Video Coaches/Deluxe Buses have completed their prescribed kilometers.

(c) No.

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 21 वीडियो कोचिज ऐसी है जो अपने निर्धारित किलोमीटर पूरे कर चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये बसें अपने निर्धारित किलोमीटर पूरे करने के बाद और कितनी चल चुकी है और क्या ये और चलने के लायक है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बसिज की लाइफ या तो 6 लाख किलोमीटर चलने पर खत्म होती है या 8 साल के

बाद खत्म होती है। उसके बाद उनको कंडम कर दिया जाता है। इन बसों के अभी 8 साल पूरे नहीं हुए हैं इसलिए अभी इनको बदल नहीं रहे हैं। उनकी हालत अभी ठीक है। जो एक दो बसें खराब होंगी उनको जल्दी बदल देंगे।

श्री कैला 1 चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी की नालेज में है कि जो ये 21 वीडियो कोच हैं इनमें से अधिकतर के वीडियो ठीक नहीं चलते और इनमें से कोई न कोई बस खराब हो कर रास्ते में खड़ी रहती है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बसों की जितनी संख्या ज्यादा होगी उनमें से एक आध तो खराब हो ही सकती है। हाउस को यह जान कर खुशी होगी कि केवल हरियाणा प्रदेश ही ऐसा है जिसमें वीडियो डीलकस बसें इतनी चल रही हैं। पंजाब हिमाचल हमारे साथ लगते हैं, इन दोनों की एक एक बस चलती है। तो वह एक बस कहां बंद होगी और कहां रुकेगी। जहां तक वीडियो का ताल्लुक है, यह बहुत सेंसेटिव इन्स्ट्रूमेंट होती है। यह कई बार खराब हो जाता है और हम उसे ठीक करवा देते हैं।

डा मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन रुट्स में रोहतक को शामिल नहीं कर रखा रोहतक वालों ने क्या गलती कर रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहतक में चूंकि महम का हल्का पडता है, इस वजह से उस रुट पर डीलकस बस नहीं चलाई जाती?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, डीलकस् बस तो नहीं लेकिन सैमी डीलकस् बस रोहतक से बकायदा चलती है। जहाँ तक हमह हल्के की बात है, हमह से तो रोहतक ऐडवैंटेज है।

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आज कल पुलिस कई काम कर रही है और नए नए खास अफसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या अब इन्होंने बसों को भी सम्भाल लिया है? जो बसें खराब हैं, क्या उनको ठीक करवाने के लिए गृह विभाग से कोई विशेष टैक्नीकल ईलाज करवाएंगे?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बसिज का गृह विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है। गृह विभाग तो खुद अपने वाहन इनके वर्क शाप से ठीक करवाता है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल हरियाणा की ट्रांसपोर्ट के बारे में है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने पांच सौ मिनी बसिज खरीदी है। इनके बारे में पहले जो रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक सरकार को मिनी बसिज से बहुत घाटा था। तो नई मिनी बसिज का आर्डर देते समय क्या सरकार ने सोचा था कि जब इनसे घाटा था तो नया आर्डर क्यों दिया जा रहा है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, श्री रणजीत सिंह जी बड़े इंटैलिजेंट मैम्बर हैं। यह डीलक्स बसिज का सवाल है और उन मिनी बसिज में कोई डीलक्स बस नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, भाई कैला । चन्द जी का गिला था कि वीडियो कोच में वीडियो ठीक नहीं चलते लेकिन हम लोगो को यह गिला है कि जब वीडियो चलते हैं तो ऐसी अलील फिल्में दिखाई जाती है कि सहयात्रीयो के साथ बैठ कर देखी नहीं जाती। क्या सरकार कोई ऐसा विचार रखती है कि बसों में केवल आर्ट फिल्में ही दिखाई जाएं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बहिन जी ने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे नोटिस में कोई भी ऐसी बात आएगी तो ऐसी फिल्मो को निकाल देंगे। अगर बहिन जी च्वायस करके फिल्मो के नाम बता दे तो हम केवल वही फिल्में दिखाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि रेवाडी चूंकि नया जिला बना है इसलिए क्या रेवाडी से चण्डीगढ के लिए वीडियो कोच चलाने का सरकार का विचार है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी कोई विचार नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किस किस हैडक्वार्टर से सैमी डीलक बसे चल रही है? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भिवानी से पहले सैमी डीलकस बस

चलती थी, वह कितने दिन से खराब है और वहां से कब तक सैमी डीलकस बस चलाई जाएगी?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां तक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज से सैमी डीलकस बसें चलने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज से सैमी डीलकस बसें चलाई जा रही हैं। अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, जींद, कैथल, रोहतक, यमुनानगर और सिरसा, इन 10 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज से सैमी डीलकस बसें चलाई जा रही हैं। जहां तक भिवानी वाली सैमी डीलकस बस के खराब होने का सवाल है, वह बीच में एक आध बार खराब हो गई होगी। जिस समय नई सैमी डीलकस बसें ली जाएंगी उस समय उसको रिप्ले कर दिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि बसों की लाइफ या तो 6 लाख किलोमीटर चलने पर खत्म होती है या 8 साल के बाद खत्म होती है और उसके बाद उसको कंउम कर दिया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो बस दोनो कंडी शर्तें पूरी कर लेती है तब उसको कंउम कर दिया जाता है या इनमें से एक कंडी शर्त पूरी होने पर कंउम कर दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस समय 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे सैमी डीलक बसें चलाने में क्या दिक्कत है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय 12 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज नहीं हैं बल्कि 4 और नए जिले बनने से 16 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज बन गए हैं। माननीय सदस्य तो पुरानी बात कर रहे हैं। जिस समय नई सैमी डीलक बसें खरीदी जाएंगी उस समय यही कोर्ण्ड की जाएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज से ऐसी बसें चलाई जाएं, अगर ये वायबल रहती हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि बस को 6 लाख किलोमीटर पर या 8 साल के बाद कंडम कर दिया जाता है या दोनो कंडी ंज पूरी होने पर कंडम किया जाता है यानी इनमें से एक कंडी ंज पूरी होने पर कंडम किया जाता है यानी इनमें से एक कंडी ंज पूरी होने पर कंडम किया जाता है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो बसिज दोनो कंडी ंज पूरी कर चुकी हैं उनको 30 अप्रैल तक रिप्लेस कर देंगे और जिन डीलकस बसिज की कंडी ंज अच्छी है लेकिन वे दोनो कंडी ंज पूरी कर चुकी हैं उनको आर्डिनरी बसिज में बदल देंगे।

श्रीमती कला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जितने रुटस पर वीडियो कोच चलाई जा रही हैं क्या उनमें से ऐसा कोई रुट है, जो घाटे में चल रहा है? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या हमारे प्रदेश की वीडियो कोच का किराया हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के अनुसार लिया जाता है या नहीं?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में केवल एक एक वीडियो कोच चल रही है। हरियाणा सरकार ने अलग अलग रुटज़ पर डीलकस, ए० सी० और सैमी डीलकस बसें चला रखी है। जिस रुट पर डीलकस और सैमी डीलकस बसें चल रही है उनको इकट्ठी ऐवरेज निकालते हैं। पर किलोमीटर ऐक्सपेंडीचर 4.04 रुपये है और रीसीट 4.28 रुपये है। इसलिए हम घाटे में नहीं नफे में हैं।

श्रीमती कला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहती हूँ कि किसी भी रुट पर घाटे में वीडियो कोच चल रही है या नहीं?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बहन जी को ऐवरेज आंकड़े बताए हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे लायक गृह मंत्री श्री सम्पत सिंह जी यातायात विभाग से संबंधित सवाल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए भाई रणजीत सिंह को बहुत इंटेलिजेंट कहा और बताया कि सरकार 500 नई मीनी बसें खरीदेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि मिनि बस घाटे में चल रही है तो और बसें खरीदने का क्या फायदा है?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो मैंने इस बारे में जवाब दे दिया है लेकिन मिनि बस का अलग से सवाल लगा

हुआ है। जब उसका जवाब दिया जाएगा तो इस बारे में डिटेल्स बता दी जाएगी।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र भारत का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का दर्शनीय स्थान है और वहां पर फौरनर्ज बहुत अधिक संख्या में आते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुरुक्षेत्र से सैमी डीलकस बस चलाने का सरकार का विचार है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं कटारिया साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली से चण्डीगढ़ के बीच में जो वीडियो कोच चलती है वे सभी पीपली होते हुए चण्डीगढ़ जाती है लेकिन उनमें से एक बस वाया कुरुक्षेत्र होते हुए भी चण्डीगढ़ जाती है।

श्री कैलाश चन्द भार्गव: अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो कोच नारनौल से चलाई गई थी लेकिन उसको 5-7 दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस बस को बंद किए जाने का क्या कारण है?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, उस बस की रीसीट 1.72 रुपए प्रति किलोमीटर थी इसलिए उसे मजबूरी में बंद करना पडा। सवारियों की कमी की वजह से ही ह बस बन्द करनी पडी। यदि ये सवारियों का प्रबंध करवा दे तो हमें वहां से बस चलाने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कुन्दन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद से जो वीडियो कोच बस चलती है उसका वीडियो हमें खराब रहता है। इसके बारे में मैंने कई बार इनको लिख कर भी दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस बस के वीडियो को ठीक कराने का प्रबंध किया जायेगा?

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब जब भी इन्होंने उस बस के वीडियो के खराब होने के बारे में लिख कर दिया है, उस वीडियो को ठीक करा दिया गया है।

Bungling in Insecticide

***1074. Shri Hira Nand Aryan:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any raid has been conducted by the C.M. Flying Squad in the office of the Sub-Divisional Agricultural Officer, Loharu in connection with the bugling in the insecticide "Phosphomidon" during the years 1988-89 and 1989-90; if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी औम प्रकाश चौटाला): कोई छापा नहीं मारा गया। परन्तु एक रिपोर्ट के आधार पर मुख्य मंत्री उडन दस्ते द्वारा जनवरी, 1988 में उप मण्डल कृषि अधिकारी लोहारु के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसी आधार पर सितम्बर, 1989 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई है, क्या उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? दूसरे, इस अधिकारी के खिलाफ पुलिस द्वारा या विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा एक डिमोस्ट्रेटिव प्लांट विशेष रूप से दवाई के लिए बनाया हुआ है। इस प्लांट में 57.5 लीटर दवाई होनी चाहिए थी लेकिन जब मुख्य मंत्री के उड़न दस्ते ने छापा मारा तो वहां 30 लीटर के करीब दवाई कम पाई गई। इस 30 लीटर दवाई की कीमत करीब 5 हजार रुपए बनती थी। इन्वैस्टीगेशन जारी है। इस अधिकारी के खिलाफ सितम्बर, 1989 में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवा दी गई थी। ज्यों ही अधिकारी कसूरवार साबित हो जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्टिवेशन लिया जाएगा।

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कीटनाशक दवाईयां किसानों को समय पर न मिलने की क्या कोई शिकायत इनके पास आई है, अगर आई है तो उस पर क्या ऐक्टिवेशन लिया गया है?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई शिकायत नोटिस में आती है तो उस पर पूरी कार्यवाही की जाती है और दवाई की कमी को पूरा करने की

कोई रिपोर्ट सरकार द्वारा की जाती है। कई दफा दवाई की प्रोडक्शन में कमी की वजह से भी ऐसी समस्या आ जाती हैं पीछे चावल की फसल के दौरान खास कर चावल वाली बैल्टमें दवाई की कमी पाई गई थी लेकिन सरकार ने किसी न किसी तरह से दवाई का प्रबन्ध करके इस दवाई को सही ढंग से तकसीम करवाया।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस दौरान दूसरी कीटनामक दवाइयों की कमी की कोई रिपोर्ट इनके पास आई है, अगर आई है तो उस पर क्या ऐक्शन लिया गया है?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: जब भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर पूरा ऐक्शन लिया जाता है। विशेष रूप से मैं आर्य जी के सवाल के उत्तर में बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के नोटिस में नहीं आई।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाबमें बताया है कि सितम्बर, 1989 में दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराए करीब 6 महीने हो गए हैं। क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि एफ0 आई0 आर0 ही दर्ज है या उस पर कोई कार्यवाही भी की गई है?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: मैंने पहले ही बताया है कि उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और अब आगे इन्वैस्टिगेशन जारी है। इन्वैस्टिगेशन पूरी होने पर अगर वह दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अभी मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि ऐसी कोई रिक्वायट सरकार के नोटिस में नहीं आई। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऐसी ही एक रिक्वायट मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख कर भेजी थी, उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री औम प्रकाश चौटाला: इस प्रकार की कोई रिक्वायट अगर आर्य साहब की तरफ से आई होगी तो उस पर जरूर गौर किया जायेगा और उसका पूरा विवरण इनको दिया जायेगा।

श्री योगेश चन्द भार्गव: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री ने अभी बताया है कि उस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बित करना तो विभागीय कार्यवाही है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो एफ0 आई0 आर0 लौज की गई थी उसके तहत इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और यह किस किस स्टेज पर है?

Mr. Speaker: It has been said that investigation is in progress.

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी खुद वकील है। मैंने अभी बताया है कि इस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है और इन्कवायरी हो रही है। ज्यों ही इन्कवायरी के बाद वह दोशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। निलम्बन के बाद दोशी पाए जाने पर अगली कार्यवाही गिरफ्तार करने की होती है।

Construction of building of Govt. High School, Khambi

***1068. Shri Udai Bhan:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of Government High School, Khambi; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be constructed?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) जी हां, मामला विचाराधीन है।

(ख) चार कमरों का निर्माण तुरन्त करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं तथा भोश कमरों के निर्माण का कार्य पर्याप्त धन राशि के उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जायेगा। अतः नये भवन

के निर्माण कार्य के पूर्ण होने बारे कोई निश्चित समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वोटों के लालच में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने जिस बिल्डिंग को गिरवा दिया था, हमारे मंत्री महोदय ने स्कूल की उस बिल्डिंग को बनवाने का आवासन दिया है और 4 कमरे बनवाने की मंजूरी दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि टोटल कितने कमरे बनवाने का निर्णय लिया गया है, बाकी के कमरों के लिए धन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी और ये कमरे कब तक बन जाएंगे?

श्री हुक्म सिंह: 4 कमरे इस बरसात से पहले ही बनवा दिए जाएंगे। टोटल कमरे 14 बनवाए जाएंगे। 2-3 और कमरे भी हम इसी साल बनवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बाकी कमरों का संबंध है, इनको भीघ्न बनवाने के लिए हम कोशिश करेंगे लेकिन इनके लिए समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या इन्होंने हरियाणा में कोई सर्वे करवाया है जिससे यह पता चले कि इन इन स्कूलों के लिए बिल्डिंग बनवाने की आवश्यकता है? पी0 डबल्यू0 डी0 द्वारा

कितने स्कूलों की बिल्डिंगों को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और जो ऐसी बिल्डिंगें हैं उनके कब तक बनाने की संभावना है?

श्री अध्यक्ष: बात एक स्कूल की चल रही है, सारी स्टेट के स्कूलों के बारे में जबानी बता सकना इनके लिए पौसिबल नहीं है। यदि आप किसी स्पैसिफिक स्कूल के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसका नाम बता दीजिए ये आपको बता देंगे। यह सवाल एक स्कूल के बारे में है सारे सूबे के बारे में सप्लीमेंटरी नहीं की जा सकती।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग के लिए कितने धन की आवकता होगी जो अतिरिक्त धन की भावना में दिया जाना है तथा इसके ऐस्टीमेट्स के मुताबिक 14-15 कमरे कब तक पूरे हो जाएंगे?

श्री हुक्मसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि 4 कमरे तो बरसात से पहले पहले बनवा दिए जाएंगे। एक कमरा बनाने पर लगभग 80 हजार रुपए का खर्च आता है।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 4 कमरे इकट्ठे बनवा कर देंगे। इस स्कूल के लिए पहले व्यवस्था क्या थी? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने इस स्कूल की बिल्डिंग को किस वजह से गिरवा

दिया था? क्या और स्कूलों में भी एक साथ इतने कमरे बनवाने की जरूरत है?

श्री हुक्मसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं और पी० डब्ल्यू० डी० ने उन्हें अनसेफ कर दिया है। बरसात या फ्लड की वजह से भी कई बिल्डिंगें गिर जाती हैं और उन्हें बनवाने की जरूरत पड़ती है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में गुन्दाना स्कूल की बिल्डिंग बच्चों के लिए बहुत कम है। बच्चे धूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

Mr. Speaker: This is not relevant.

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि कई बिल्डिंगें पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में कौन कौन सी बिल्डिंगें अनसेफ डिक्लेयर की गई हैं और वहाँ पर कितने कितने कमरे बनवाए जाएंगे?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, इस समय सारे हरियाणा की लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की यह बात ठीक है कि सारे स्कूलों के बारे में अलग अलग से सूचना

नहीं दी जा सकती। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुल मिला कर कितने स्कूलों की मरम्मत हो गई है, कितने स्कूलों की बाकी रहती है और उनके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, टोटल धन कितना चाहिए यह बताना संभव नहीं है क्योंकि हर साल बारिश और फ्लड से नुकसान होता है। फ्लड से भी बिल्डिंगें गिर जाती हैं और कुछ ऐडिशनल कमरे बनाने की भी मांग आती रहती है,, कुछ रिपेयर भी होनी होती है इसलिए यह बताना कि कितने धन की आवश्यकता होगी यह संभव नहीं है। उसका ऐस्टिमेट भी नहीं लगाया गया है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि कुछ कारणों से पी० डब्ल्यू० डी० स्कूलों की बिल्डिंगों को अनसेफ डिक्लेयर कर देती है और कुछ बिल्डिंगों फ्लड की वजह से गिर जाती हैं लेकिन जो यमुना के साथ साथ फरीदाबाद और करनाल जिले का एरिया है यानी जो यू० पी० के बोर्डर के साथ लगता है उस एरिया में बुरी तरह से फ्लड आते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई कम्प्लेंट आयी है कि बिल्डिंगों की तबाही हो गई है, अगर आयी है तो क्या जिस प्रकार से इस गांव के लिए कर रहे हैं, उन गांवों के लिए भी कर रहे हैं?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, जहां भी कोई नयी बिल्डिंग बनानी हो या रिपेयर प्रायरिटी बेसिज पर होनी है, उसके लिए बहन सुशमा स्वराज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई थी, उसमें माननीय काबिल साथी श्री रणजीत सिंह जी और धीरपाल सिंह जी मैम्बरज थे। उस कमेटी ने प्रायरिटी फिक्स की कि कौन से स्कूल का भवन बनना या रिपेयर होना जरूरी था। कमेटी की रिपोर्ट पर ही काम हुआ।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह नहीं था कि कौन सी रिपेयर होनी है, कौन सी नहीं होनी है। मेरा सवाल यह था कि उस एरिया में फलड आने के बाद कितने स्कूलों की बिल्डिंगें गिरी हैं, जिनकी रिपेयर का काम सरकार के पास है यानि टोटल स्कूलों की बिल्डिंगों की रिपेयर के लिए सरकार क्या कदम लेने जा रही है?

श्री हुक्म सिंह: फलड या बारि 1 की वजह से 34 हाई-स्कूलों, चार मिडल स्कूलों और 14 प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें गिरी हैं जिनकी रिपेयर होने की आवश्यकता है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल उनकी दृष्टि में कितने हैं जिनके बारे में तीन तीन साल से विभाग ने यह मान्यता दे दी है कि यह बिल्डिंग बननी चाहिए? मेरे हलके में भीमखेड़ी गांव है जिसके स्कूल की बिल्डिंग के लिए एक साल से ईंटे आयी

हुई है लेकिन पी० डबल्यू० डी० वालो ने चिनाई भुरु नही की है। इसलिए मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर काम कब भुरु करने जा रहे है?

Mr. Speaker: Singla Sahib, it is not possible to reply to this question off hand.

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, जिन 34 स्कूलो की बिल्डिंगो गिरने या हालत खराब होने की बात कही गई है, क्या उनकी रिपेयर के लिए सरकार ने धन का प्रावधान करने की सिफारि की है?

श्री हुकम सिंह: जी हां, की गयी है।

तारांकित प्र न संख्या 1101

यह प्र न पूछा नही गया, क्योंकि माननीय सदस्य, श्री मनीराम, इस समय सदन में उपस्थित नही थे।

Pension to employees of Local Bodies

***1057. Comrade Harpal Singh:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the services of the employees working in the Municipal Committees in the State as pensionable service;

(b) if so, the time by which such a proposal is likely to materialize; and

(c) the total number of employees working on ad-hoc basis in the Municipal Committees in the State at present together-with the period since when they are working?

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल):

(क) नहीं।

(ख) 'क' को मुख्य रखते हुए उतर भून्य।

(ग) इस समय भिन्न भिन्न नगरपालिकाओ में जिन की सेवाएं एक वर्ष से अधिक हो चुकी है, 124 कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि विभिन्न नगरपालिकाओ में 124 कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे है। क्या मंत्री महोदय इनके नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: नामों की लिस्ट तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन यह बता देता हूं कि कौन सी नगरपालिका में कितने कितने काम कर रहे है। करनाल में एक, लाडवा में दो, जगाधरी में सात, हांसी में दो, गन्नौर में तीन, सम्भालखा मे तेरह, नीलोखेडी में तीन, इन्दरी में तीन, चीका में एक, यमुनानगर में पांच, सफीदो में एक, नूह में दो, फारुखनगरमें एक, दादरी में एक, डबवाली में एक काम कर रहे है। इस तरह से

और भी काफी लम्बी लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो वह भी पढ कर सुना देता हूँ।

आवाजें: रहने दीजिए।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, जगाधरी में इन्होंने ऐडहॉक पर काम कर रहे कर्मचारियों का नम्बर केवल 7 बताया है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आदमियों की जगह पर रैगुलर आदमी का कोई विचार है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, ये जो कर्मचारी हैं, इनकी सेवा एक-एक साल से फालतू है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एक एस० एल० पी० दायर है। उसका जब फैसला हो जाएगा तब इनकी सेवा भी नियमित करने के बारे में सोचा जाएगा।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने केवल 124 कर्मचारी ही ऐडहॉक पर म्यूनिसिपल कमिटीज में लगे हुए बताए हैं। मगर हजारों स्पीपर्ज ऐसे हैं जो ऐडहॉक पर नहीं बल्कि पार्ट टाइम एन्गोज किए हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनको रैगुलर करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: इनकी यह बात ठीक है कि क्लास फोर कर्मचारी भी डेली-वेजिज पर नगरपालिकों में लगे हुए हैं। उनके बारे में भी फैसला तभी हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाएगा।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को पेंशन देने का कोई विचार नहीं है। बुढ़ापा पेंशन देने वाली यह सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन देने से इंकार करे, यह बात उनकी बुढ़ापा पेंशन देने की बात से मेल नहीं खाती। क्या वे उनको भी पेंशन देने पर विचार करेंगे?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: सर बुढ़ापा पेंशन में और इसमें बड़ा फर्क है। नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए कन्ट्रीब्यूटरी प्रोवीडेंट फण्ड का प्रावधान है। उसमें नगरपालिका की ओर से कर्मचारियों की बेसिक पे का 8 प्रतिशत पैसा दिया जाता है।

श्री किरपा राम पुनिया: अभी मंत्री महोदय ने यह बताया है कि ऐडहाक ऐम्पलाईज को रैगुलर करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसेजिन का इंतजार हो रहा है। मगर जो ऐम्पलाईज नगरपालिकाओं में ऐडहाक पर नहीं लगे हुए हैं बल्कि उनको पार्ट-टाइम एन्गोज किया हुआ है, उनको रैगुलर क्यों नहीं किया जाता, वे समाज के कमजोर तबके के आदमी हैं। उनका रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार से मिल चुका है। कम से कम सरकार उनको तुरन्त रैगुलर करने के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करती?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: सुप्रीम कोर्ट में जो केसिज है, उनमें डेली-बेसिज ऐडहाक और सब तरह के कर्मचारियों की

बात है। उसका फैसला होने के बाद ही इनका भी फैसला किया जाएगा।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यमुना नगर में केवल 5 आदमी ही तदर्थ आधार पर लगे हुए बताए हैं, मगर संख्या तदर्थ आधार की अधिक है। जग सरकार का यह नियम है कि 240 दिन के बाद उनको पक्का कर दिया जाएगा तो वह क्यों नहीं उनको पक्का करती? इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्यों आवयकता पडी? क्या कारण है कि वे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: यमुना नगर में 5 कर्मचारी नहीं बल्कि क्लास फोर के 219 आदमी है। इसमें चूंकि पैसे की इन्वोलमेंट बहुत ज्यादा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो 124 ऐडहाक कर्मचारी है, ये किस किस कैटेगरी के है और कितन कितने साल से काम कर रहे है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, भाहबाद में एक जे0 ई0, करनाल में एक क्लर्क.....

श्री अध्यक्ष: एक एक भाहर का गिनकर बताने की आवयकता नहीं है आप सारे इकटठे ही बता दो।

श्री सुभाश चन्द कटियाल: बहुत अच्छा जी। मेरे पास सारी कैटेगरीज की लिस्ट है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के आदमी इस प्रकार से है।:- सैकेट्रीज 4, जे0 ई0 13, सैनेटरी इंस्पैक्टर्ज 2, स्टैनो टाईपिस्ट 3, क्लर्कस 56, पटवारी 1, ड्राईवर्ज 10 और फायरमैन 12 आदि आदि। यह सब एक साल से फालतू समय से लगे हुए है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय,

10:00 बजे

श्री अध्यक्ष: आप कृप्या बैठिए क्योंकि आपने पहले ही तीन क्वै चन कर लिए है।

श्रीमती सुशामा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जो सफाई कर्मचारी है उनको पैनान देने और उनको नियमित करने की बात तो सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओ के जो सफाई कर्मचारी है उनको बोनस देने की बात सरकार के विचाराधीन है क्योंकि वे कर्मचारी बोनस की माग कर रहे है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, इस बारे में उनके नियमित होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, बोनस का नियमित होने से कोई संबंध नहीं है। बोनस तो डेली बेसिज कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने नगरपालिकाओं में जिन कर्मचारियों की सेवाएं एक साल से ज्यादा हो चुकी हैं उनकी तादाद तो बता दी है लेकिन जिन कर्मचारियों की सेवाएं एक साल से कम हैं उनकी तादाद नहीं बताई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि म्यूनिसिपल कमेटीज में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार किया जाएगा और झाड़ू जैसी चीजें और दूसरी चीजे जो रोजाना इस्तेमाल में आती हैं, उन को प्रोवाइड करने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधी है? स्पीकर साहब, झाड़ू जैसी चीजें भी उनको अपने घर से लानी पडती है।

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, अगर कोई डिमांड आएगी तो विचार कर लिया जाएगा। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is no reply.

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये इवेसिव जवाब दे रहे हैं। जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात तो सुनते नहीं हैं। मैंने कहा है कि thi is no reply.

कमारेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मयूनिसिपल कमेटीज के अंदर ऐडहाक बेसिज पर हजारो कर्मचारी काम कर रहे है लेकिन ये 124 ही बता रहे है। ये गलत जवाब दे रहे है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाश चन्द कटियाल: आप सुनने की कोशिश करिए। मैं सब कुछ बताउंगा।

डा० मंगल सेन: अध्यक्ष महोदय, स्थानीय भासन मंत्री जी ने बताया है कि कर्मचारियों के नियमित होने के बाद ही बोनस देने के बारे में विचार किया जाएगा। क्या मंत्री महोदय फाईल देखकर बताएंगे कि जो आलरेडी कंफर्मड है या रैगुलर ऐम्पलायज है उनको बोनस देने की बात पहले ही, जब चौधरी देवीलाल जी मुख्य मंत्री थे, स्वीकार कर ली थी? क्या यह बात सही है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: डा० साहब दुबारा सवाल पूछिए।

(इस समय उप-मुख्य मंत्री महोदय जवाब देने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: Please put the question again and Gupta Ji will reply. The minister concerned has not done home work today. I am very sorry to say that he is not prepared.

डा० मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय, फाईल देखकर बताएंगे या सारी बात पता करके बताएंगे कि क्या कुछ म्यूनिसिपल कमेटीज ने ऐम्पलाइज को आलरेडी बोनस दे दिया है?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्यूनिसिपल कमेटीज के कर्मचारियों को बोनस देने का प्र न है यह सरकार नहीं देती। सरकार के कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसा नहीं जाता। नगरपालिकाएं अपने फण्ड से देती हैं। मुझे सही संख्या का तो पता नहीं लेकिन हरियाणा की कुछेक नगरपालिकाओं ने, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अपने कर्मचारियों को बोनस दे भी दिया है। सरकार की तरफ से हर नगरपालिका को यह कहा गया है कि जहां तक संभव हो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को बोनस सरकार के पैटर्न पर दिया जाए।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय डा० मंगल सैन जी का स्पैसिफिक प्र न था कि चौधरी देवी लाल जी जब मुख्य मंत्री थे उस वक्त स्थाई कर्मचारियों के थ्रू ऐक्सचैकर बोनस देने का फैसला किया गया था। क्या उप मुख्य मंत्री महोदय उस बारे में कोई स्पैसिफिक जवाब देंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, ऐसा तो कोई निर्णय उस वक्त नहीं हुआ था।

श्री रणसिंह मान: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जो 124 कर्मचारी ऐडहाक पर बताए हैं उनका मोड आफ रिकूटमेंट क्या है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, ये पिछले दो तीन साल से लगे हुए हैं।

Dr. Mangal Sein: Speaker Sir, it is a very serious matter. You have just now observed that the Hon'ble Minister has not come prepared. If it is your observation then some follow up action must be taken against him.

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please put your question now.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, साहब अभी उप मुख्य मंत्री महोदय जी ने फरमाया कि सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जाता है। यह उनकी बात ठीक तो है लेकिन गुप्ता जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार की अनुमति के बिना कमेटियां पैसा दे भी नहीं सकती।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डा० साहब, अनुमति दी हुई है।
डा० मंगल सैन: ठीक बात है गुप्ता जी, लेकिन आप साफ कहें, भाब्दो में कंजूसी मत कीजिए। इससे सरकार की व्यवस्था बिगडती है। हम ने कर्मचारियों को यह वचल दिया था कि आपको बोनस दिया जाएगा और फाईल पर इस तरह के आर्डर भी है कि जो कमेटियां बोनस दे सकती हैं, उनको अव य देना चाहिए। मेरी

जानकारी के अनुसार एक दर्जन कमेटियां अपने कर्मचारियों को बोनस दे भी चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्या वे बताएंगे कि जिन कर्मचारियों को बोनस अभी बकाया है उनको जल्दी ही दे दिया जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जिन कमेटियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी उन्होंने तो अपने कर्मचारियों को बोनस दे दिया है। सरकार ने भोश म्यूनिसिपल कमेटियों को यह आदेश दिया है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को बोनस दें।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटीज में सफाई कर्मचारियों को जो आज समाज के सब से पिछड़े हुए लोग हैं, प्रायरीटी देकर के दूसरे ऐडहाक ऐम्पलाईज से पहले रैगुलर किया जाएगा?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: इस पर विचार कर लिया जाएगा।

Distribution/Pasting of posters against particular community

***1027. Shri Surinder Kumar Madan:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) whether any cases of distribution/pasting of posters against particular community in the State have come to the notice of Govt. durin the month of January, 1990; and

(b) if so, the names of the persons who have been found involved in the said incident togetherwith the action, if any, taken against them?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) निम्नलिखित दो व्यक्ति इन घटनाओ में संलिप्त थे:—

(1) योधा प्रताप सिंह चौधरी, प्रधान वि ाल हरियाणा महा सभा, निवासी गांव हेवतपूर थाना नारनोंद जिला हिसार।

(2) राजेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह जाट निवासी गांव दाता, थाना सदर हांसी (जगलान प्रिटिंग प्रैस, हिसार के मालिक)।

इस संबंध में एक मुकदमा नं० 63 दिनांक 25-1-90 धाराधीन 153ए भा० द० स० थाना भाहर हिसार में दर्ज किया गया था। राजेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंज जाट को दिनांक 27-1-90 के जमानत पर रिहा कर दिया गया था। योधा प्रताप सिंह चौधरी अभी फरार है। मुकदमा अनुसंधानाधीन है।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा के अंदर जो पोस्टर्ज वगैरह बांटे गए उस बारे में गृह मंत्री महोदय ने एक

प्रैस स्टेटमेंट दिया था कि यह किसी बड़े कांग्रेसी का हाथ है जो कि इस सूबे के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय अगर इनके नोटिस में यह बात थी तो क्या इन्होंने उस कांग्रेसी के खिलाफ कोई ऐक्टान लिया?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमें भाक जाता है कि वह भी किसी आधार पर गया था। जहां तक उनके खिलाफ ऐक्टान लेने का सवाल है इस केस से संबंधित एक योधा प्रताप सिंह नाम का आदमी है जो कि अभी तक फरार हैं। जब वह पकडा जाएगा और इंटैरोगेट होगा तभी जाकर किसी के खिलाफ ऐक्टान लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, यह मसला बडा ही सीरियस है। जो आदमी इस में दोशी थे, उनको नै नल सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत पकडा जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने उनको धारा 153-ए के तहत पकडा और अगले ही दिन उनकी जमानत भी हो गई। क्या सरकार उनके खिलाफ नै नल सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है? मेरे विचार से सरकार इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो आदमी गिरफ्तार किया गया, उसका प्रिटिंग प्रैस था। योधा प्रताप सिंह नाम का आदमी अभी तक फरार है, जब वह पकडा जाएगा तो अब य ही कार्यवाही की जाएगी। जहां तक मदान साहब ने कहाकि सरकार

इसको सीरियसली नहीं ले रही है, ऐसी बात नहीं है। इस मामले को सीरियसली लिया जा रहा है। एक दो जगहों पर पोस्टर्स बांटे गए थे, सभी जगहों पर ऐसा नहीं करने दिया गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, 25-1-90 को मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि कैथल के सिविल कोर्ट्स के अन्दर ऐसे पर्चे बांटे गए। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई और किसी को अरैस्ट किया गया या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अचम्भा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 25 तारीख को पत्र लिखा। भुरु में ऐसे पर्चे आदमपुर में बांटे थे उसके बाद 27 तारीख को ये कैथल में बांटे गए। तो जब पर्चे कैथल में 27 तारीख को बांटे तो इन्होंने 25 तारीख को पत्र कैसे लिख दिया?

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या गृह मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि इस पोस्टर में छपी हुई बातों का हुबहू रि-प्रोड्यूस करके कुछ कांग्रेस के लोगो ने जनता में बांटा ताकि लोगो में सरकार के प्रति बेचैनी और घृण का भाव पैदा हो। अगर इनके नोटिस में ऐसी बात है तो उस पर क्या ऐक्शन लिया गया?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब योधा प्रताप सिंह पकड़ा जाएगा तो जितनी बिल्लियां थैले के अन्दर बन्द हैं वे सब

बाहर जा जाएंगी। जिन्होंने साजि 1 की है उनको पब्लिक के सामने नंगा किया जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस के उपर छिंटाक की गई है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने भाक अखबारों में जाहिर किया था क्या वह उसी तरीके से तो नहीं किया था जैसे दरियापुर आतंकवाद के कांड के बारे में किया था? वह कांड इन्होंने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कांग्रेस के उपर थोपा था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि योधा प्रताप सिंह अभी फरार है। क्या ये बताएंगे कि उसको जानबूझ कर तो नहीं पकड रहे हैं और ढील दे रहे हैं जिससे सस्पेंस बना रहे, जिससे कांग्रेस को बदनाम करते रहें?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कहीं दरियापुर कांड की तरह कांग्रेस के उपर तो यह बात नहीं थोप रहे हैं। इस बात का आधार कुछ है। स्पीकर साहब, हाउस के सभी सदस्यों को ध्यान होगा कि लोगों की भावना भडकाने के लिए सम्मेलन भी किए गए थे। वे सम्मेलन कांग्रेस पार्टी ने किए थे और भजन लाल ने वे सम्मेलन बुलाए थे। वह जहां भी जाता है बहुरूपिया बन जाता है। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि वह जहां भी जाता है वहां वैसी ही बात करता है। जब जाटों के इलाके में जाता है तो कहता है कि मैं जाट हूँ मेरा आपसे गोत्र मिलता है। दूसरी कम्यूनिटी में जाता है तो कहता है कि मैं बहाबलपूर, पाकिस्तान से आया हूँ। बनियो में

जाता है तो कहता है कि मैं बनिया हूँ। हरियाणा और राजस्थान बोर्डर पर एक चौकी है उसके जहरए वह व्यापार किया करता था। खुद जाकर तो वह इस तरह की भावना भडकाता है। वह इस तरह का आदमी है इसलिए हमें भाक है। दरियापुर कांड का सारा रिकाड मोजूद है। हमने वह केस ऐंटी टैरोरिस्ट ऐक्टीविटी के तहत दर्ज नहीं करवाया था बल्कि सिम्पल केस दर्ज करवाया गि जोकि आगजनी का था। लेकिन स्पै गल कोर्ट भिवानी ने बकायदा आर्डर दिया कि इस पर ऐंटी टैरोरिस्ट ऐक्टीविटी का केस बनाएं। ये कोर्ट के आर्डर है तो इससे बडा सबूत और क्या हो सकता है?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, * * * * *
* * (गोर)

Mr. Speaker: Mr. Mahender Partap Ji, this is no way. This is not to be recorded. (interruption) This creates difficulty. You should know that clarification cannot be obtained during questions hour. मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप रुल्ज प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस की किताब पढा करें। यदि मैं आपको कुछ कहता हूँ तो आप गुस्सा करते हैं। (गोर एवं व्यवधान) please take your seat and let Dr. Mangal Sein have his say.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, आदरणीय सम्पत सिंह जी ने बडी डिटेल में बातें बताई है। हाउस में कुछ आदरणीय बहने बैठी हुई है, मुझे कहना नहीं चाहिए। भाई सम्पत सिंह जी

जिस भाख्स का भुभ नाम ले रह है वह तो हर महफिल में अपनी बात कहा करता है, हरिजनो में जाएगा तो अपनी बात कहेगा, वैस्ट पंजाब के लोगो में जाएगा तो अपनी बात कहेगा और महिलाओ में जा कर कहेगा मेरा डाक्टरी मुआयना करवा लो मै क्या हू। (हंसी) मै उस चक्कर में नही पडना चाहता। मै तो यह जानना चाहूंगा कि जो आधार है पर्चे बांटने वालो का क्या उसका पता किया गया है? क्या उनके बारे मै कोई जानकारी इकट्ठी की गई है? योधा प्रताप सिंह के मिलने पर तो सारी बातें सामने आ जाएंगी लेकिन उससे पहले क्या आपने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है? आपने कहा कि पर्चे बांटने से उन्हे रोक दिया गया। रोकना तो सरकार का काम है लेकिन बांटने वाले को पकडना भी सरकार का काम है। मै यह जानना चाहता हू कि पर्चे बांटने वालो को अपने गिरफ्तार किया या नही?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब योधा प्रताप सिंह पकडा जाएगा तभी यह जानना संभव हो पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग भागिल थे। इसके अलावा एक बात मै यह भी बताना चाहूंगा कि 1982 और 1987 में दो बार हांसी में चुनाव हुए थे उनके अन्दर वहां के हमारे आदरणीय साथी श्री अमीर चन्द मक्कड एक बार चुनाव जीत गए और दूसरी बार हार गए थे। दोनो चुनावो में यह आदमी बकायदा हर वक्त उनके साथ बौडी गार्ड के रुप में रहता था।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की भांति भंग करने के लिए और एक समुदाय में घृणा फैलाने के लिए वह पोस्टर छापे गए थे। गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि दो तीन जगहों पर ही वह पोस्टर बांटे गए थे। आखिर हरियाणा की पुलिस और सी० आई० डी० बड़े सक्रीय रूप से और कुशलता से काम करती है। पहले एक जगह बांटे फिर दूसरी जगह बांटे फिर तीसरी जगह बांटे। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या उन पुलिस अधिकारियों और सी० आई० डी० पर इस बारे में कोई जिम्मेवारी डाली गई और अगर डाली गई तो क्या ऐकान लिया गया?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह मामला विद इन टू और थ्री डेज में ही हो गया था। उसके बाद बकायदा रोक दिया गया था। यह केस भी इनवैस्टीगेशन के लिए पुलिस से ले कर सी० आई० डी० काइम ब्रांच को दे दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया है कि केवल दो तीन दिनों नहीं पर्चे बांटे थे। मंत्री जी के ध्यान में यह बात होगी कि कुरुक्षेत्र जिले में उप चुनाव के दौरान भी वह पर्चे बांटे गए थे। क्या ये बताएंगे कि उसके बारे में इन्होंने क्या कार्यवाही की है? मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि वह पोस्टर हिसार की एक प्रैस में भी छपे थे, बहादुरगढ़ की एक प्रैस में भी छपे थे और उत्तर प्रदेश के एक जिले की प्रैस में भी छपे थे। तो क्या उन प्रैस वालों को गिरफ्तार किया गया या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, भुरु में बहादुरगढ की एक प्रैस में छपे थे उनमें ऐसी भाशा नही थी। उसके बाद हिसार में जो पोस्टर छपे थे उनमें ऐसी भाशा थी। मदान साहब ने कहा है कि कुरुक्षेत्र जिले में उप चुनाव के दौरान भी वह पोस्टर बंटे थे। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में उप चुनाव के दौरान वह पोस्टर नहीं बंटे थे। कैथल में जो पोस्टर बंटे थे उनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। कैथल कोर्ट में 27 तारीख को बंटे थे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 26 तारीख को बंटे थे। मैं हाउस को अ योर करता हूं कि जिस कम्यूनिटी के खिलाफ वह पोस्टर छापे गए हैं उस कम्यूनिटीका हरियाणा की तरक्की में विशेष योगदान रहा है। चाहे हरियाणा की संस्कृति है, चाहे हरियाणा की समृद्धि है और चाहे हरियाणा की सभ्यता है, उस कम्यूनिटी ने हर क्षेत्र में बढ चढकर हिस्सा लिया है। आज हरियाणा की जो भाक्ल है उसके बनाने में उस कम्यूनिटी का बहुत बडा योगदान रहा है। हरियाणा सरकार उस कम्यूनिटी की बहुत इज्जत करती है। किसी जाति विशेष के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर यानी जाति और धर्म के बवे पर यदि कोई भी राजनैतिक आदमी रोटियां सेंकने की कोशिश करेगा तो उसको इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह मामला बडा संगीन था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने और बाकी सब लोगो ने इसको बडा सीरियसली लिया। यह जो योधा

प्रताप सिंह है और इसके जो साथी हैं उन्होंने लगभग सारे हरियाणा के अंदर वह पोस्टर बांटे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि योधा प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्री जी ने किसी खास आफिसर की ड्यूटी लगाई? क्या उसको चेंज किया गया और उसको कहीं पर देखा गया? यह बड़ा अहम मसला है। एक विशेष भाईचारे के खिलाफ यह एक नफरत फैलाने का मसला है। पंजाब में भी इसी तरह से गडबड भुरु हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि योधा प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है और कितने दिन में वह गिरफ्तार हो जाएगा?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये पोस्टर सारे हरियाणा में नहीं बांटे गए बल्कि दो-तीन जगह पर ही बांटे गए थे। मैंने पहले ही कहा है कि यह केस अंडर इन्वेस्टीगेशन है और इस केस को सी० आई० डी० कार्डम ब्रांच को जांच के लिए दिया हुआ है। दोषी की मुवमेंट का पता चला है लेकिन उसका बताया जाना पब्लिक इंटरैस्ट में नहीं है। मैं यह अयोर करता हूँ कि उस व्यक्ति को बकायदा पकडा जाएगा और उसके खिलाफ अवय कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को प्रदेस का माहौल बिगाडने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ यह है कि क्या उस व्यक्ति को पकडने के लिए सरकार की तरफ से छापे

मारे गए और मारे गये तो कौन कौनसी जगहो पर छापे मारे गए? क्या उसका कोई पता चला कि वह व्यक्ति कहां पर रहता है? कृप्या यह ब्यौरा सदन को दें।

प्रो० सम्पत सिंह: मैं बताया है कि छापे मारे गए है और उसकी मूवमेंट का पता चला है। अब कहां कहां पर छापे मारे गए वह बताना पब्लिक इन्ट्रस्ट में नहीं है। अगर इस बारे में बता दिया गया तो वह व्यक्ति फिर कहीं और सरक जाएगा। पुलिस ने राजस्थान, यु० पी० और हरियाणा में अर्थात् तीनों स्टेटस में छापे मारे है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जातीय सम्मेलन जनता दल की सरकार और कांग्रेस दल की सरकारो द्वारा करवाए गए है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जातीय सम्मेलन भविश्य में किसी भी पार्टी की तरफ से और्गेनाइज न किए जाएं क्या इस पर कोई कानूनी पाबंदी लगाने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा मेरा सवाल यह है कि इन पोस्टरो में भजन लाल जी का नाम साफ लिखा है जिससे लगता है कि यह उनकी साजि । है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी?

प्रो० सम्पत सिंह: यह तो भांका जाहिर की गई है। अगर वह दोशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी बकायदा पूरी

कार्यवाही की जाएगी। जहां तक जातीय सम्मेलन पर पाबंदी लगाने की बात है, यह कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।

Water table of Babain Area

***1037. Sh. Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the water table of Babain area has come down; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to raise the water table of the aforesaid area?

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री सचदेव त्यागी):

(क) हां।

(ख) पानी की सतह को बढ़ाने के उपायों के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण का प्रस्ताव है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों के अन्दर पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हमारे यहां पर दादूपुर-नलवी नहर पर काम होना था लेकिन वह अभी तक भुरु नहीं हुआ है। पिछले दिनों सी० एम० साहब उस एरिया में कई गावों में गए थे और जन सभाएं भी की थीं। उन सभी जन सभाओं में मुख्य मंत्री जी के सामने दादूपुर-नलवी नहर को बनाने की बात लोगों ने की थी। उस समय मुख्य मंत्री जी ने आ वासन

दिया था कि इस पर काम भुरु किया जाएगा। मै पुछना चाहता हूं कि इस पर कब तक काम भुरु हो जाएगा क्योंकि वहां पर पानी का लैवल बहुत नीचे जा चुका है?

Mr. Speaker: Kataria Ji, you please first see the question. This is not the way. You are an Advocate. You want a different reply which can not be given off hand.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मै दूसरे तरीके से सवाल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठें।

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बिजली तथा सिंचाई राज्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस समय सारे हरियाणा प्रदेा में भूमि जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विशय है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस संबंध में यानी जल स्तर को उपर उठाने के लिए क्या कारगर कदम उठाए है या उठाने जा रही है?

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, इन्होने यह सही बात कही है कि इस समय हमारे यहां पर जल स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां पर पानी का निकास ज्यादा है। वैसे भी हरियाणा में मीठा पानी सिर्फ 40 परसेंट है और यह बहुत सीमित एरिया में है। ऐसी जगह पर पानी

का लैवल बहुत नीचे जा चुका है। दूसरी तरफ जो 60 प्रति 100 पानी है उसका लैवल ऊपर जा रहा है। (विघ्न) स्पीकर साहब, 35 ब्लॉकस ऐसे हैं जो डार्क कैटेगरी में आते हैं जहां पानी सतह तक पहुंच चुका है कि नावार्ड और दूसरे लोन देने वाले इन्स्टीच्यू इन लोन पर बैन लगा दिया है। वहां लोन पर सबसिडी भी देते थे। अब हमें पानी का लैवल उंचा उठाने के लिए रैगुलेटरी मैयर्ज लेने पड़े हैं। (विघ्न) एक तो हमने रैगुलेटरी मैजर्स अपनाये हैं और दूसरे हमने बिजली के महकमे से सर्वेक्षण करवाया और कहा है कि बिजली के कनेक्ट्स पूरी तरह से देख कर, अच्छी तरह से जांच करके जहां लो वाटर है, वहां पर ही दिए जाएं। स्पीकर साहब, जब हरियाणा ऐगजिस्ट्रेंट्स में आया था.....(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: सवाल यह है कि जो पानी नीचे जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने क्या क्या ऐक्ट्स लिए हैं, लैण्ड को चार्ज करने के लिए क्या क्या कोर्डीनेशन की है? This is the simple question.

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसके लिए दो ही रास्ते हैं। एक तो जो पानी खर्च होता है, जो पानी की निकासी है, उसको कम करे और दूसरे यह की जमीन बरसात से रिचार्ज हो जो हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए कुछ रैमिडियल मैजर्स हैं जैसे नहरों के पानी से या सीपेज से पानी का लैवल बढ़ाया जाए। जब नहरों में पानी ज्यादा हो तो

पम्प सैटो से बाहर निकाल कर जमीन पर बहाया जाए। यह सीपेज का तरीका बनाया है।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वाटर का लैवल नीचे जाने का कारण यूक्लिपटस की पैदावार तो नहीं है?

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जमीन की सिंचाई की जो वर्तमान व्यवस्था है वह 45 प्रति 100 अण्डर ग्राउण्ड वाटर पर निर्भर करती है। कृषि में नई-नई टेक्नोलोजी आई है इससे कृषि की सिंचाई पर पानी का खर्च ज्यादा आता है। सफेदा जो लगाते हैं उसमें भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है यह भी एक कारण है। इस के साथ ही हम यह ऐगजामिन कर रहे हैं कि किसानों को शिक्षित किया जाए कि वे ऐसी फसलें पैदा करें जिनमें कम पानी खर्च होता हो।

श्री रतन सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, मेरे एरिया में वाटर लैवल को रिचार्ज करने के लिए दादूपुर-नलवी स्कीम बनाई गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस नहर को बनाने की योजना इस वर्ष सरकार के विचाराधीन है?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, यह पानी की अवेलिबिलिटी पर निर्भर करता है। एस० वाई० एल० का अभी तक फैसला नहीं हुआ कि हमें कितना पानी मिलेगा। अभी यह फैसला

भी नहीं हुआ कि जो पानी मिलेगा उसका स्टेट में डिस्ट्रिब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। इसी तरह से यमुना के पानी का मामला इण्टर-स्टेट मामला है और यू0 पी0 से भी पानी के बंटवारे के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जब तक यह तय नहीं हो जाता कि हरियाणा स्टेट को कितना पानी मिलना है तब तक इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। (विधुन्)

श्री अध्यक्ष: इन्हे तो इतना भी नहीं बताना चाहिए था because the supplementary does not relate to this question.

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर सर, अभी मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में बताया है कि किसानों को शिक्षित करेंगे कि ऐसी फसलें उगाएं जिनमें पानी कम खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि नई साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी से जो खेती हो रही है उसमें ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हर फसल को 6-6 या 7-7 पानी लग रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पानी के लेवल को ऊपर लाने के लिए सरकार क्या बंदोबस्त कर रही है? सरकार के क्या साधन या मीडिया है और क्या हरियाणा सरकार इसके लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से भी मदद ले रही है?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Buses allotted to each depot in the State

***1052. Shri Sita RamSingla:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the number of buses allotted to each depot, separately, during the last year?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह): वर्ष 1988-89 में डिपो वाईज निम्न प्रकार से बसे अलौट की गई:-

क्रम संख्या	डिपो का नाम	वर्ष 19'88-89 में जो बसे अलौट की गई
1	2	3
	टाटा	
1	सोनीपत	52
2	यमुनानगर	42
3	चण्डीगढ़	48
4	करनाल	47
5	जीन्द	37
6	कैथल	27
7	अम्बाला	38

लेलैण्ड		
8	गुडगांव	26
9	फरीदाबाद	20
10	भिवानी	39
11	दिल्ली	18
12	हिसार	26
13	सिरसा	35
14	रेवाडी	30
15	रोहतक	36
16	फतेहाबाद	11
	कुल जोड	532

Botanica Garden

***1079 Seth Lachman Dass Bajaj:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to setup a Bonatical Garden at Karnal; and

(b) if so, the time by which aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य मंत्री (चौधरी औम प्रकाश चौटाला):

(क) नहीं

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Water Supply scheme for Rewari

***1087. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for P.W.D.(Public Health) be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government for supplying drinking water through canals in Rewari town; and

(b) if so, the time by which the scheme, as referred to in part(a) above, is likely to be finalized?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री महा सिंह):

(क) जी हां।

(ख) इस स्कीम के लिए 347.00 लाख रुपए की प्रासकीय स्वीकृती हरियाणा राज्य सफाई बोर्ड ने अपने प्रस्ताव क्रमांक 30 दिनांक 8.8.89 द्वारा प्रदान कर दी है।

Selling of Panchayat Land

***1085 Shri Yogesh Chand Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether any land of Panchayats in the State has been sold by the Government during the period from 1st June,

1987 to-date, if so, the village-wise and year wise details thereof; and

(b) the names of the person to whom the land as referred to in part (a) above has been sold?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) सरकार द्वारा पंचायत की कोई भूमि 1 जून, 1987 से अब तक की अवधि में नहीं बेची गई है तथा

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Plying of buses by other States in Haryana Territory

***1076. Shri Parma Nand:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether any private transport companies registered in neighbouring State ply their buses in the territories of Haryana State; if so, the names and routes of said companies;

(b) the total number of kilometers permitted to be covered by such buses within the territory of Haryana during the years 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89 and 1989-90; and

(c) the total amount of passengers tax paid by each of the aforesaid bus operators during the period as referred to in part (b) above, year wise, separately?

Interim reply

अ0स0 पत्र कमांक 25 MR-90

राज्य मंत्री,

परिवहन विभाग हरियाणा,

चण्डीगढ ।

दिनांक : मार्च 13, 1990

**Sub:- Reply to starred Assembly Question No.
1076 by Shri Parma Nand, M.L.A.**

Respected Chatha Sahib,

The reply to the Starred Assembly Question No. 1076 from Shri Parma Nand M.L.A is due on the 15th March, 1990. The reply to the question involves obtaining information of Private Transport Companies registered in the neighbouring States for 4 years starting from the year 1985. The State of Haryana has interstate Transprt Agreement with the neighbouring States of Punjab, Rajasthan, Himachal, U.P., Dehi and Madhya Pradesh. In most of the State passenger Transprt is not fully nationalized. For answering part (c) of the question, informationhas to be collected from the Excise and Taxation Department, It will take sometime to collect the required information. I would, therefore, request you to kindly grant an extension of 3 weeks for furnishing the reply to this question.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(DHARAMBIR)

Shri H.S. Chatha,

Hon'ble Speaker

Vidhan Sabha, Haryana

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैन्डान्स मोडन आपकी सेवा में दी थी कि हरियाणा में प्रौढ शिक्षा बन्द कर दी गई है जिसके कारण हजारों लोग बेकार हो गये हैं। वे 15-15 साल से लगे हुए थे। वे दो सौ और तीन सौ रुपये महीने पर काम कर रहे थे। 15 साल के बाद एकदमसे यह योजना बन्द कर दी गई है। लगभग चार हजार नौजवान बेकार हो गये हैं।

Mr. Speaker: I have received it and it is under consideration.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो आपको अधिकार है और सरकार भी इस संबंध में विचार कर रही है। अच्छा हो अगर वह कलिंग अटैन्डान्स मोडन आज ही लग जाये। (गौर एवं विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, यहां हाउस में पानी के स्तर को उठाने की भी बात कही गई, पंजाबी विरोधी पर्चे

बांटने की बात भी यहां सुनी गई लेकिन वाल्मीकियों के विषय में अक्ल तो कोई आवाज उठाता नहीं, अगर उठाता है तो उसे दबाया जाता है। स्पीकर साहब, नीलाखेड़ी के अन्दर 15 कनाल 10 मरले जमीन थी यानी वह दो एकड़ के करीब बनती है। आधी जमीन में रविदासियों का कब्जा था और आधी जमीन पर वाल्मीकियों का मंदिर और धर्म ाला बनी हुई थी।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर से बोले।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं अपनी सीट पर से ही बोल रहा हूं (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि आधी जमीन पर वाल्मीकियों का मंदिर और धर्म ाला थी लेकिन श्री किरपा राम पूनिया जो इस सरकार में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने डी० सी० भोरिया से मिल कर वाल्मीकियों पर कुठाराघात किया। उनसे कब्जा छुड़ाया (गोर)

Mr. Speaker: Mr. Banarasi Dass, no no please take your sea. This is not the way.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे रूलज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस की किताब में सदन का संचालन करने के बारे में रूलज दिये हुए हैं। स्पीकर साहब, उस पुस्तिका में यह प्रावधान है कि इस सदन का सदस्य समय समय पर सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषयों पर आकर्षित कर सकता है। तारांकित प्र न, अतारांकित प्र न, काल अटैन् इन मो इन, ऐडजर्नमेंट मो इन और प्रिविलेज मो इन आदि के बारे में इस

किताब में व्यवस्था है। स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेंगे, कल मेरे साथी ने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहा था और आज सुबह मैंने भी एक नोटिस दिया है जो आपके पास पहुँच गया होगा। मैं उसमें कहा है कि एक ऐसा धिनौना पोस्टर सारे प्रदेश में जान-बूझ कर बांटा गया। इस पर सवाल भी आपके सचिवालय में आया हुआ है। मेरे मित्र ने उस सवाल के जो जवाब दिये हैं वे कुछ इवेसिव दिये हैं। स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मैटर है। इसका कुछ आधार जरूर है।

Mr. Speaker: No reply has been evasive.

Dr. Mangal Sein: Sir it is is very serious matter.

Mr Speaker: The matter is very serious, no doubt about it.

Dr. Mangal Sein: He has charged a very responsible man. मैं समझता हूँ कि वह रिस्पोसिबल रहा है, आज है या नहीं, यह मुझे पता नहीं।

Mr. Speaker: He is very responsible today also.

Dr Mangal Sein: Therefore, Sir, since he is a responsible man and is not present in this House. It is another matter that she never cares to attend. However, Sir, I honour the observations made by the presiding officers from time to time that one member should not ask a question or say anything against a person who is not present in the House.

Following the well sestablished tradition, my humble submission is this that these provisions are simply there to give some relief to the members. But, Sir, it is a burning topc of the State. और समाज का एक सैक न अननससरी हैरासमेंट महसूस कर रहा है। My friend has also rightly said कि आज उन्हे आये हुए 43 साल हो गये है। आज वे यहां की कल्चर, सो ल लाईफ और पोलिटिकल लाईफ मे बिल्कुल सररस हो गये है। इस हाउस में भी उस सैक न के कई मैम्बर्ज है। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ने जो ऐक न लिया वह मुझे मालूम है और मुख्य मंत्री जी की स्टेटमेंट भी मुझे याद है। उन्होने जो वारन किया था कि किसी को ऐसा करने की इजाजत नही दी जायेगी वह ठीक है लेकिन इन्होने जो बात कही वह अगर और अच्छी तरह से यहां आ जाती और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता तो ठीक था। इसलिए मैने आपकी सेवा में काल अटैन् न मो न भेजी है। Speaker Sir, please admit it and ask my friend the Hon'ble Home Minister to make a statement thereon.

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have received your calling attention notice and that is under consideration.

Dr. Mangal Sein: You kindly admit it so that I may get a chance to ask supplementary on the statement made on it.

श्री अध्यक्ष: स्पलीमेंट्री तो आपने आज बहुत कर लिये है।

डा० मंगल सैन: आपकी इजाजत से मैं और भी कर सकता हूँ।

Mr. Speaker: Yes yes, you can.

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, गलती से आज के कुछ अखबारों में यह छपा है कि बी० जे० पी० के श्री पी० के चौधरी ने भी कल हाउस से वाक आउट किया है। टू कीप दि रिकार्ड स्ट्रेट, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कल वाक-आउट नहीं किया। मैंने उनसे कन्फर्म किया है। वह तो वैसे ही उठकर गये थे। रिकार्ड स्ट्रेट रहे, इसलिए मैंने यह कहा है।

Dr. Mangal Sein: Speaker Sir, to keep the record straight it is very essential that this thing should be brought to your notice. Because what happens, if anybody goes for toilet, it is doubted by the press that he is staging a walk out. प्रेस वालों को यह बात बुरी नहीं लगनी चाहिये। जो भाई वैसे ही पे गब करने गया हो, या किसी काम से गया हो, उसको वाक-आउट समझ ले यह ठीक नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डायबैटिक हूँ। मुझे बार बार टायलैट के लिए उधार जाना पड़ता है। No body should doubt that I am walking out. I might be simply going for toilet, that's all.

Mr. Speaker: Dr Sahib, your point has come. Please take your seat.

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मेरा भी एक कालिंग अटैंटान्स मो आ था.....

Mr. Speaker: That is under consideration.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

भाहबाद सहकारी चीनी मिल द्वारा प्रयोग किए गए पानी की निकासी के कारण फसलो के नश्ट होने संबंधी

Mr Speaker: Hon'ble members I have received a notice of Calling Attention Motion No. 9 from Shri Harnam Singh M.L.A regarding the crops damaged due to discharge of used water by Co-Operative Sugar mills, Shahabad. I admit it. आज श्री हरनाम सिंह अपना नोटिस पढ दें ओर उसके बाद यदि कंसर्ड मिनिस्टर साहब स्टेटमैट देना चाहे तो दे दें ।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मै इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि भाहबाद सहकारी चीनी मिल से निकलने वाला प्रयोग किया हुआ पानी निकास के पर्याप्त प्रबन्ध न होने के कारण, त्योडा, बकाना, ारीफगढ के खेतो में भर गया है। किसानो में भारी बेचैनी हैं। यदि चीनी मिल के पानी से फसल को बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही नही की गई तो सारी फसल नश्ट हो जायेगी।

अतः मै निवेदन करता हूं कि सरकार फसल को बचाने तथा प्रभावित किसानो को राहत देने के लिए तुरंत कार्यवाही करें।

वक्तव्य—

सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर साहब, भाहबाद सहकारी चीनी मिल, भाहबाद के पानी के निकास का प्रावधान इस मिल की स्थापना के समय ही कर दिया गया था। यह पानी एक बरसाती नाला जिसका नाम बेनतान नाला है, के द्वारा निकास किया जात है। बेनतान नाले में मानसून तथा सर्दियों की भारी वर्षा का पानी भी बहता है। किन्तु गांव छपडी के आगे कुछ किसानो ने इस नाले के बहाव को रोक दिया है और वर्षा का पानी नीचले स्थान पर इकटठा हो जाता है।

2. भाहबाद सहकारी चीनी मिल में फरवरी, 1985 में उत्पादन भुरु हुआ था। इस मिल के पानी के प्रदूषण को भली-भांति हटाया जाता है और इस पानी का प्रयोग सहकारी चीनी मिल के फार्म की सिंचाई के लिए किया जाता है। किन्तु जो पानी फार्म की सिंचाई के बाद बच जाता है उसे बेनतान नाले में डाला जाता है। केवल इसी अवधि के दौरान ही इस मिल का पानी इस नाले में डाला जाता है। क्योंकि इस पानी के प्रदूषण पर मिल द्वारा भली-भांती काबू पा लिया जाता है, यह फसल के लिए हानिकारक नहीं है। वास्तव में वहां के किसान बेनतान नाले पर पम्पिक सैट लगाकर इस पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। बेनतान नाले में इस पानी को डालने के लिए हरियाण राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 1989-90 के लिए अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है।

3. इस वर्ष भाहबाद और उसके आस पास के क्षेत्रों में 26 और 27 फरवरी को भारी वर्षा हुई। सहकारी चीनी मिल भाहबाद में लगे वर्षा मापक यंत्र के अनुसार इन दो दिनों में 78 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकार्ड की गई इतनी वर्षा होने के कारण बेनतान नाले में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया, विशेषकर उस क्षेत्र में जहां बेनतान नाले को किसानों द्वारा रोक लिया गया है। इस प्रकार यह समस्या अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुई है न कि सहकारी चीनी मिल के पानी की वजह से जो कि मात्रा में बहुत ही कम है।

4. स्थानीय अधिकारीगण जैसे कि उपायुक्त, कुरुक्षेत्र जो कि सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन भी है, सहकारी चीनी मिल के प्रबन्धक निदेशक तथा ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों के ध्यान में यह मामला पहले ही आया हुआ है। माननीय सदस्य श्री हरनाम सिंह जी की उनसे बातचीत हो भी चुकी है। भाहबाद सहकारी चीनी मिल के प्रबन्धक निदेशक ने उन्हें यह आवासन दिया है कि यदि चीनी मिल के पानी से किसी खड़ी फसल को कोई नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा जो कि राजस्व अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जायेगा, सहकारी चीनी मिल द्वारा प्रभावित किसानों को दिया जायेगा।

श्री हरनाम सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पानी से फसलो के डूबने का सवाल इसी साल आया है या हर साल यह सवाल आता है?

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, इस मिल के पानी को हमारे किसान वर्ष 1987-88 और उससे पहले भी खेती के लिए प्रयोग करते रहे हैं। चूंकि इस साल सर्दी के मौसम में ज्यादा बारिश हुई और इस कारण आसपास का पानी वहां इकट्ठा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आवासन देता हूँ कि अगर हमारी मिल के पानी की वजह से किसानों की खेती खराब हुई है तो जो भी रैवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा मुआवजा निर्दिष्ट किया जाएगा, वह किसानों को दिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर का सवाल लागू होता है तो अगर मैं तो इन्कार भी किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से यह आवासन चाहता हूँ कि जो पानी किसानों के खेतों में भर गया है, क्या उसको ड्रेन आउट करने के लिए सरकार फौरी तौर पर कोई इंतजाम करेगी?

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर की जो बात है उस बारे में मैं आपके माध्यम से आवासन दे चुका हूँ कि किसानों की जो भी खेती मिल के पानी की वजह से खराब हुई है उसका मुआवजा हम देंगे। अगर की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 1985 में यह मिल भुरु हुई थी और उसी समय से पानी नाले में

डाल दिया जाता था। चकबन्दी से पहले यह नाला कायम था लेकिन कुछ प्रभाव वाली लोगो ने इसको सममतल कर दिया इस कारण उस क्षेत्र में जहां इसको सममतल कर दिया था वहां वर्षा का पानी इकटठा हो गया। वहां के लोग चाहते है कि उस जमीन पर नाले को खोदकर आगे ड्रेन में डाल दिया जाए इसके लिए उन्होंने बारबार ड्रेनेज विभाग और डी० सी० से कोनटैक्ट किया था।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री सदन की मेज पर कागज-पत्र रखेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) :Sir, I beg to lay on the Table-

1. The 14th Annual Report for the year 1987-88 of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

2. The 15th Annual Report for the year 1988-89 of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

वर्ष 1990-91 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज अब वर्ष 1990-91 के बजट पर जनरल डिस्कान होगी। इस सम्बन्ध में मैं एक प्रार्थना करता हूं कि आप टाईम का ध्यान रखे कोई भी मैम्बर दस मिनट

से ज्यादा टाईम लेने का यत्न न करे। दस मिनट में ही बजट के तथा अपनी कांस्टिच्यूएंसी के बारे में अपनी बात कहने का यत्न करें। होता क्या है कि मैम्बर साहिबान पहले ज्यादा टाईम ले लेते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान श्री बनारसी दास गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इस विषय में चर्चा करने एवं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले इन्होंने राज्य एवं केन्द्र के स्तर पर राजीव लॉंगोवाल समझौते के फलस्वरूप जो न्याययुद्ध छिडा और उसके फलस्वरूप जो बदलाव आया उसका जिक्र किया गया है। न्याययुद्ध छिडने के पचात् चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी। उस न्याययुद्ध ने सारे देहा में चेतना पैदा कर दी। हरियाणा राज्य की बागडौर सम्भालने के बाद चौधरी देवी लाल ने केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे देहा में घूम घूम कर जन जागरण का काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज श्री विवेकनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उभर कर देहा के सामने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय न्याययुद्ध चल रहा था उस समय इस देहाके और प्रदेश के लोग गोलियों के शिकार हो रहे थे और इसी विधान सभा के 21 सदस्यों ने चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में विधान सभा के पद को त्याग कर देहा को एक नया रास्ता दिखाया था। आज फिर इस देहा में नए सिरे से उन्ही के नेतृत्व में एक आन्दोलन चला और

सारे देश में केन्द्र के साथ साथ जनता दल की सरकार कायम हुई। हमारी सरकार विराजमान होने के बाद सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाये हैं जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 19.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं कहना चाहता हूँ कि चालू वर्ष का योजना परिव्यय 676 करोड़ रुपए रखा गया था लेकिन साधनों की कमी के कारण योजना परिव्यय 596.69 करोड़ ही रह गया। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह योजना बनाई गई थी उस वक्त इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए था कि किस तरह के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। बजट स्पीच में उप-मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 1990-91 के अंत में 31 करोड़ 19 लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है जबकि वर्ष के शुरू में 19 करोड़ 33 लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से इस घाटे की पूर्ति की जाएगी। इस बार हमारी सरकार ने नये टैक्स नहीं लगाये हैं यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त इसके लिए हालात बेहतर नहीं हैं। हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि जनता के ऊपर नये कर लगाए जाएं। वैसे नये कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जो टैक्स पहले ही लगे हुए हैं, चाहे बिजली के रेट्स से आमदनी की बात हो, चाहे और दूसरे कर हो, इनके अलावा अगर सरकार करों की चोरी रोक ले तो उसे नये कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। करों की चोरी रोकने से ही सरकार को काफी आमदनी हो सकती

है। इसलिए सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि करों की चोरी को किस प्रकार रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गुप्ता जी आपके केवल भिवानी जिले का अब तक का क्यूमूलेटिव लौस 5 करोड़ रुपये के लगभग है और इसमें पिछले एक वर्ष का घाटा 1 करोड़ 34 लाख है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इन बातों की ओर गौर करना चाहिए तभी करों की व दूसरी चोरियों को रोका जा सकेगा और इनसे सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केवल प्रशासकों की गलती के कारण उपभोक्ताओं पर करों के बोझों का और टैक्सों के बोझों का भार नहीं पड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में बेरोजगार युवकों को भत्ता देने की स्कीम चलाने का भी जिक्र किया गया और इस स्कीम के तहत चालू वर्ष में 30 हजार बेरोजगार युवकों को यह भत्ता सहायता दी भी गयी है। अगल वर्ष में इस योजना के तहत 5 करोड़ 90 लाख रुपये की धनराशि का खर्च प्रस्तावित किया गया है। यह सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वृद्ध लोगों को आत्म-सम्मान व उनकी सुरक्षा हेतु जो वृद्धवस्था पेंशन स्कीम चलायी है वह अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय कदम है और पूरे राष्ट्र में इस स्कीम की बदौलत हरियाणा को एक विशेष स्थान मिला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है कि अब वृद्ध लोगों को, कचहरियों में, दफ्तरों में अपनी

पैँ ंन के लिए धूमना नही पडता। अधिकारीगण गांव बांन जाकर लोगो से सम्पर्क बनाकर के लोगो का काम करते है ताकि उन्हे पैँ ंन लेने के लिए जगह जगह न भटकना पडे। घर बैठे ही लोगो को इस तरह की राहत सरकार के द्वारा दी जा रही है जिके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लोग इससे काफी खुा है। आज मनीआर्डर उनके घर पहुंचते है। मै इस विशय में एक बात कहना चाहता हूं कि आज पैँ ंन देने के लिए साल में पांच करोड रुपया मनीआर्डर करवाने पर खर्च किया जाता है। मेरा सुझाव है कि ब्लाक अधिकारी या पंचायत अधिकारी द्वारा 5-5 या 1010 गावों के बीच यह पैँ ंन बांटी जाए। इसके लिए नए कर्मचारियो को भर्ती कर लिया जाए। अब यह जो पांच करोड रुपया मनीआर्डर करवाने पर खर्च किया जाता है यह बेरोजगार नौजवानो को दिया जा सकता है। अगर ऐी कोई वयवस्था कर दी जाए तो ज्यादा उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेा कृशि प्रधान प्रदेा है। कृशि के लिए पानी की जरूरत होती है और पानी भी तीन प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो कुदरत के जरिए, दूसरे नहर के जरिए और तीसरे ट्यूबवैल के जरिए। पिछले अढाई सालो में बिजली उत्पादन के लिए जो पानी की व्यवस्था की जा सकी है, वास्तव में वह हमारी सरकार का सराहनीय कदम है। एक आध साल को छोडकर पिछले अढाई सालो में जितनी अच्छी बिजली हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाई वह पहले कभी नही हुई थी।

(विधन्) उसका श्रेय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को भी जाता है बल्कि सारी सरकार को जाता है। वह श्रेय जनता को भी जाता है जिसने ऐसी सरकार को बनाया यानी इस सरकार को सत्ता में लाई। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोग बड़ी उतावली से इंतजार कर रहे हैं कि एस० वाई० एल० नहर का पानी उनके खेतों में कब आएगा? सभी लोग चाहते हैं कि उनको इस पानी का पूरा हिस्सा मिले ताकि वे अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। जिस वक्त हमने अपने पॉर्न में एस० वाई० एल० नहर का पानी लेने के लिए नहर बनाई थी उस समय से लेकर अब नहर बनाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार प्रयत्न करे कि जब से हमारी तरफ नहर बनी है तब से लेकर अब तक उकी रख रखाव का खर्चा भी केन्द्रीय सरकार वहन करे क्योंकि उसमें पानी न आने का दोष हमारा नहीं है। उसके लिए दोष केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार का रहा है। पानी न आने की वजह से हमारे प्रदेश के लोगो की लुटाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० के पानी के विषय में इंदिरा गांधी जी ने अपना एवार्ड दिया था। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार का स्टैंड उस एवार्ड पर कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान का जो पानी जाता था उसका सौ करोड रुपया मुआवजे के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया था। मुझे अब भी भांका है कि जब तक थीन डैम नहीं बनता वह पानी पाकिस्तान को जाता रहेगा। थीन डैम भीघता से बनाने के लिए हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करना चाहिए। थीन डैम हरियाणा प्रदेश के लोगो के लिए, पंजाब के लोगो के लिए,

राजस्थान के लोगो के लिए यानि सारे दे 1 के लोगो के लिए बहुत जरुरी है। यदि वह डैम भीघता से बन जाए तो हां पर जो बिजली पैदा होगी उससे लोगो को बहुत फायदा होगा। हमें इस बात की मांग भी करनी चाहिए कि जिस समय वहां पर बिजली पैदा होगी उसका हमें पूरा हिस्सा मिलें। अध्यक्ष महोदय, आज प्र नोत्तर काल के दौरान दरियापुर कांड का जिक भी आया। हमारी जनता दल की सरकार के भुरु भुरु में बनते ही दरियापुर कांड हुआ और वह बहुत जघन्य कांड था। दरियापुर कांड करके अपराधियो ने हरियाणा में दूशित वातावरण पैदा करने का प्रयास किया था। उस समय हिसार में अनेको लोगो की दुकाने लूटी गई। जिन लोगो ने दुकाने लुटी उनसे हमारी सरकार ने माल बरामद करके वापिस दुकानदारो को दिया। लाखों रुपए का माल दुकानदारो को वापिस दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदे 1 के दुकानदारो और कर्मचारियो के लिए काम किया है तथा उनको कुछ राहत भी दी है लेकिन राहम देने के बावजूद भी दुकानदारो में कुछ नाराजगी है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि दुकानदारो को राहत देने के बावजूद भी वे हमसे नाराज क्यों है? क्या हमसे कोई भूल हो गई है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर कोई भूल हुई है अगर कोई गलती हुई है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अपनी किसी भूल को या गलती को स्वीकार करना भी प्रजातंत्र की नि गानी है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में भांगति का वातावरण बनाने के लिए चुनाव प्रणाली ठीक होनी चाहिए। हमारी केन्द्रीय सरकार चुनाव व्यवस्था को ठीक करने के बारे में विचार कर रही है। चुनावों के दौरान जिस किस्म की घटनाएं होती हैं, हिंसा होती है चाहे वह टोहाना के चुनाव में रीगिंग हो, चाहे तो आम के चुनाव में गडबडी हो, चाहे भिवानी के चुनावों में हत्याएं हो और चाहे अन्य स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो सभी निन्दनीय हैं। ऐसी घटनाओं की कोई भी आदमी प्र हिंसा नहीं करता निंदा करता है। मेहम के उप चुनाव में जो लोग मारे गए उसका हमें बड़ा अफसोस है। जिन हालात में मेहम के अन्दर हत्याएं हुई हैं मैं उसकी निन्दा किए बगैर नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, मेहम के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला सब-जुडिस है। मेहम की घटनाओं की जांच के लिए हाई कोर्ट का एक जज नियुक्त किया हुआ है। उसकी रिपोर्ट आने पर यह पता लग जाएगा कि कौन जिम्मेवार है। वहां पर जो घटना हुई है उसकी तह में जाना होगा कि वहां पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। अगर उसमें हमारी कोई गलती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर दूसरे लोगों ने वहां पर वह काम किया है तो हमारे इन्तजाम में कोई कमी रही होगी जिसको स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि पंजातंत्र में किसी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उप चुनाव के दौरान मेहम में जो घटनाएं हुई हैं उनकी सभी साथियों को निंदा करनी चाहिए। अगर

प्रजातंत्र खत्म हो जाता है तो जितने साथी यहां हाउस में बैठे हैं वे सभी धरा पाही हो जाएंगे और उनको यहां आने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा। हमारे प्रदेश के और देश के लोगो ने बड़ी कुर्बानी के बाद वोट का अधिकार प्राप्त किया है अगर वह खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे वह किसी भी प्रकार की ब्रिगेड हो। चाहे वह जैली ब्रिगेड हो, चाहे ग्रीन ब्रिगेड हो और चाहे कोई लाल ब्रिगेड हो उसका मुकाबला करना चाहिए और जो लोग उनका मुकाबला करते हैं हमें उनकी सराहना करनी चाहिए।

11:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने अपने कर्मचारियों को बोनस दे कर एक बहुत ही अच्छी बात की है। यह भी ठीक किया है कि उनका यह पैसा उनके भविष्य निधि खाते में जमा हो जायेगा। इसी प्रकार से सरकार ने यह भी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10-10 साल या 20-20 साल हो जाती थी और उनकी प्रमोशन नहीं होती थी उनको भी अब ऐडवांस इन्क्रीमेंट वगैरा मिलेगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए ये दोनों बहुत ही अच्छे कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है। शिक्षा के बारे में तो हमारे यहां स्कूलों की यह हालत है कि इन स्कूलों की हालत एक धर्म माला से भी बदतर है। इस बारे में सभी पार्टियों और प्रदेश के लोगों को राजनीतिक

स्तर से उपर उठकर काम करना होगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना होगा। आज कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक संकट हैं। इस बारे में चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश में या प्रदेश में राजनीतिक संकट नहीं हुआ करते बल्कि संकट होता है नैतिकता की कमी का, आचरण की कमी का और मनुष्य के चरित्र का। अगर गलत तत्व राज सत्ता में आ जाएंगे तो कोई भी देश या समाज अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों में नैतिकता की भावना आए और उनका चरित्र ठीक बने।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी गांवों के लोगों के लिए पीने के पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसा होने पर हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश होगा जिसमें हर एक गांव में पीने का पानी लोगों तक पहुंचेगा। इस बात के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जनता दल की हार्ड कमांड भी बधाई की पात्र है कि उसे मेहम काउप चुनाव नए सिरे से करवाने की मांग की। सरकार इस बात के लिए भी बधाई की पात्र है कि उसने मेहम की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इलैक्ट्रान कमी उन ने जो हिदायते मेहम के उप चुनाव के संबंध में जारी की है उनकी पूरी तरह से सरकार पालना करे और जो भी दोषी अधिकारी हो, चाहे वह

कितना ही बडा क्यो न हो और चाहे वह पुलिस का ही अधिकारी क्यो न हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एकान लेन। इसके साथ साथ सरकार को प्रशासनिक स्तर पर या दूसरे स्तर पर जिन लोगो ने वहां पर गडबड फैलाई है उन सब के खिलाफ एकान लेना चाहिए और एकान लेकर जनता में अपना पुनः विवास पैदा करना चाहिए। हमारी जनतांत्रिक सरकार है। जनतंत्र में लोगो की इच्छा के अनुरूप ही काम किया जाता है। इस कलंक को हमारी सरकार को धोना चाहिए ताकि यह पार्टी और सरकार इस प्रदेश के लिए एक अच्छी मिसाल साबित हो सके। मैं आशा करता हूं कि हमारी पार्टी और सरकार इस कलंक को धोएगी। जिस प्रकार से चौधरी देवी लाल जी ने बहादुरी से न्याय युद्ध लडते हुए प्रदेश और प्रदेश को नया रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर यह सरकार भी जाएगी और लोगो में अपना विवास पैदा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, कल गुप्ता जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि किसी प्रदेश को गाडगिल फार्मुले के तहत उस प्रदेश की योजना के लिए सहायता दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के अने मुख्य मंत्री रह चुके है। सभी यह कहते है कि आज केन्द्र में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री है और मैं मंत्री हु इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी से मैं प्रदेश के लिए पैसा ला रहा हूं। इसी प्रकार से कभी राजीव गांधी का नाम लेकर पैसा लाया जाता था। इस बारे में मैं अब यह चाहता हूं कि हमारी

सरकार को ऐसी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। इसलिए हमारी सरकार को गाडगिल फार्मूले के जरिए या किसी दूसरे फार्मूले के जरिए केन्द्र सरकार से प्रदे 1 के लिए अधिक से अधिक पैसा लाना चाहिए ताकि यह पैसा प्रदे 1 की डिवलैपमेंट के कामों पर खर्च हो सके। अध्यक्ष महोदय, जब तक प्रदे 1 में बजट की ठीक व्यवस्था नहीं होगी और पैसे की कमी होगी तब तक डिवलैपमेंटका काम नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों कन्साईनमेंट टैक्स की बात भी चली थी। उस वक्त की केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन नहीं किया था लेकिन अब तो केन्द्र में हमारी पार्टी की सरकार है। इसलिए अब इस मामले को फिर से केन्द्र सरकार के साथ उठाना चाहिए ताकि टैक्स का पैसा स्टेट को मिल पाए और उस पैसे से प्रदे 1 की डिवलैपमेंट का काम हो सके, प्रगति के काम हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके सामने प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेहमकी चर्चा बार बार उठती है और मेहम के बारे में यह खबर भी है कि वहां पर पुलिस में असंतोश रहा। अध्यक्ष महोदय, जिन पुलिस कर्मचारियों को मेहम में चुनाव की ड्यूटी पर भेजा गया, वहां पर उनके खाने पीने, रहने सहने का किसी भी प्रकार का कोई इन्तजाम नहीं किया जा सका तथा उनको अपनी नौकरी के बारे में भी काफी बेचैनी है, तकलीफ है। यदि कोई एच0 ए0 पी0 का टैस्ट पास कर ले तो उसकी उसी वक्त प्रमोट कर दिया जाता है जब कि पुलिस में 8 या 10 साल के बाद प्रमोशन होती है। यदि एच0 ए0 पी0 से ट्रांसफर हो कर कोई

हरियाणा पुलिस में आ जाता है तो 1-2 साल की सर्विस वाला 8-10 साल की सर्विस वाले से सीनियर हो जाता है। इस कारण से पुलिस में रैजिमेंट है। एक बड़े अफसर और छोटे कर्मचारी कान्सटेबल के वेतन में भी बहुत अन्तर है। जब तक उनकी तकलीफ को दूर नहीं किया जात, उनके पे स्केलज् को बैटर नहीं बनाया जाता, जब तक उनमें रिजेंटमेंट तो होगी ही। हम उनके दुख दर्द को दूर नहीं कर पाये जिस कारण उनमें बेचैनी है। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी हमें माननी पडेगी कि कोई भी प्रजातंत्रीय दे । या राज्य ज्यादा अर्से तक पुलिस के सहारे राज नहीं कर सकता। इस दौरान जिन अधिकारियों ने कोताही की है, गलती की है या बदमा ि की है उनको किसी भी प्रकार से बख्ताना नहीं चाहिए ताकि दे । के लोगो को और मेहत के लोगो को लगे कि सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मै टीचर्ज ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने कई जगह पर टीचर्ज ट्रेनिंग भुरु कर रखी है। टीचर्ज ट्रेनिंग संस्थानो में 5-6 महीने से तन्ख्वाह नहीं मिल रही है, उनको तनख्वाह समय पर मिलती चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रौढ ि िक्षा के लिए जो लोग काम करते थे वे सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बावजूद भी आर्थिक संकट में है। क्योकि अब उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई है। इन लोगो में बहुत से लोग ऐसे थे जो 10-12 साल से प्रौढ ि िक्षा के काम कर रहे थे। इस बारे में मै अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग कन्डी िंज

पूरी करते हैं ऐसे व्यक्तियों की छुट्टी करने की बजाय उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, अब आप वाईड अप करिये।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट में मुझे कुछ आवश्यक बातें कहनी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार के प्रशासनिक खर्च में जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है उसे कम किया जाए। आर० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या में कमी करनी चाहिए। यू० पी० स्टेट हरियाणा से करीब छः गुणा बड़ा है लेकिन यू० पी० और हरियाणा के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या लगभग बराबर है। इन अधिकारियों की संख्या कम की जानी चाहिए वरना स्टेट का खर्च बहुत ही ज्यादा होगा। इनकी संख्या को कम करने के लिए सरकार को चाहे कोई आयोग ही क्यों न नियुक्त करना पड़े लेकिन इनकी संख्या को कम करके सेव हुए पैसे को सरकार डिवैल्पमेंट पर खर्च करे ताकि स्टेट का विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष: आर्य जी, आपने काफी समय ले लिया है इसलिए अब आप बैठें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। हमारे उप-मुख्य मंत्री था फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है उसमें पैसे की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा

कि चाहे सचिवालय बनाना हो, चाहे टेल पर पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे सतनाली में बस स्टैण्ड बनाने की बात हो, चाहे लोहारु में वूलन मिल लगाने की बात है, इसी बजट में से इनके लिए पैसा खर्च किया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन भाब्दो के साथ मै गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई टैक्स नही लगाया है और भविश्य में भी हम उनसे आ आ करते है कि वे कोई टैक्स नही लगाएंगे। इन भाब्दो के साथ मै बजट का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं क्योकि मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष जी, सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। सब से पहले मै हरियाणा के उप-मुख्य मंत्री और जो यहां के वित्त मंत्री भी है उन्हे सदन में कर रहित बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देती हू। मार्च के पहले सप्ताह से नागरिको में भय व्यापत हो जाता है कि इस महीने से उनके घर का खर्चा बढ जायेगा क्योकि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार अपने बजट में नये कर लगायेगी। बैठे बैठाए ही उनकी आमदनी कम हो जायेगी।

(इस समय सभापतियो की सूची के एक सदस्य, श्री किान सिंह सांगवान, पदासीन हुए)

सभापति जी, कल हमारे वित्त मंत्री जी ने कर रहित बजट प्रस्तुत करके हरियाणा के नागरिको को राहत दी है और

उन्हे भयमुक्त किया है यह कह कर कि मैं इस बजट में कोई कर प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं उन्हे पुनः बधाई देती हूँ। सभापति जी, परम्परा यह रही है कि बजट प्रस्तुत करने के बाद एक या दो दिन का अन्तर दे कर उस पर चर्चा भुरु हो जाती है और ऐसी होना भी चाहिए क्योंकि केवल बजट वक्तव्य ही हमको नहीं दिया जात उसके साथ बजट के वयाख्यात्मक दस्तावेज भी दिये जाते हैं। अगर आप बजट पर कोई सार्थन चर्चा करवाना चाहते हैं तो यह आव यक है कि उन दस्तावेजो का अध्ययन करने के बाद हम लोग चर्चा भुरु करे। अब बीस किलो का भार हम लोगो को दिया गया है, बजट का वयाख्यात्मक ज्ञापन, उसके साथ अनुपूरक अनुदान मांगो का ब्यौरा यानी तमाम चीजे दे दी है और साथ ही सीमा बांध दी है कि दस मिनट उन तमाम बातो पर चर्चा करिए, जो कुछ कहना है वह कहिए। अब यह गागर में सागर भरने वाली बात है। यह तो किसी किसी की कैपेसिटी हो सकती है भायद गुप्ता जी की हो सकती है, हम लोगो की नहीं है। आज का यह अन्तर हमें सहज और स्वाभाविक रूप से मिल रहा था क्योंकि वीरवार होने के नाते आज गैर-सरकारी दिन था। आज के दिन गैर-सरकारी संकल्प हो जाता और हम लोग आज के दिन बजट को पढ लेते, कल आ कर चर्चा भुरु कर देते। यही कारण था कि जब बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पे ा हुई थी, मैंने यह रिक्वैस्ट की थी कि यह दिन हमारे लिए गैर-सरकारी रहने दिया जाये ताकि हम बजट को पढ कर चर्चा कर सकें लेकिन उसे माना नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आत कि

वजह क्या है, समय की कोई कमी तो दिखती नहीं। 20 तारीख से 28 तारीख तक आप लोगो ने छुट्टी डिक्लेअर की है और फिर 29 तारीख को सैान बुलाया है। अगर दो दिन और बहस चल जाती तो ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सार्थक बहस हम लोग कर सकते थे। आज हम बहस करते समय केवल उप-मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य को आधार बना सकते हैं बाकी कोई दस्तावेज पढने का हम लोगो को समय नहीं मिला। इसी बजट स्पीच को आधार बना कर मैं अपने विचार बजट पर सदन में रख रही हूँ। उप-मुख्य मंत्री महोदय जरा ध्यान देंगे। मैं उन्हें मुखातिब करके एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आप हिन्दी के बहुत पंडित हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हिन्दी पर आपको अधिकार भी हासिल है। आप देखें की बजट स्पीच के पहले ही पृष्ठ पर जहां आपने चौधरी औम प्रकाश चौटाला का स्वागत करते हुए कहा कि अपनी राजनैतिक परिपक्वता, संगठनात्मक योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं वहां अपने यह भी कहा कि वे हरियाणा विकास के बारे में उद्दिग्नता के लिए भली भांति जाने जाते हैं। उद्दिग्नता भाब्द के बारे में गुप्ता जी जानते हैं कि यह कभी अच्छे मायने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि खामखाह ही क्यों उद्दिग्न हो रहा है। फिर मैंने अंग्रेजी स्पीच को उठाया क्योंकि मुझे यह मालुम है कि यहां पहले अंग्रेजी में स्पीच बनती है फिर उसका तरजमा किया जाता है। मैंने देखा कि कौन से भाब्द का तरजमा अंग्रेजी से हिन्दी में किया है। उसमें लिखा था कंसर्न फार हरियाणा डिक्लेअरमेंट। अब कंसर्न भाब्द का उद्दिग्नता अर्थ

बनता है यह मुझे मालूम नहीं। मेरे विचारानुसार तो इसको चिंता भाब्द कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि हरियाणा के विकास के लिए ये चिन्तित है, विख्यात है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही आगे बढ़ना चाहता है तो व्याकुलता भाब्द इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उद्धिग्नता भाब्द ठीक नहीं बैठता। मुझे हैरानी है कि गुप्ता जी ने पढते हुए इसे क्यों नहीं काटा? हो सकता है कि ये भी उनकी कार्य शैली को उद्धिग्न मानते हों। इसलिए इन्होंने उद्धिग्नता भाब्द को ही रखा हो वरना यह भाब्द इसमें अखरता है।

इसके बाद गुप्ता जी मुझे एक और बात आपसे कहनी है। हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने जो संशोधित वार्षिक योजना रखी है उसके दो आंकड़े काफी दुखदायी हैं। हमारी जो टोटल सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 2900 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसमें से हमने केवल 2567 करोड़ रुपये ही खर्च करने की सम्भावना व्यक्त की है। यानि इसमें हमने तीन-सवा तीन सौ करोड़ रुपये की कमी की है। यह बात ठीक है कि उस पंचवर्षीय योजना की पूरी की पूरी जिम्मेवारी तो यह सरकार नहीं ले सकती क्योंकि उसके पहले के दो वर्ष के खर्च दूसरी सरकार कर गयी थी लेकिन उससे भी ज्यादा दुखदायी आंकड़े चालू वर्ष के हैं जिनकी सीधी-सीधी जिम्मेवारी हमारी वर्तमान सरकार पर आती है। 676 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय इसमें रखा गया था लेकिन उसको भी घटा कर 596.69 करोड़

रुपया कर दिया है। यह साढ़े ग्यारह परसैंट की कटौती है। एक आध परसैंट की कटौती हो तो लोग सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, उसके अनदेखा किया जा सकता है। जब हम अन्दर रिशर्क पढते हैं सं गोधित वार्षिक योजना का तो आम तौर पर दिमाग में यह बात आती है कि सं गोधन करके कुछ पैसा बढ़ाया गया होगा। इसलिए इसमें सं गोधन किया गया होगा ताकि विकास के कार्यों पर कुछ ज्यादा पैसा खर्चा हो सके। लेकिन दोनो आंकड़े घाटे के आंकड़े हैं। यहाँ पर पैसा घटाया गया है। 676 करोड़ रुपये पर साढ़े ग्यारह परसैंट की कटौती की गई है और टोटल सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी 333 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इससे विकास के कार्यों की झलक मिलती है कि पूरे वर्ष में इसमें कमी आई है। यह कोई अच्छी बात नहीं है हालांकि गवर्नमेंट के कई कंस्ट्रेटस रहे हैं। मैं उनको ऐप्रीशियेट करती हूँ। गवर्नमेंट के उन कंस्ट्रेटस को देखते हुए कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना पडा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय आ गए, जिनकी वजह से कुछ अनऐन्टीसिपेटिड एक्सपेंडिचर हो गया और उनको देना पडा। मैं समझती हूँ कि गुप्ता जी जवाब देते हुए यह कहेंगे कि इसमें काफी से ज्यादा भागीदारी सुशमा जी आपकी रही है क्योंकि तब आप शिक्षा मंत्री थी। मैं समझती हूँ कि यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमें अध्यापकों को पैसा देना पडा, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर हम वित्तीय अनुपासन के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा होता। इससे जो विकास के कार्यों की कमी की झलक आती

है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उप मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात और आपसे कहूंगी जिसका मुझे काफी दुख है। आप पृष्ठ 4 पर देखिए जहां वार्षिक योजना का जिक्र आता है वहां पर बीच में एक लाइन लिखी है कि अप्रैल, 90 से हम आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 में प्रवेश करेंगे। यह पढ़ कर मुझे दुख हुआ कि इस योजना अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य-नीति और दृष्टीकोण को अभी कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैं यह कहती हूँ कि यह बात गलत है। राजनीतिक दल तो अपनी नीतियों और दृष्टीकोण को उसी दिन अंतिम रूप दे देते हैं जब वह अपना इलैक्ट्रॉनिक मैनीफैस्टो डिक्लेयर करते हैं। उन नीतियों और दृष्टीकोण को झलकाने वाली योजनाओं को अगर अंतिम रूप नहीं दिया गया तो यह बात तो मानी जा सकती है कि हमारी योजनाएँ अभी बननी हैं लेकिन यदि हमारी नीति ही स्पष्ट नहीं है या हमारा दृष्टीकोण साफ नहीं है यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बात बजट वक्तव्य में आये, यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। नीतियों और दृष्टीकोण के बारे में तो जब हम लोग चुनाव के अखाड़े में उतरे थे, उसी दिन स्पष्ट कर दिया था। हमारी नीतियों और दृष्टीकोण को जनता ने पसंद किया था तभी तो उसने आपको सत्ता के आसन पर बैठाया था। हमने अपनी नीतियों और दृष्टीकोण मंचों पर गाया और महारानियों की तरह से भाया था। जनता से उसको जोड़ा था। तभी हम मੈम्बर बने थे। हमारे मुख्य मंत्री बदले हैं। उसी दल की सरकार है। उसी दल के विधायक हैं। दल के नेता बदल गये हैं यह दूसरी बात है। उसी दल की

कार्य पैली है, उसी दल की कार्य प्रणाली है। उसी दल की नीतियां हैं। उसी दल का दृष्टीकोण है। गवर्नमेंटके नेता बदलने से प्रगति के कामों में गति बदल सकती है। कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन बजट वकवतय में यह कहना कि हमारी नीति और दृष्टीकोण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, यह ठीक बात नहीं है। हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, हमारा दृष्टीकोण बड़ा साफ है। हां इनको झलकाने वाली योजनाओं को जो आगामी पांच वर्षों में कौन सी बनेगी, नैचुरली उसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। वह साथ साथ चलेगी। बदली भी जाएगी। इस तरह से उसको अगर आप कहते तो भायद ज्यादा अच्छा लगता। जिस तरह से यहां पर कहा गया है, यह बहुत अच्छा नहीं लगता। एक बात उप मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्पीच में यह कही है कि इन्होंने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि सितम्बर 1990 तक हरियाणा प्रान्त के हर गांव को नल द्वारा पेय जल की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। आपने आगे यह कहा है कि मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस दि 11 में कार्य पूरे जोर- जोर से आरम्भ किया जा चुका है। यह बात पढकर अच्छी लगी लेकिन गुप्ता जी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं उनसे पूरे जोर- जोर वाली बात नहीं लगती। उन आंकड़ों द्वारा बताया गया है कि वर्ष 1989-90 के दौरान 400 समस्याग्रस्त गावों को भुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक केवल 260 समस्याग्रस्त गावों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। सभापति महोदय, वर्ष 1989-90 में चार सौ समस्याग्रस्त गावों को पानी देने का लक्ष्य था लेकिन जनवरी,

1990 तक केवल 260 गावों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। आपको मालूम है कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। आपने जनवरी तक के आंकड़े दिए हैं। इसका मतलब यह है कि दस महीनों में आपने 260 गावों को पानी दिया है। साल खत्म होने में केवल दो मास बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि आपने एक मास में 26 गावों को पानी सप्लाई किया और आगे दो महीनों में 140 गावों को कवर करना है। इसका मतलब यह है कि मास में 70 गावों को आप कवर करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि आप यहां क्या लिख रहे हैं। और ये कैसे कवर होंगे? अब तक एक मास में 26 गावों को ही पानी दे पाए और अब एक मास में 70 गावों को पानी देंगे, यह कैसे हो पाएगा। आप सारे पैरा को पढ़ लें। सारे के सारे आंकड़ों को देखें। मुझे भाक है कि 33 परसेंट की जो कमी है जो 33 परसेंट का लक्ष्य बाकी रहता है उसको दो महीने में कैसे पूरा करेंगे? सभापति महोदय, आगे देखिए। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख आपरे तनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले जनवरी, 1990 तक केवल 67227 आपरे तन कये गए हैं। सभापति महोदय, इस महीने में केवल 67 परसेंट लक्ष्य पूरा हुआ है और बाकी 33 परसेंट फरवरी और मार्च में पूरा करने का प्रोग्राम है। मुझे भाक है कि दो महीने में यह कैसे पूरा होगा? गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 36666 व्यक्तियों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 27309 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। अगले दो महीने में यानी फरवरी और मार्च में 9357 व्यक्तियों को लाभ

पहुंचाना है इसका मतलब यह हुआ कि एक महीने में लगभग 2730 व्यक्तियों को इस स्कीम का लाभ पहुंचा और अब आप एक महीने में 4600 व्यक्तियों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यह लक्ष्य कैसे पुरा होगा? यह बात समझ में नहीं आती। सभापति महोदय, अब आप वानिकी कार्यक्रम को देखिए। इसके अन्तर्गत 1988-89 में 5 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने थे लेकिन आपने जनवरी 1990 तक 4 करोड़ 32 लाख वृक्ष लगाए हैं और अभी एक करोड़ 18 लाख पेड़ लगाने बाकी हैं। इसका मतलब है कि 43 लाख 32 हजार पेड़ हर महीने लगाए और अब हर महीने 59 लाख पेड़ लगाने पड़ेंगे तभी लक्ष्य पूरा होगा। यह हो पाएगा या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। बायोगैस संयंत्र लगाने का पूरे साल का लक्ष्य 2000 था लेकिन इस महीने में 1349 बायोगैस संयंत्र लगाए गए। 651 बायोगैस संयंत्र दो महीने में लगाने हैं। पहले हर महीने 135 बायोगैस संयंत्र लगाए गए लेकिन अब 325 बायोगैस संयंत्र हर महीने लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों की जो भलाई करनी थी उसका लक्ष्य वर्ष 1988-89 में 56326 रखा गया था लेकिन उस लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 52079 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। सभापति जी इसका मतलब यह है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रति माह 5208 परिवारों की सहायता की और अगले दो महीने में 4244 परिवारों की सहायता करनी है और एक महीने में 2122 परिवारों की सहायता करनी है। सभापति जी, हमें इस प्रकार से काम करने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। यह नहीं होना चाहिए

कि दस महीने में तो चींटी की चाल से काम लिया जाए और जो अंत में दो महीने रह जाए उसमें तेज चाल से काम किया जाए। अधिकारियों की इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। इन दो महीनों में अन्धाधुंध खर्चा किया जाता है। सारे के सारे टैन्डर्ज इन दो महीनों में मांगे जाते हैं। सारा रुपया खर्च करने की मनोवृत्ति इन दो महीनों में होती है। क्योंकि दो महीनों के बाद ग्रांट लैप्स हो जाती है। घटिया माल खरीदा जाता है। इन दिनों में आपाधापी होती है। माल खरीदने के मामले में और काम करने के मामले में जो नियम हैं उनमें ढील दी जाती है और कई नियम नजरअन्दाज किए जाते हैं। ऐसा करने का कारण केवल यह होता है कि कहीं ग्रांट लैप्स न हो जाए। अधिकारियों को डर रहता है कि ग्रांट लैप्स होने से उनकी बदनामी होगी। सभापति जी, मेरा कहना यह है कि इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, यह परम्परा बदलनी पड़ेगी। कहा जाता है कि जब कोई योजना आरम्भ होती है तो उसके तीसरे या चौथे महीने ग्रांट आती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही कोई योजना मंजूर हो उसके लिए धनराशि उसी समय उपलब्ध करा देनी चाहिए। हमें कायदे कानून के अनुसार काम करना चाहिए। कायदे कानून के अनुसार काम करने से संतुष्टि होती है। यह नहीं होना चाहिए कि पहले दस महीने में तो 66 परसेंट काम किया जाए और आखिरी दो महीनों में 33 परसेंट काम किया जाए। इस प्रवृत्ति को हमें रोकना है तभी काम ठीक ढंग से हो सकेगा।

श्री सभापति: आपके बोलते हुए चौदह मिनट हो गए हैं। अब आप बैठिए।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अभी तो मैंने छः पृष्ठ ही पढ़े हैं। इसके तो 39 पृष्ठ हैं।

श्री सूरजभान: सभापति जी, एक ही रात में यह हालत है अगर दो दिन दे देते तो पता नहीं क्या होता।

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, जहां तक एस0 वाई0 एल0 का सवाल है इस बारे में उप मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने की गति में तेजी आएगी। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है, बिल्कुल तेजी आनी चाहिए और पहले केन्द्र सरकार की ओर से इस कार्य के लिए जो अडचनें आती थी, वे अब बिल्कुल समाप्त हो गयी हैं। अब केन्द्र में हमारी सरकार विराजमान है। लेकिन गुप्ता जी मैं केवल एक वायदा आपको याद दिलाना चाहती हूं। पिछले सत्र में सिंचाई तथा बिजली मंत्री महोदय से हमने एक बात कही थी और उन्होंने क्वै चन आवर में एक प्र न के जवाब में कहा था कि वे नौ बार एस0 वाई0 एल0 नहर देख कर आए हैं। हमने कहा था कि आप नौ बार इस नहर को देखकर आए हैं तो कम से कम हमारी इस 90 विधायकों की टीम को वहां पर ले चलिए ताकि सभी विधायक अपनी आंख से देख लें कि वह काम कितनी गति से चल रहा है। कितनी तरक्की इस काम में है। इस पर उन्होंने सदन में यह

आ वासन दिया था कि हां जरूर ले जाएंगे। (विघ्न) इसलिए मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगी कि सरकार अपना वायदा निभाये और इन सभी 90 के 90 एम0 एल0 एज0 को वहां नहर का काम दिखाने के लिए ले जाएं ताकि हम अपनी आंख से देख सकें कि उस काम में कितनी तरक्की और प्रगति हो गयी है।

सभापति महोदय, पेज 12 पर इन्होंने लिखा है कि किसानों के खेतों के साथ साथ लगे वृक्षों से होने वाली आय का आधा हिस्सा उन्हें देने के लिए आगे भी सरकार वचनबद्ध है। आगे की वचनबद्धता पर तो मैं प्र न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ लेकिन मैं इतना अव य कहना चाहूंगी कि अब तक इस तरह का कितना पैसा किसानों में बांटा जा चुका है यह वे बता दें। यह स्कीम हमारी सरकार की सबसे उच्चतम स्कीमों में से एक थी कि सड़क के साथ लगने वाले वृक्ष जब बेंचे जाएंगे तो उसकी आधी आमदनी किसानों को दी जाएगी। इसलिए मैं यह जरूर जानना चाहता हूँ कि बेंचें गए वृक्षों में कितनी आय हुई और उसका कितना हिस्सा किसानों को बांटा गया और कितने किसान इससे लाभान्वित हुए?

सभापति महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात अव य जानना चाहूंगी। जब अनुपूरक अनुमानों को दूसरी किस्त सदन में रखी गई थी तो उस समय उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य आयोग एवं जिला फोरम बनाने के लिए 60.65 हजार रुपया मांगा गया था। यह एक बहुत राहत देने वाला काम है जोकि हरियाणा

सरकार ने किया है। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार इन जिला फोरमों ने काम करना शुरू नहीं किया है। एक वर्ष के लिए हमने इनको बनाने का निर्णय ले भी लिया। वे बन भी गए। उनमें जो लोग बैठने थे वे भी नियुक्त हो गए। नियुक्तियां बदल भी गयीं, दूसरी नियुक्तियां भी हो गईं लेकिन अभी तक उन फोरमों ने अपना काम शुरू नहीं किया। एक बात सभापति महोदय, मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि अगर ये फोरम अपना काम करना शुरू कर भी दें तो जब तक उपभोक्ता में जागरण को न लाया जाएगा तब तक इनका गठन गैर प्रभावी रहेगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आप इस काम के लिए एक पखवाडा मनवाइयें। उपभोक्ता जागरण के अभियान के नाम से 15 दिनों का एक पखवाडा हो, जिसमें पोस्टर्स निकालें, जिसमें वॉलन्ट्री आर्गनाइजेशन को आप लें, टीचर्स को आप लें, जिला प्रशासन के लोगों को आप उसमें भिजवाएं और उसके पूरे 15 दिनों तक हरियाणा के आखिरी गांव के आखिरी उपभोक्ता तक जब तक हम यह बात नहीं पहुंचाते कि हमने इस तरह के फोरमों का गठन किया है जहां जाकर के वे लोग अपनी राहत प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिकायतें दे सकते हैं, तब तक उन फोरमों का गठन केवल रस्मी बनकर रह जाएगा। अगर आप यह चाहते हैं कि यह फोरम प्रभावी ढंग से काम करे तो यह बहुत आवश्यक है कि उपभोक्ता जागरण का अभियान शुरू किया जाए और इनके लिए 15 दिनों का पखवाडा मनाया जाए ताकि हरियाणा के उपभोक्ता जागरण हो सके।

श्री सभापति: बहन जी, आप जल्दी वाइंड अप कीजियेगा।

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, एक बात शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगी। सरकार ने यहां पर कहा कि हमने बहुत से स्कूलज अप-ग्रेड किये हैं और उनके नाम भी दिये हैं।

उप-मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): बहन जी, वे सब आप ने ही किये थे।

श्रीमती सुशमा स्वराज: गुप्ता जी, आप वित्त मंत्री हैं। आप उस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और अगर आप सभी मिलकर सहयोगा न करते तो कुछ भी न होता। आप पैसा न देते तो कैसे सारा काम होता। मैं केवल एक चीज कहना चाहती हूं कि पहली बार यह तरीका अपनाया गया यानि हर विधायक से पूछ कर काम किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि वे हल्के के प्रतिनिधी हैं और वे वहां की मांग को जानते हैं। ऐसा करके हम लोगो ने स्कूलो का दर्जा बढा दिया। भाई आत्मा राम गोदारा ने भी सभापति के पद पर बैठे बैठे टिप्पणी कर दी कि बहन जी ने अपने हलके के स्कूल ज्यादा अपग्रेड कर लिये। क्योंकि वह टिप्पणी लाइट मूड में की गई थी इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आज यह बताना चाहती हूं कि जितने हमारे एम0 एल0 एज0 साथी बैठे हैं एक भी खडा हो कर ऐसा नहीं कह सकता।

(विधुन) अडुडललल डललल डें दस हलुके है और दस हलुको डें 16 सुकुल अडुग्रेड हो गए तो डेरे डलंटे कलतने आए यह तो देख लो। तो हमने डकलयदल, नीतल डनलई, कलइटेरलल डनलय। हमने कलइटेरलल कल उलुलंधन नही होने दललल और उसके सलथ सलथ आड लोगो की संतुशुटी डी हो गई। डलतनी अवेलेडल चीड थी उसको हमने डरलडर डलंटेने की कोलललल की। इससे सब लोगो की संतुशुटी हुई। इसलललल डै केवल यह कहनल डलहती हूँ कल इस डलर आडने डो 175 सुकुलो को अडुग्रेड करने कल लकुषुड रखल है, सौ डुरलइडरी से डलडल, 50 डलडल से हलई, और 25 सीनलडर सैकेंडरी, इनको आड उसी तरीके से डलंटे डलससे सभी सलथलडो की संतुशुटी हो और उनको यह न लगे कल एक डगह डर डहुत डुडलदल दे दललल गए है, और एक डगह डर डहुत कड दे दललल गए। अडर आड ठीक डलंटे करेंगे तो सभी एड0 एल0 एड0 कहेंगे कल हमें हमलरल हलसुसल डललल है। तो उसी तरीके से यह कललल डलए तो ठीक है। डहलं डुरलइडल सुकुलो के ललकुषको कल सवल है उनके डलरे डें डै यह कहनल डलहती हूँ कल उनके डलरे सुडुरीड कोर्ट कल एक नलरुणड आडल थल। डहले उसकी डडडेंड के डलरे डें कुषु डतडेद थल। अब उस डडडेंड की डी वुडलखुडल आ गई है। सुडुरीड कोर्ट ने यह कलल है कल डुरलइडल सुकुलो को डी सरकलरी सुकुलो से डे और डी0 ए0 की डेरलटी आडको देनी है। डै ललकुषल डंत्री डी को केवल इतनल कहनल डलहूंगी कल सुकेल और डी0 ए0 की डेरलटी डी आड दें। हम डुरलइडल सुकुलो को इतनी डुरलंटे डी दे और उसके डलद इस तरह की तोहडतें सहें कल डुरलइडल सुकुलो के टीकलरुड को तनखलह नही डललती

या ज्यादा पर दस्तखत करवा कर कम दिये जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान ही क्यों न कर दें। कालेज वालों ने कर दिया है वे कालेज पैटर्न पर देते हैं। सीधे यहां से पैसा जाता है और बैंकों में जमा हो जाता है। तो कालेज पैटर्न अगर आप अपना ले तो आप पर हींग फटकडी का बोझ जरा भी नहीं पड़ेगा लेकिन वे लोग भाषाण से मुक्त हो जाएंगे। यह एक अच्छा काम होगा और आप लोगों की सराहना होगी। आप चाहे कालेज पैटर्न पर दे दो या ट्रेजरी के थू दे दो। इनमें से कोई पैटर्न अपना ले क्योंकि इतना पैसा सरकारी खजाने से जाने के बाद भी वे भाषित हैं, उनको भाषाण से बचाया जाए। प्रौढ शिक्षा को बन्द किया जाना तो बहुत तर्क संगत है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया कि वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे हीरा चन्द जी ने कहा कि उनका जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वह केवल 160 लोगों का है। वे सभी बी० ए० बी० एड० हैं, उनमें से कोई भी मैट्रिक नहीं है बल्कि कुछ एम० ए० बी० एड० भी है। ऐजूकेटिव डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और यहां पर रिक्तियां होती रहती हैं। इसलिए उनको कहीं ऐडजस्ट कर दिया जाए। अब आप नए स्कूल अपग्रेड करेंगे और वहां पर आपको और ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो उसमें इन 160 लोगों को ऐडजस्ट कर दें। वे लोग अब 40-42 साल के हो गए हैं और रोड पर आकर खड़े हो गए हैं। अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत बढ़िया बात होगी।

पर्यटन के बारे में एक दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। पर्यटन के बारे में ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो इन्होंने कहा कि मेहम में 'चौबीसी का चबुतरा' ऐतिहासिक स्थल पर एक रेस्तरां बन चुका है। सभापति जी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चौबीसी मेह में एक ऐसी पंचायत थी जिसकी बहुत गौरव ाली परम्परा रही है। बड़ी स्थापित परम्परा रही है कि कवह अपना उम्मीदवार अगर एक बार चुन लेती थी तो उसके पीछे एक दम खरा काम करती थी। हम पूरी पंचायतों में 'चौबीसी का नाम लिया करते थे क्योंकि चौबीसी की गौरव ाली परम्परा का पिछले दिनों में जिस तरह से चीर हरन हुआ है वह बहुत निन्दनीय है। जितनी उसकी निन्दा की जाए उतनी कम है। आज उस चौबीसी के चबुतरे पर भाोक सभाए हो, सरकार विरोधी नारे लगे। (विघ्न) कुछ लोग इधर से कह रहे हैं कि ठीक हुआ लेकिन ये यह न समझे कि वहां के लोग दोशी नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि जैसे द्रोपदी के चीन हरन के लिए दुर्योधन दोशी था उतने ही युधिष्ठिर भी दोशी थे जिन्होंने उसको दांव पर लगाया। उसी प्रकार से यह जो परम्परा जिस प्रकार से भ्रष्ट हुई है, जिस तरह से चौबीसी की गरिमा धूमिल हुई है वह हम सब के लिए भार्म की बात है। जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से एक व्यक्ति के लिए ही भार्म की बात नहीं बल्कि सब के लिए है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एक तो हमने उसको ऐतिहासिक स्थल की संज्ञा दी, मेहम में चौबीसी का चबुतरा उस गौरव ाली परम्परा को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेगी इस

चौबीसी के स्मरणीत इतिहाय में काला अध्याया जुडेगा, यह हमको उस समय मालूम नही था। सब से बुरी बात तो यह है कि जब वहां ऐतिहासिक स्थल बना उसी साल ये सारी घटनाएं घटी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर एक बात पर्यटन में आई है कि गुडगांव जिला में दमदमा के समीप एक मनोरंजन पार्क की स्थापना होगी जो डिजनीलैंड की तरह होगा। सभापति जी मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि डिजनीलैंड पर हमारे कई साथियो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए। भाई राम विलास भार्मा ने और दूसरे कई भाइयो ने दिए और हमारे अध्यक्ष जी ने यह कह करके उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावो को रिजैक्ट कर दिया कि डिजनीलैंड पर चूंकि 5-6 सवाल ऐडमिट कर लिए है इसलिए उस समय आप सप्लीमेंटरी पूछ लेना। सभापति जी, आप तो जानते है कि प्र नो का जवाब जेरे गौर है, जेरे तलब है, विचाराधीन है और आपके सुझाव पर गौर किया जाएगा ऐसे जवाब दे कर टाला जा सकता है लेकिन जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऐडमिट हो जाता है तो उस पर सरकार को अपना एक नीतिगत वक्तव्य देना पडता है जो बकायदा रिकार्ड बनता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि इस बारे में भ्रांतिया है या प्रैस में इस बारे में कुछ गलत खबरे दी गई है या जो किसान लोग यहकह रहे है कि उन्हे उजाडा जा रहा है अर वे लोग किसी गलतफहमी का िकार हो कर यह कह रहे है तो यह सबसे बडा फार्म है जहां पर सरकार अपना नीतिगत वक्तव्य दे कर उन

भ्रांतियों को दूर कर दे। भ्रांतिया इसलिए पैदा होती है, क्योंकि अमरीका का डिजनीलैंड केवल दो हजार एकड़ में बना है और इस डिजनीलैंड के लिए 28 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। इसलिए आईब्रोज उठती है। अगर उन आईब्रोज उठने का कोई सही जवाब, एकदम कंविन्सिंग जवाब, सरकार के पास हो तो जरूर देना चाहिए। हम जैसे लोगों को भी बड़ी मुश्किल आई हुई है क्योंकि हम लोगों से भी पूछते हैं। फिर हम लोगों को बता सकते हैं कि नहीं यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसलिए इस पर सरकार को जरूर अपना वक्तव्य देना चाहिए।

इसके अलावा सभापति जी, मैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सदन में जिक्र आया है। यह हरियाणा की एक ऐसी स्कीम है जिसने पूरे देश में हल्ला मचा दिया है। मतलब यह कि कांग्रेस की सरकार के मुख्य मंत्रियों को भी चुनावों से पहले यह घोषणा करनी पड़ी कि हम 100 रुपए पेंशन के देंगे, 150 रुपए देंगे। उन लोगों ने भी बुढ़ापा पेंशन दी। हमारे यहां तो इसके लिए 101.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छी स्कीम है। इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी कई गांवों से हमें पता चलता है कि जो पेंशन के पात्र व्यक्ति हैं वह पेंशन से वंचित रह जाते हैं। मैं करनाल हलके के एक गांव में जब गई तो उस अकेले एक गांव में 89 नाम ऐसे बुढ़ों के आए जिन्होंने मुझे कहा कि उनके नाम काट दिए गए हैं। भारतरत्नी अधिकारी वहां जाते हैं और उनके

नाम जानबूझ कर काट देते हैं। कई जगहों पर तो चुन चुन कर यह देखा जाता है कि फलों वृद्ध की निशठा किस दल में है। अगर उसकी निशठा किसी और दल में हो तो उसका नाम काट दिया जाता है। यह बहुत गलत बात है। इसके अलावा एक बात है। इन के बारे में यह भी कहना चाहती हूँ कि इन की डिस्बर्समेंट पर मनी आर्डर के माध्यम से जो 5 रुपए खर्च करते हैं वह रुपया किसी खाते में नहीं जा रहा है। न तो वह रुपया हरियाणा के विकास के खाते में जा रहा है और न किसी के पल्ले लग रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप यह कर सकते हैं कि वह पैसा आप बैंक में जमा करवा दें लेकिन ऐसे नहीं जैसे कामरेड हरनाम सिंह जी ने कहा कि जिसको मैं इन दी जा रही है उनको पास बुक दे दी जाए। यदि उनको पास बुक दे दी जाए तो वे वृद्ध और अपाहिज लोग कैसे चल कर जाएंगे। वे साईन भी नहीं कर सकते। बैंक में सबसे बड़ा झगडा साईन मिलाने का होता है। बूढ़े आदमी कांपते हाथों से साईन करेंगे तो उनके साईन कैसे मेल खाएंगे। बैंक में आप सिर्फ पैसा जमा करवा दें और अनएम्पलायड ग्रेजुएट्स से आप वह पैसा बंटवाएं। अपएम्पलायड ग्रेजुएट से अगर आप चार परसेंट कमी इन दें क रवह पैसा बंटवाएंगे तो यदि एक ग्रेजुएट 10 हजार रुपया बांटेगा तो उनको 400 रुपए मिल जाएंगे जोकि बेरोजगारी भत्ते का चार गुणा बनता है। इन सुझावों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

श्री आत्मा राम गोदारा (धिराय): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सभापति महोदय, 14-3-1990 को हमारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री जी ने 1990-91 का बजट सदन में प्रस्तुत किया जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड हुआ हू। सभापति महोदय, बजट के आंकड़ो पर चर्चा करने से पहले मैं भारतवर्ष में आए हुए राजनैतिक बदलाव की चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। हमारे देश के बहादुर लोगो ने राजनैतिक बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत दिया है और बहुत ही भांतिपूर्ण तरीके से हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ा राजनैतिक बदलाव दिया। भारत की जनता ने 1989 के पार्लियामेंट के चुनावो में यह साबित कर दिया कि भारत का वोटर कम से कम प्रजातंत्र के हथियारो को इस्तेमाल करने में बहुत परिपक्व हो गया है। उसी बदलाव के तहत हमने यह देखा कि देश की आजादी के बाद लगातार सेंटर में और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी का राज रहने के बावजूद, एक थोड़े से समय के लिए 1977 में बदलाव आया था। सभापति महोदय, भारत के वोटरों ने सेंटर के लैवल पर भी और राज्यों में भी कांग्रेस सरकारो को धरा पाही करके सेंटर में नेशनल फ्रंट की सरकार और राज्यों में जनता दल और बी0 जे0 पी0 की सरकारे कायम की। यह एक बहुत ऐतिहासिक बात है। इसी प्रकार से भारत के वोटरों ने एक और निराली बात की थी। वह यह थी कि हम यह आम तौर पर देखते थे कि पत्रकारों के और पत्रकारों की एजेंसियों के इलैक्शन से पहले कुछ अनुमान अखबारों में छपते थे और

लगातार दे 1 की आजादी के बाद तकरीबन भारत का वोटर उन अनुमानों के अनुसार ही सरकार बना दिया करता था लेकिन दे 1 की आजादी के बाद पहला मौका 1977 में आया जब भारत के वोटरों ने सारे पत्रकारों को, सारी भारत की प्रेसों को और सभी अखबारों की एजेंसियों के अनुमानों को बिल्कुल धरा पायी कर दिया। चैयरमैन साहब, किसी भी अखबार ने, किसी भी अखबार की एजेंसी ने या किसी भी पत्रकार ने 1977 के उस रिजल्ट की भांका जाहिर नहीं की थी। जो 1977 में भारत के वोटरों ने अपने मत डाल कर दिखाया। चैयरमैन साहब, इसलिए मैं विशेष रूप से उन मामलों में पत्रकारों के बारे में एक जिक्र करता आवे एक समझता हूँ। पत्रकारों के अनुमान भारत के वोटरों ने गलत साबित किए। उस समय चाहिए तो यह था कि भारत के पत्रकार अपने आप में कुछ चिंतन करते और सोचते कि जो अनुमान तुम एयर कंडी टान्ड कमरों में बैठकर भारत के वोटरों के बारे में अखबारों में लिख देते हैं, वह क्यों गलत सिद्ध हुआ है। वे कम से कम मैजोरिटी आफ वोटर्स के बारे में सोचते जिन्होंने यह फैसला दिया था। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान में 85 प्रतिशत जनता देहात में रहती है।
(विघ्न)

Shri Ram Bilas Sharma: Mr. Chairman, it is budget discussion. मेरे ये भाई पे 1 से वकील है और इस सदन के बहुत ही सम्मानित सदस्य है। इन्हे मालूम होगा कि पत्रकारों को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। पहले ये हमारे पक्ष में भी लिखते रहे हैं। अब अगर वे हमारी कोई आलोचना करते हैं तो

उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। It should be appreciated. मैं चाहता हूँ कि प्रैस के बारे में ये ऐसी कोई बात न कहें जो ठीक न हो।

श्री आत्मा राम गोदारा: चेयरमैन साहब, मैं अपने साथी भाई राम बिलास जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी प्रै की फ्रीडम का उतना ही हामी हूँ जितना की ये है। मैं ऐसी कोई डैरोगेटरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ जो यहां के वोटरो ने करके दिखाया है। चेयरमैन साहब, जो बात मैं कह रहा हूँ वह इस बजट से संबंधित ही है। यह बात बजट के प्रावधान में ही आती है। बजट के प्रावधान में यह भी है कि कोई भी सरकार हिन्दुस्तान की प्रैस के लिए बजट में कितनी सुविधा देती है। ये सारी चीजे बजट से संबंधित है। चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जो परिणाम हिन्दुस्तान के वोटरो ने उस समय करके दिखाया और जिस तरह से प्रैस के अनुमानों को गलत किया था, उन हालात में प्रैस को चाहिए था कि अपनी पत्रकारिता के लिए उन देहातमें जाते जहां हिन्दुस्तान के 85 प्रति 100 वोटर रहते हैं। पत्रकार गावों की गलियों तक जाएं, भाहरों की गलियों तक जाएं और जो असली बात हो वही अपने अखबार में लिखें। जो अनुमान वे लगाए उसमें सार्थकता आए। अगर हिन्दुस्तान के वोटरो ने उनका अनुमान गलत किया है तो उन्हें आत्म चिन्तन करना चाहिए न कि किसी राज नेता के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ आक्षेप करके ये हमला कर दें। सभापति महोदय,

बदलाव की बात है, हिन्दुस्तान की जनता ने दे 1 में पहला बदलाव 1977 में लाया। इस बदलाव के पिछे जो बहुत बड़ी भाखिसयत या सिप्रट काम कर रही थी वह हमारे नेता जय प्रका 1 नारायण जी थे। उन्होने सारे दे 1 को एक नई दि 11 दी थी जिसका नतीजा 1977 में राजनैतिक बदलाव था। उसके बाद हिन्दुस्तान में दूसरा राजनैतिक बदलाव लाने में सबसे बड़ी भाखिसयत हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी थे जो आज हमारे उप-प्रधान मंत्री है। यह राजनैतिक बदलाव लाने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी रही है। चाहे आज कोई इस बात को माने या न माने लेकिन 1987 में हरियाणा के लोगो ने गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट कायम की और चौधरी देवी लाल ने इस गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हुए लोगो के कल्याण के लिए अनेको कार्य किए जिन्हे हरियाणा के लोगो ने भोगा। इन कार्यों की चर्चा सारे हिन्दुस्तान में हुई। उस समय हर राज्य में इस बात का उदाहरण दिया जाता था। जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने बुजुर्गों को पै 1 न दी उसी प्रकार से दूसरे राज्यों के बुजुर्गों भी यह कामना करते है कि उन्हे भी पै 1 न मिले। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक वर्ग को अपने खजाने से कुछ-न-कुछ हिस्सा जरूर दिया है। मैं इस बात को विस्तार पूर्वक नहीं दोहराउंगा लेकिन थोडा इ 11ारा जरूर करुंगा। चाहे बूढे हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हरिजन हो और चाहे बैकवर्ड क्लासिज हो समाज के सभी वर्गों को सभी प्रकार के लोगो को बकायदा इस बात का फायदा हुआ है और हरियाणा के खजाने से कुछ न कुछ सहायता मिली है जिसका नतीजा यह हुआ

कि हिन्दुस्तान में सैंटर लैवल पर और राज्यो के लैवल पर बदलाव हुआ और वह कांग्रेस जो लगातार आजादी के बाद राज्यो और केन्द्र पर भासन कर रही थी उसका सफाया हो गया। आज विपक्ष की सरकार, जनता दल की सरकार सैंटर में बनी है और भिन्न-भिन्न राज्यो में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकारे सत्ता में आई है। सभापति महोदय, मेरे आदरणीय साथी श्री राम बिलास जी अभी कह रहे थे कि बजट पर आईए लेकिन मैं उन्हे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामले भी बजट पर बोलते हुए इन्कलूड हो जाते है। खैर, अब मैं बजट पर ही बात करता हूँ। सभापति महोदय, आदरणीय गुप्ता जी ने 31.19 करोड रुपए के घाटे का बजट पे 1 किया है। डिवैल्लिंग इकौनोमी में घाटे का बजट पे 1 करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे अनुमान के मुताबिक जो हमारी आमदनी के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सिज है उनको इकटठा करके कार्य करे और घाटे को उन रिसोर्सिज से पूरा करें। इस घाटे को हम किस रुप में पूरा करेंगे यह बात बजट में देखी जाती है। सभापति महोदय, सब से पहली बात यह है। एक बात उन्होने यह भी बताया कि कर की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो। दूसरे उन्होने यह भी बताया कि नौन-प्लान बजट के खर्चे में भी किफायत करे। ये सभी बातें डेफिसिट बजट को पूरा करने की है। ये सराहनीय बाते है और गवर्नमेंट की कार्यकुशलता को बढ़ाती है।

श्री सभापति: अब आप वाइंड अप करें।

श्री आत्मा राम गोदारा: चेयरमैन साहब, अभी तो मैंने सब्जैक्टवाइज आना था लेकिन आपने तो पहले ही वारनिंग दे दी। अब मैं शिक्षा के मामले में कहना चाहूंगा। शिक्षा के मामले में जो नीति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है लेकिन इसमें अब बदलाव लाने की बात कही है। सबसे पहले तो यह बदलाव लाना है कि किताबों का जो बोझ है, उसका बोझ कम हो। बच्चों की किताबें कम की जाएं। इस प्रकार की शिक्षा लागू की जाए ताकि उनको किताबों का इतना बोझ न उठाना पड़े। छोटे छोटे बच्चों का वजन कम है और उनकी किताबों का वजन ज्यादा है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वे कम किताबों से पूरी शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक तो शिक्षा के मामले में खर्च कम होगा और बच्चे बोझ से बचेंगे। दूसरी बात हरियाणा में यह भी देखी गई है कि मैट्रिक का एग्जाम प्राइवेट दे सकते हैं लेकिन उसे नौवीं कक्षा किसी रिकोग्नाइज्ड स्कूल से पास करनी होगी। अगर वह नौवीं कक्षा किसी रिकोग्लाइज्ड स्कूल से पास नहीं करेगा तो वह मैट्रिक के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकेगा। हरियाणा सरकार को यह बात विशेष रूप से देखनी चाहिए। ऐसा होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में काफी रुकावट आयी है। हरियाणा सरकार शिक्षा के मामले में और विशेष रूप से महिलाओं के मामले में बहुत अग्रणीय है। इसलिए सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल रिकोग्नाइज्ड है, वे दुकानों की तरह चलते हैं। उनके वारे न्यारे हो गए हैं। इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे वे मनमाने ढंग से फीस लेते हैं। सारे

हरियाणा में ये रिकोगनाइज्ड स्कूल फीस के मामले में बहुत बड़ी लूट मचा रहे हैं। इस लूट को किसी न किसी रूप में बन्द किया जाए। जहां तक प्रौढ शिक्षा की बात है कि उसे सरकार ने बन्द कर दिया। यह बन्द ही होनी चाहिए थी क्योंकि यह प्रौढ शिक्षा नहीं बल्कि फौड शिक्षा है। सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम इसका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं।

अब मैं आपके द्वारा परिवहन विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हरियाणा का परिवहन विभाग बहुत ही प्रसिद्धिमान रहा है। इसकी सेवाएं बहुत अच्छी रही हैं लेकिन अब कमियां नजर आने लगी हैं क्योंकि हमारे यहां बसों की कमी है। बसों में जब लोग सफर करते हैं तो ठूस ठूस कर भरे होते हैं और बसों की छतों पर भी बैठ कर सफर करते हैं। इस बारे में सरकार को गौर करना चाहिए क्योंकि लोगों की सुरक्षा का मामला है। हमारे यहां बसों की कमी होने से ऐसी हालत हो रही है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि परिवहन विभाग का बजट बढ़ायें ताकि वे बसे खरीद सकें और लोगों को सुविधा हो सके।

सिंचाई के मामले में एस0 वाई0 एल0 तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। उसका पानी आने पर ही हरियाणा के लोगों को राहत मिलेगी। आज हरियाणा के लोगों के लिए खाले पक्की करने और मार्डनर्ज को पक्का करना भी बड़ा आवश्यक है। यह लोगों की बहुत बड़ी मांग है। जब हम अपने हल्को में जाते हैं तो किसानों की तरफ से बहुत बड़ी मांग हमारे सामने आती है। मैं यह

समझता हूँ कि सिंचाई के मामले में जो बजट प्रोविजन किया गया है, उसमें खाली को पक्का करने और माईनर्ज की ऐक्सटेंशन करने के बारे में मदद में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि किसानों की यह मांग पूरी की जा सके। ड्रेनेज के मामले में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं यह समझता हूँ कि ड्रेनेज डिपार्टमेंट सारे साल भर कोई काम नहीं करता। जब फ्लड आते हैं तब वह हथियार उठाता है। उस वक्त हम ख्याल करते हैं कि ड्रेनेज के महकमे ने क्या किया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ड्रेनेज के महकमे में वह देखे कि फ्लड आने से पहले ही महकमा अपना कार्य समय पर करे ताकि लोगों को फ्लड के समय दिक्कत पें न आए। (घंटी) चेरमैन साहब, दो मिनट और दीजिए।

बिजली के मामले में हरियाणा ने बहुत ही प्रगतिशील काम किया है। इस सरकार के आने के बाद लगातार लोगों को बिजली मिलती रही है। किसानों को बिजली मिलती है लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि बिजली को प्रोडक्शन की जो कौस्ट आती है, वह थर्मल प्लांट के जरिए से जो बिजली प्रोड्यूस होती है, उसमें कौस्ट ज्यादा आती है। इसलिए हमारे इंजीनियर्स को और हमारे साइंटिस्ट्स को यह चाहिए कि थर्मल टेक्नोलोजी जो ओब्सोलीट हो चुकी है, इसको छोड़े या फिर बिजली की प्रोडक्शन की कौस्ट को किसी तरह से कम किया जाए, ऐसा कोई तरीका निकालें।

बहन सुशमा जी ने एक बात चौबीसी की पंचायत के बारे में कही और जिक्र किया। उन्होंने कुछ ऐसे भाब्द इस्तेमाल किए कि पंचायत की चीर हरण हुआ है और चौबीसी की परम्परा धूमिल हुई है। मैं इस बात से थोड़ा सा अलग मत रखता हूं। (विघ्न) चौबीसी की पंचायत का चीर हरण कैसे हुआ और कैसे उसकी परम्परा धूमिल हुई है, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आयी। चौबीसी की पंचायत के वोटर्स ने इकट्ठे हो कर जो निर्णय दिया है, इस तरह से पंचायत का चीर हरण हुआ है या परम्परा धूमिल हुई है, ये भाब्द मैं ठीक नहीं समझता हूं। (घण्टी) चेयरमैन साहब मैं एक मिनट में ही खत्म कर रहा हूं।

श्री सभापति: बाकी डिपॉजिज आप गुप्ता जी को वैसे ही बता देना।

श्री आत्मा राम गोदारा: बहुत अच्छा जी। धन्यवाद।

श्री कैला । चन्द भार्मा (नारनौल): सभापति जी, श्रीमान् गुप्ता जी ने कल जो बजट रखा है, वह बदली हुई परिस्थितियों में यह बजट रखा है। सौभाग्य से केन्द्र में भी ऐसी सरकार है और प्रदेश में भी ऐसी सरकार है जो लोगों की भावनाओं से भली प्रकार से परिचित है। सबसे पहले मैं गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इनहोंने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर रहित बजट प्रस्तुत किया है। सौभाग्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना का भी आरम्भ इसी वर्ष से हो रहा है।

पिछली सरकार ने भायद हिन्दुस्तान का मतलब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को ले रखा था, हिन्दुस्तान के गावों के बारे में कोई बात नहीं होती थी, कोई विचार नहीं होता था। इस सरकार ने पहली बार यह बात रखी है और कहा है कि हम हरियाणा के हर गांव में पानी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। डेट भी फिक्स की है। यह अच्छी बात है लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी से एक बात कहना चाहता हूं कि उसमें ढाणियो का जिक्र नहीं है। हरियाणा में काफी ढाणियां हैं जो वास्तव में गांव ही हैं। जब हम गावों के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं तो हमें ढाणियो को भी शामिल करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ढाणियो में भी पानी सप्लाई करेंगे। सभापति महोदय, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है और इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता।

सभापति जी, हम हरियाणा के सब विधायक आज इस स्थान पर जिस बात को लेकर बड़े चिन्तित बैठे हैं वह है एस0 वाई0 एल0 नहर की। हमारे नेताओं ने इस बारे में बड़ा भारी संघर्ष किया था। आज तक हम कहते रहे कि पंजाब में एस0 वाई0 एल0 नहर का जो हिस्सा है वह केन्द्रीय सरकार नहीं बनने देती लेकिन सौभाग्य से आज दिल्ली में हमारी अपनी सरकार बैठी हुई है जिसमें चौधरी देवी लाल जी उप प्रधान मंत्री के पद पर सु गोभित हैं। अब समय आ गया है कि इस नहर का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब हमारे पास जनता को कहने के

लिए कुछ नहीं रह गया है। पहले तो जनता से हम कहते थे कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार है वह नहर बनने नहीं देती या पंजाब वाले नहीं बनने देते। मेरा कहना यह है कि आने वाले समय में एस० वाई० एल० नहर निश्चित रूप से बनकर तैयार होनी चाहिए। इस समय पंजाब में अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार का ही राज है इसलिए एस० वाई० एल० नहर को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इस नहर के साथ हरियाणा के आम आदमी के जीवन में सुधार आएगा और हरियाणा की तरक्की होगी। सभापति जी, मैं तो ह कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिए हरियाणा के एक विशेष मंत्री की ड्यूटी लगाई जाए जो इस नहर की दिन प्रतिदिन की प्रगति का ध्यान रखे और अगर कहीं किसी स्थान पर कोई रुकावट आती है तो केन्द्रीय सरकार से मिलकर उसको दूर करवाए। मैं अपनी इस बात को फिर दोहराता हूँ कि एक व्यक्ति विशेष के जिम्मे यह काम लगाना चाहिए। तभी यह काम पूरा हो सकता है।

सभापति जी, इस नए बजट में आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा के तीस हजार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का लक्ष्य रखा है। यह सराहनीय कदम है। भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है। सभापति जी, इसके साथ ही साथ मैंने दूसरा पहलू भी देखा और मुझे बात समझ नहीं आई। कुछ साथियों ने कहा कि प्रौढ शिक्षा बन्द कर दी गई है, यह अच्छा हुआ। सभापति जी, एक ओर तो हम बेरोजगार नौजवानों को

भत्ता दे रहे हैं और दूसरी ओर इसके उल्टा हो रहा है यानि जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है, उनसे रोजगार छिना जा रहा है। हमार उददे य रोजगार देने का है, रोजगार छिनने का नहीं है अभी पिछले दिनो से काफी नौजवानो को निकाल दिया गया। सभापति जी, एक और अजीब बात हुई कि एस० वाई० एल० बोर्ड द्वारा पांच हजार क्लर्कस का सिलैकान हुआ। उसमें से दो हजार के करीब नौजवानो को चिट्ठियां भेजी गईं। वे उन लैटर्ज को लेकर घुम रहे हैं। जब डिपार्टमेंट मे जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारा नम्बर यहां नहीं आया या उनको कह दिया जाता है कि वहां कोई वैकेन्सी नहीं है। वे नौजवान हताश होकर घुम रहे हैं। कहा जाता है कि फाइनेंशियल कमिशनर से कोई चिट्ठी हू हुई है कि वैकेन्सीज को फिल अप करने पर बैन लगा दिया है। सभापति जी, वास्तव में एस० वाई० एल० बोर्ड हरियाणा में एक मजाक बनकर रह गया है। बडी मुश्किल से तो आज नौकरी का नम्बर आतर है और उसके बाद लोगो को, हमारे नौजवानो को परेशानी उठानी पडती है। प्रौढ शिक्षा मे जो हमारे नौजवान लगे हुए थे और जिनको हटाया गया है उनकी संख्या पांच हजार है। जिन्होने ग्यारह-ग्यारह साल तक नौकरी की उनको हटा दिया गया, यह ठीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण सारा गुस्सा इन नौजवानो पर नहीं निकलना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर उनमे कोई मैट्रिक है, कोई बी० ए० है तो कोई एम० ए० बी० एड० है तो इनको उनकी योग्यता के आधार पर कहीं न कहीं काम देना

चाहिए। अगर हमारे ये नौजवान खुलकर सामने आ जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एक भायन ने कहा है—

मन की हवि । तन को गुनाहगार बना देती है

और बाग के बाग को बीमार बना देती है।

ऐ भुखो को दे । भक्ति सिखाने वालो,

भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।

इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन निकाले हुए नौजवानो को योग्यता के अनुसार किसी न किसी विभाग में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही हमारे हित में है।

सभापति जी, आज प्र नोत्तर काल में एक पोस्टर के मामले में चर्चा हुई थी ओर मैंने उस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उसको ला एण्ड आर्डर का मामला बताकर रिजैक्ट कर दिया। सभापति जी, प्र न वास्तव में कानून और व्यवस्था का नहीं है, प्र न विचारधारा का है। जिस समय पहली बार पंजाब में खालिस्तान का नारा लगाया गया था उस समय इस बात को किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया था। अगर उस समय इस बात को गम्भीरता से लिया होता तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। आज यहां हमारे हरियाणा में एक वि ेश पोस्टर छापा गया जो अच्छी बात नहीं है। अगर हरियाणा में किसी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आते हैं तो यह प्रदे । के

लिए और इस दे 1 के लिए ठीक बात नहीं है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर हम आरम्भ में खालिस्तान के नारे को गम्भीरता से लेते तो आज ये खतरनाक हालात न होते। इसलिए हरियाणा में हुई इस घटना को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। सभापति जी, प्र न काल में बताया गया कि प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और प्रताप सिंह चौधरी अभी फरार है, मिला नहीं है। सभापति जी, हम सब लोग जानते हैं कि धारा 107/151 में अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती तो उस धारा के तहत उसके नातेदार, रि तेदार या भाईबंध को थाने में बुलाकर बैठाया जा सकता है। वह अभी तक मिला नहीं है। आखि रवह कहां चला गया। अगर पुलिस ने को 11 की होती तो वह अव य पकडा जाता। इसके अलावा एक जिम्मेवार व्यक्ति का नाम भी आदरणीय गृह मंत्री महोदय ने लिया है। सभापति महोदय, अगर इस प्रकार का जिम्मेवार व्यक्ति ऐसी धिनौनी हरकत करे तो उसको समाज के सामने जरूर नंगा किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जोकि अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, वोटों की राजनीति के लिए तथा हर बात को वोट से जोड़ने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलती चाहिए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लें।

सभापति महोदय, अभी बहज सुशमा स्वराज जी ने डिजनीलैंड की बात कही। आज यह विशय हरियाणा में हर किसान

के लिए चिंता का है। यद्यपि इससे प्रभावित होने वाले गुडगांव जिले के किसान ही हैं लेकिन कहीं भी आप चले जाओ, सारे हरियाणा में डिजनीलैंड की चर्चा जोरो पर हो रही है। डिजनीलैंड के बारे में बताया गया कि अमेरिका की तरह इसे यहां बनाया जाएगा। लेकिन भारत आज आर्थिक तौर पर अमेरिका जैसा सम्पन्न नहीं है। फिर भी यदि भारत में इसकी आवृत्ति महसूस की गयी है तो आवृत्तिनुसार जितनी जमीन चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए लेकिन यहां तो जरूरत से ज्यादा जमीन एक्वायर की जा रही है। ऐसा करके हम किसानों के साथ ज्यादाती कर रहे हैं। आज जो जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं वह 10 साल के बाद डिजनीलैंड बनेगा। उस समय आप अंदाजा लगाएं कि उस जमीन की किमत क्या होगी? आज गुडगांव के आस पास की जमीन का मुल्या क्या है? सभापति जी, अगर आज वहां के जमींदार की जमीन का आंकलन किया जाए और एक्वायर की गयी जमीन का ईमानदारी से 10 प्रतिशत हिस्सा भी किसान को दे दिया जाए तो भी किसान खुश रहेगा लेकिन वह भी उसे नहीं मिलता है। किसान की जमीन एक्वायर कर ली जाती है और उसको इस बारे में बताया भी नहीं जाता। कोई उस जमीन की रजिस्ट्री करवा रहा है, कोई किसानों की जमीन के प्लॉट काट रहा है लेकिन उस बेचारे किसान को कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं क्योंकि किसानों के साथ ज्यादाती होती है। यह एक बड़ा ही अहम मुसला है इसमें सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र में सरकारें जनता की भावनाओं के अनुकूल चलती हैं और

अगर जनता की भावनाओं के अनुकूल सरकार न चले तो इससे कई तरह की कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। इस लिए सरकार को जनता को वि वास में लेकर ही चलना चाहिए। सभापति महोदय, यह सरकार तो वैसे भी किसानों की सरकार है। सदा किसानों के हितों की ही बात करती है। आज 28 हजार एकड़ के करीब जमीन ऐक्वायर की जा रही है और वह भी केवल मौज मस्ती का अड्डा बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछेक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लखपति व करोड़पति बनाने के लिए, कुछ लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। यह बड़ी ही गलत बात होगी, बड़ी ही भ्रम की बात होगी। इसलिए मेरा सरकार से बार बार निवेदन है कि इस विषय पर दोबारा गम्भीरता से विचार किया जाए कि इस के परिणाम क्या हो सकते हैं।

सभापति महोदय, हैफड हरियाणा के अन्दर कई मिलज रन कर रही है। महेन्द्रगढ़ और उसे आसपास का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरसौ बहुत पैदा होती है। और उस सरसो में तेल की मात्रा पूरे प्रदेश के मुकाबले अधिक होती है। इसलिए इस प्रकार की मिल नारनोल के क्षेत्र में भी लगती चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय जब नारनौल में गए थे तो जनता ने उनके सामने कई प्रकार की मांगें रखी थी जिसमें एक यह मांग भी थी और उन्होंने जनता को इस बात का आ वासन भी दिया था। अगर इस तरह की मिल यहां पर लगाई जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही इसके साथ साथ किसानों को भी उनकी उपज का उचित भाव

मिलेगा। आज हमें सरसौ बेचने के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है। सरसो ले जाकर मंडियों में डाल दी जाती है और महीने बाद किसानों को उसका मूल्य मिलता है। यदि उस इलाके में इस तरह की मिल लगा दी जाएगी तो मैं विवास के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा वहीं उस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हैफेड को भी इससे लाभ होगा। किसान को उसकी जिन्स का सही ओर उचित दाम मिलेगा क्योंकि इस जिले में सरसों के तेल की मात्रा सारे हरियाणा से अधिक है।

सभापति महोदय, एन० सी० डी० सी०-४ परियोजना के अन्तर्गत अनेक कृषि आधारित यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत कुछ पिछड़े इलाकों में रोजगार दिलाने व कृषि पर आधारित छोटे उद्योग लगाने की बात इस बजट भाषण में कही गयी है। मैं प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार के लघु उद्योग महेन्द्रगढ़ जिले में भी लगाए जाएं जोकि वाकई में पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ एक भी ऐसा लघु उद्योग नहीं है जिसकी लागत एक करोड़ के लगभग हो। छोटे मोटे उद्योग जो थे, वे रिवाड़ी में चले गए हैं। इसलिए दन एन० सी० डी० ओ०-३ स्कीम के अन्तर्गत महेन्द्रगढ़ जिले में भी कोई न कोई उद्योग जरूर स्थापित किया जाना चाहिए।

सभापति जी, एक सब से बड़ी बात आज कल हमारी सरकार के लोग कहते हैं वह यह है कि भाहरों के लोग हमसे

नाराज क्यों है? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि पिछले अठाई साल में इस सरकार ने बहुत ही लोक-भलाई के काम किए हैं, इसमें कोई भाक नहीं है। परंतु भाहरो की भी उपेक्षा हुई है, यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं है। भाहरो का विकास नगरपालिकाओं की जो आर्थिक स्थिति है उससे नहीं हो सकता। आज कई नगरपालिकाएँ ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन भी इकट्ठा नहीं कर सकती। बढ़े हुए वेतन और बोनस की जब बात आती है तो वह वह भी नहीं दे सकती विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए बजट के अंदर आपने जो पैसा रखा है उस पैसे का वितरण भी ऐसे ढंग से होना चाहिए कि जो नगरपालिकाएँ पिछड़ी हुई हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाए। नारनौल कहने को तो भाहर है लेकिन वह एक पिछड़ा हुआ कस्बा है जहाँ की गलियों और सड़कों की बहुत दुर्दशा है। मानो पिछले अनेक वर्षों में वहाँ एक पैसा भी नहीं लगाया गया। इसलिए जब तक हम इन भाहरो के अन्दर सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी। आज जिस हिसाब से भाहरो में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से वहाँ सीवरेज की व्यवस्था बहुत जरूरी है। इस लिए लिए मेरा सुझाव है कि एक सीवरेज बोर्ड भी बनाया जाए और उसके लिए अब य पैसा रखा जाए।

सभापति जी, आज सारा हरियाणा जिस विषय से जुड़ा हुआ है वह मेहम उपचुनाव का है। हम सब लोग प्रजातंत्र के

कारण यहां बैठे हैं। लोगों के पास चूंकि वोट डालने का अधिकार था इसलिए हम यहां बैठे हैं। अगर लोगों के पास वोट डालने का अधिकार न होता तो मेरे जैसे साधारण परिवार के लोग इस महान सदन में न आते बल्कि कोई गुंडे बदमाश आते या कोई राजे महाराजे आते। आज हरियाणा में एक उप चुनाव के कारण से मतदाताओं में एक भय पैदा हो गया है, भांका पैदा हुई है कि हमारे मताधिकार को छिनने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार के मामले को लेकर मेरे कुछ साथी मित्र अभी समाचार पत्रों पर आरोप लगा रहे थे। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों के अनुमान में कभी गलती नहीं रही है। अगर हमको ध्यान है तो अक्टूबर 1989 का इंडिया टुडे देखें। उसने हिन्दुस्तान की जनता को अनुमान लगाकर बताया था कि लोक सभा चुनाव में कांग्रेस की 194 सीटें आएंगी। जब नतीजा सामने आया तो 91 प्रतिशत अनुमान सही पाया गया। जब पत्रकार और प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा खम्भा कहा गया है तो अगर हमारे किसी काम की वे आलोचना करते हैं तो हमें उसके बारे में आत्म निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई एक अखबार आलोचना करता है तो कोई बात नहीं लेकिन जब सारा प्रेस सारे अखबार आलोचना कर एक ही बात कहते हैं तो अखबारों पर दोशारोपण करने की बजाय हमको आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर कारण क्या हो गया। यह वही प्रेस है जो दो साल पहले हमारे चित्र छापा करता था, हमारी न्यूज लाया करता था। आज क्या कारण हो गया। कहीं हमारी टैकलिंग में तो गलती नहीं। कहीं हम उनको टैकल करने

में गलती तो नहीं कर गए या कहीं हमारी कार्यशैली तो दोषपूर्ण नहीं है। सभापति जी, इस पर चिंता करनी चाहिए और मेहम के विषय में जो चारों तरफ भांका व्यापक है उसको दूर करना चाहिए क्योंकि पंजातंत्र में कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हुआ करता, कोई पार्टी देना से बड़ी नहीं हुआ करती। अगर आवयक हा तो आदमी को पार्टी के लिए त्याग करना चाहिए और पार्टी को देना के लिए त्याग करना चाहिए। इस प्रकार यदि त्याग से समाज का विकास पैदा होता है, जनता का विकास पैदा होता है तो उस विकास के लिए त्याग करना चाहिए और जनता के टूटे विकास को दोबारा जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपूर): सभापति महोदय, माननीय गुप्ता जी ने कल हाउस में जो बजट भाषण दिया है उस पर चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, चाहे गवर्नर ऐड्रेस हो और फिर उसके बाद चाहे बजट हो वह सरकार की विकाश नीति व योजनाओं को प्रतिबिम्ब होता है। सवेरे से हुई बहस और बजट की समीक्षा से एक धारणा तो बिल्कुल मजबूत होती है। कुछेक साथियों को एक दो के सिवाए चाहे वे सत्ता पक्ष के मੈम्बर हैं चाहे विपक्ष के हैं, विपक्ष को तो भाषण अभी बोलने का मौका ही नहीं मिला है। जिन्होंने बजट को बार बार सराहा है उनको यदि मैं बजट की बेगानी कहुँ तो गलत नहीं होगा। अप्रत्यक्ष रूप से सभापति महोदय, इस बजट को कोई विकासमूलक बजट नहीं

मान सकता। अगर इस बजट को नीरस बजट कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा।(गोर)

एक आवाज: आप कौन से रस की बात करते हो?(गोर)

चोधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: वह रस तो आपने छोडा ही नहीं। अब तो आपने खुन पीने का सिलसिला भुरु कर दिया है बल्कि उससे भी आगे निकल गए हो (गोर एवं विघ्न) मैं वही कह रहा हूं। अब तो आपने पब्लिक को भी पीसना भुरु कर दिया है। कृपा करके उससे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता के हाथों में तो बहुत बडी भाक्ति है उससे टकराना अच्छा नहीं है। (गोर एवं विघ्न) यह कहानी बहुत पुरानी है। इसमें कोई सार नहीं है और न मैंने वहां पर कोई पाजामा छोडा है और न कोई कपडा छोडा है और न ही मैं पाईपो पर चढा हूं। (गोर) सभापति महोदय, माननीय सदस्य मुझे बीच बीच में टोका-टोकी करते है अगर आप इन्हे ऐसा न करने की हिदायत दे दे तो ज्यादा उपयुक्त होगा (विघ्न)

Mr. Chairman: No interruption please.

श्री राम बिलास भार्मा: सभापति महोदय, मैं रिकार्ड को ठीक करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। यहां जो कपडों की बात चली है उसके बारे में निवेदन है कि तेजाखेडा में मैं चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहजी के साथ था और मेरे पास जो अटैची थी

उसमे मैने इनके कपडे रखे थे। यह बात फ़ैक्ट है कि ये तेजाखेडा में हमारे साथ थे और वहां पर ये अपने कपडे छोड कर आए थे।
(विघ्न)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, वैसे मुझे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि पता नहीं राम बिलास जी को हाउस में * * * बोलने में मजा आता है या यह इनकी आदत हो गई है। इस आदत को मैं जान चूका हूं इसके अलावा मैं क्या कहूं। (गोर)

डा० मंगल सैन: सभापति महोदय, सदन की मर्यादा का तकाजा है ठीक है इन्होंने दल बदला, कपडे तेजाखेडा में छोड आए, जूते छोड आए, पल्ली छोड आ लेकिन जो * * * भाब्द है यह अनपार्लियामेंटरी है इसको ऐक्सपंज कर दिया जाए।

श्री सभापति: यह भाब्द ऐक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, रसो की बात तो हमारे सीनियर मैम्बर डाक्टर साहब और गुप्ता जी ही बता सकते हैं। मुझे तो कोई रस लगा भी नहीं है। सभापति जी **** भाब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि राम बिलास जी ने निराधार और बेबुनियाद बात की है। मैंने वहां पर कोई कपडा नहीं छोडा। जहां तक दल बदलने की बात है उसके बारे मे मैं कह देता हूं कि क्योंकि यह बात यहां आई है (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: सभापति महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि भाई महेन्द्र प्रताप सिंह जी एक ऐसे योग्य व्यक्ति चौधरी नेत राम जी के सुपुत्र है जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और जिन्होंने जनसंघ के टिकट पर चुनाव लडा था। इसलिए हमें इनसे ममता है। महेन्द्र प्रताप सिंह जी मेवला महाराजपूर सीट से लोकदल की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। यह रिकार्ड की बात है और ये फ़ैक्ट है।

श्री सभापति: आप कृप्या बैठें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति जी, आपको मुझे बोलने के लिए टाईम बढा कर देना पडेगा क्योकि ये बीच में टोका टाकी कर रहे है। आप जानते है और इसमें कोई दो राय नही है कि एक बार मै इन भाईयो के सहयोग से भी चुनाव जीतकर आया था। इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता। आप यह भी अच्छी तरह से जानते है कि उस समय मैने इनकी इज्जत को बढाया था। उस समय जब जनता दल और लोक दल पार्टी लेट गई थे मुझे इलैकान लडना पडा था क्योकि मुझे टिकट नही दिया गया था? मुझे इन्होन स्पोर्ट दी थी और मै 1977 मे जनता दल के मुकाबले में 250 वोटो से पिछडा था इनडिपेंडेंट कैंडीडेट की हैसियत से। उसके बाद हालांकि कांग्रेस वेव थी फिर भी इनके सहयोग से मै तकरीबन 24 हजार वोटो से चुनाव जीता था। उसके लिए मै इनका धन्यवाद करता हूं। फिर कांग्रेस ने मुझे चुनाव लडने के लिए टिकट दिया। उस समय हालांकि इनकी हवा

थी लेकिन इनके कैंडिडेट को मैं 20 हजार वोटों से हराकर हाउस में आया हूँ। अब इस बात का अन्दाजा यह खुद लगा ले कि वह दोनों बार जनता की जीत थी या नहीं। मैं तो उसे जनता की जीत कहता हूँ। यह दल बदल नहीं है, जनहित में या जन विकास के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वह जनता के लिए किया है और यह जनता ने मुझे अपने तौर पर जीता कर भेजा था। इस बात की सफाई कई बार दी जा चुकी है। इससे ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है। दोनों बार जनता ने मुझे अपने बलबुते पर जीता कर भेजा है। (विघ्न)

प्र० सम्पत सिंह: क्या ये जनहित मोर्चा में जाएंगे?
(विघ्न)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं आपको राय दे सकता हूँ कि आप अपने गुनाहों पर पश्चाताप कर लें। (विघ्न)

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, ये जनहित की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये जनहित मोर्चे में चले गए हैं तो क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब डिफ़ैक्ट इन आफ ला के तहत कोई सदस्य दूसरी पार्टी में तभी जा सकता है जब वह पहली पार्टी से इस्तीफा दे दे।
(विघ्न)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जनता ने अपने वोटों से चुनकर यहाँ भेजा है। (गोर एवं विघ्न) इसमें आपकी पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है। (विघ्न)

समाज कल्याण मंत्री (श्री जगन नाथ): चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं इनको सलाह देता हूँ कि ये न तो जनतदल में शामिल हो और न ही बी.0 जे0 पी0 में शामिल हो बल्कि इनको और जनहित वालों को मिल कर कोई एक अनहोनी पार्टी बना लेनी चाहिए।(विघ्न)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: जगन नाथजी ऐसी कल्पना तो आप ही कर सकते हैं। लेकिन ई वर का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कम से कम आपतो ऐसी बात न कीजिए। आप अनहोनी के चक्कर में न पड़ें।

श्री सभापति: महेन्द्र प्रताप जी आप इनकी बातों की तरफ ध्यान न देते हुए बजट पर ही बोले।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं तो बजट पर ही बोलना चाहता हूँ लेकिन ये बोलने ही नहीं देते। चेयरमैन साहब, जो सही बात होगी मैं उसका समर्थन भी करूँगा। मैं बहन जी की बातों को दोहराना नहीं चाहता। इस समय वहाँ पर प्रदेश की जनता भी बैठी हुई है और हमारे दूसरे साथीगण भी बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब, जैसा मैं कह रहा था कि किसी भी सरकार का मुख्य काम अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करना और उनके लिए विकास

पाए जो कि 1986-87 में कांग्रेस सरकार ने 525 करोड़ रुपए का रखा था। योजनागत बजट को बढ़ाना विकास गील सरकार की नीति होती है। सरकार अपने साधनों से बजट को बढ़ाती है लेकिन उसी बजट को घटाया नहीं जा सकता इसलिए हमने उसे बढ़ाकर अधिक किया। श्री गुप्ता जी ने 1990-91 के वित्त वर्ष के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वह दो साल के बाद भी कांग्रेस बजट के बराबर बजट पे ा नहीं कर पाए। इनके विकास दस के हिसाब से तीन साल में तो 850 करोड़ रुपए कम से कम बजट में प्रोविजन होना चाहिए था। यह विकास गील बजट हुआ या पीछे लौटने वाला विकास रोको बजट हुआ। इस बजट से सरकार की नीतियों की झलक मिलती है। इस बजट को तो किसी भी मायने में विकास गील बजट नहीं कहा जा सकता।(विघ्न) सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा है कि 70 प्रति ात बजट ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लगाया जाएगा। मेरे माननीय साथी, जिनका नाम मुझे याद नहीं, ने कहा था कि कांग्रेस भासन काल में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पता नहीं ये माननीय साथी किस कारण से ऐसा कह रहे थे। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस के भासन में हरियाणा की पूरी तरक्की हुई है। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा दे ा में 11वे नम्बर पर था। मेरे यह साथी भायद भूल गए है कि कांग्रेस भासन काल के दौरान ही हरियाणा दे ा में दूसरे नम्बर पर आया। इनके 3 साल के भासन के बाद भी अभी वह दूसरे नम्बर पर ही है जिसका श्रेय मूलरूप से कांग्रेस

को जाता हैं कांग्रेस की विकास नील नीतियो को दे । का बच्चा-बच्चा जानता है ओर विकास के मामले में हमारा आदर्श रहा है । कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री चौधरी बंसी लाल ओर उसके बाद आने वाले मुख्य मंत्रियों की ही देन कहा जा सकता है कि आज हरियाणा दे । मे दूसरे नमबर पर है । (विघ्न)

श्री जगन नाथ: * * * * *

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, चौधरी बंसी लाल के प्रति भाब्दो का इस्तेमाल कम से कम जगन नाथ को तो नहीं करना चाहिए । (विघ्न) मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इनकी बात को रिकार्ड पर न लाया जाए और इन्हे बैठने की हिदायत दी जाए ।

श्री सभापति: यह बात रिकार्ड न की जाए । जगन नाथ जी आप बैठें ।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनके प्रति इन्हे ऐसे भाब्दो का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

श्री सभापति: मैंने इनकी बात को रिकार्ड पर न लाने के लिए कह दिया है ।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: जगन नाथजी, आपका तो नहीं ही जगन नाथ है, कम से कम आप अपने नाम की भावना का

तो ध्यान रखे।(विघ्न) सभापति महोदय, बजट में 70 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खर्च करने का जिक्र आया है। अगर हम वर्ष 1987-88 के बजट पर थोड़ी सी दुश्टी डालें तो कृषि, बिजली और सिंचाई के लिए 357 जमा 61 यानी 400 करोड़ रुपये के लगभग राशि की व्यवस्था कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। 400 करोड़ रुपये टोटल बजट यानी 585 करोड़ रुपये का कितना परसेंट बनाता है यह मंत्री महोदय स्वयं ही निकाल सकते हैं। यह लगभग 68-69 परसेंट के करीब पड़ेगा। उसके बराबर भी ये चार साल में नहीं कर पाए। यदि पिछले साल 1989-90 की फीगर्ज को कम्पेयर किया जाये तो इनहोंने जो 17 परसेंट की बढ़ौतरी दिखायी है वह चार परसेंट से ज्यादा नहीं बैठती। इन्होंने गलत आंकड़े लगाए हैं। पहले तो बजट में बढ़ा कर आंकड़े दिखा दिये और फिर बाद में कह दिया कि हम साधन नहीं जुटा पाये, यह हो गया वह हो गया। फिर उसको कम कर दिया। लोगों को खुश करने के लिए कह दिया कि हमारी बड़ी विकास नीतियां हैं और हरियाणा का विकास करना चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। (विघ्न)

एक मੈम्बर: इस सरकार के आने के बाद विकास तो हुआ ही है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: यह तो आप ही लोग कह रहे हो। हम तो हाउस में कोई सवाल उठाते हैं तो उनको साईड ट्रेक कर दिया जाता है। मंत्री महोदय जब आपकी यही हालात है

तो हमें कोई अफसोस नहीं है। सभापति महोदय, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। (विघ्न)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): आपते तो इस सै। न में कोई प्र न ही नहीं दिया, फिर आपके सवाल को साइड ट्रैक कैसे कर दिया।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, मैंने काल अटैन्। न मो। न दी है, ऐडजर्नमेंट मो। न दिया है। ये सब रिकार्ड की बातें हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: सभापति महोदय, इस विषय में मैं एक निवेदन करता चाहता हूँ। कालिंग-अटैन्। न मो। न के नोटिस का फैसला करना चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका प्र न आया हो और उसका उपयुक्त उत्तर न मिला हो तो आप हम से ि। कायत कर सकते हैं। जब आपका कोई प्र न ही नहीं है तो हम किस बात का जवाब दें?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: गुप्ता जी, मैंने सप्लीमेंटरी किये हैं। जहां तक चेयरमैन साहब के फैसले का ताल्लुक है उस बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। हम चेयरमैन साहब की इज्जत करते हैं और चेयरमैन साहब का चाहे जो फैसला हो वह हम मानते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। सभापति महोदय, इस सै ान के दौरान क्वै चन कम इसलिए आये कि हमें 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। केवल पांच दिन का नोटिस दिया गया था। इसलिए क्वै चन नहीं भेज सके।

श्री सभापति: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अब आप 15 दिन की बात नहीं कह सकते। समय वाली बात तो छूट दे कर के स्पीकर साहब ने कवर कर दी है। इस तारीख तक आए सारे प्र न स्वीकार कर लिए गये है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: इन बातों का जवाब आप दे देंगे तब पता लगेगा और जवाब तो आप दे ही देंगे क्योंकि जवाब देने और बचाव के आप बड़े माहिर है क्योंकि आपने बडा लम्बा रास्ता कांग्रेस के समय से आज तक का तय किया है।

श्री सभापति: महेन्द्र प्रताप सिंह जी, सारे क्वै चन टाईम लिमिट वैव करके ऐडमिट कर लिए गये है। इसलिए आप क्वै चन वाली बात न करके बजट तक ही कनफाइन रहें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, जब बात आ जाती है तो उसका उत्तर तो देना जरूरी हो जाता है। मंत्री महोदय कह रहे थे कि कालिंग अटैन् ान मो ान का फैसला चेयरमैन साहब करती है। वह तो ठीक है वही करती है। हमें किस

किस्म का ऐतराज नहीं। जो फ़ैसला चेयर ने किया है उस पर हमें उंगली उठाने या उनकी बात पर किसी प्रकार आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं लेकिन सभापति जी कई बार दुख होता है। * * *

Dr. Mangal Sein: This is a reflection on the Chair, Sir,. This should no be on record.

श्री सभापति: यह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: जहां तक सभापति महोदय बाढ आने का सम्बंध है उस बारे में मैंने हाउस में दो बार कालिंग अटैन्शन मोशन भी दिये और सप्लीमेंटरी सवाल भी किये लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। मैंने श्री उदय भान के सवाल पर भी सप्लीमेंटरी किया लेकिन उस समय भी सरकार आवासन तो क्या जवाब भी नहीं दे सकी सरकार की अकर्मन्यता और ना-असलियत की बातें देखिए दो साल से लगातार जनता की शिकायत है, भार भाराबा है लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं किया जा रहा है। पहले साल बांध टूट गया, वह बांध तो टूटा पडा रहा लेकिन दूसरी बार वही बांध उस गांव के बराबर से फिर टूट गया। उस बांध के टूटने से तकरीबन दस हजार एकड जमीन खराब हो गई। उसका न लोगो को मुआवजा दिया गया और न ही किसी प्रकार की राहत दी गई। आज भी जगह जगह से वह बांध टूटा हुआ है। ये बातें सरकार की विकास नील नीतियों की भांभा बढा रही है।

श्री सभापति: आप एक दो मिनट में खत्म करिए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: ठीक है, एक दो मिनट का ही समय और दे दीजिए। मुझे इन्टरपॉज की वजह से बहुत देर तक इन लागो ने रोके रखा। मैं दो मिनट से फालतू समय नहीं लूंगा। (विघ्न)हमारी पार्टी से केवल एक आदमी बोला है लेकिन उसको भी समय न दिया जाये तो हम कैसे अपनी बात कह पायेंगे।

श्री सभापति: आप कंक्लूड करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: देखिए सभापति महोदय, हम चार मैम्बर हैं। एक एक मैम्बर को आपने इतना समय दिया, इसलिए हमें भी उतना ही समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति: आपको भी इतना ही समय दिया है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, इन्होंने मुझे रोक दिया इसके कारण मेरा समय जाया हो गया।

श्री सभापति: आप एक मिनट में खत्म करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, दूसरी बात मोटे तौर पर यह है कि सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति विकास की होती है दूसरे उसके मान सम्मान और सुरक्षा की होती है। सरकार दोनो उद्देश्यों की दृष्टि से फेल हो चुकी है। मेहम मे प्रजातंत्र का कत्ल हुआ है जो प्रजातंत्र के इतिहास में एक ही मिसाल है। इसके लिए सरकार को प्रायश्चित्त व जनता के सामने

समर्पण करना ही होगा। सभापति महोदय, विकास के फ्रंट पर भी यह सरकार फेल है। इस बारे में कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुरक्षा का और प्रजातंत्र का सवाल है, वह आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अपने मन को खुला करने के लिए कुछ भी कह ले लेकिन इसका इन्हें प्रायश्चित्त व जनता के सामने समर्पण करना ही होगा।

श्री सभापति: अब आप बस कीजिए आप का टाइम खत्म हो गया है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सर अभी दो मिनट नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: आपने तो एक मिनट के लिए कहा था।
Please take your seat. Next Member, Shri Makhan Singh.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सर, मेरे दो मामले अभी कहने रह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए कहता हूँ कि जहां तक महम का ताल्लुक है गुप्ता जी ने सरकार को बड़ी खुबी से बचाने की कोशिश की है और गुप्ता जी तो ऐसे कामों में बड़े माहिर हैं। वे बड़े काबिल आदमी हैं। इन्होंने तो कांग्रेस भासन में और अब भी सब कुछ देखा है लेकिन गुप्ता जी, इस तरह से सरकार को नहीं बचाया जा सकता हैं।.....

Mr.Chairman: Now please take your seat. I have already called upon Shri Makhan Singh,. Let him speak. You will get other opportunities to speak.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: सर, मैं यह कहना चाहता हूँ
कि जैसे प्रैस के लिए * * * * *

Mr.Chairman: This will not be recorded. I have
already called upon the other Member. Please take your seat
and let him speak.

Chaudhri Mahender Partap Singh: * * * * *

Mr.Chairman: Nothing to be recorded which is said
without my permission.

Chaudhri Mahender Partap Singh: * * * * *

श्री सभापति: आपके साथियों को कहने का मौका
मिलेगा वह कह लेंगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह:* * * * *

श्री सभापति: आपको 26 मिनट का टाइम मिला है। मैंने
इनको भी रोका है। अब आप बैठिए। बहुत टाइम आपको मिला
है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मेरी पार्टी के तमाम सदस्य
अपना समय भी मुझे दे रहे हैं। अगर फिर भी आप मुझे समय नहीं
देते तो मुझे वाब आउट करना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह बहुत
गलत परम्परा है कि हमारे साथ हाउस में समय के मामले में भी
ज्यादती की जा रही है।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): चेयरमैन सर, जैसे इन्होंने कहा है कि इन्ट्रूप् एन्ज वगैरा होती रही है। लेकिन इनको यह भी तो पता होना चाहिए कि जग चेयरमैन कहते हैं कि आपका टाईम समाप्त हो गया है और कोई चीज रिकार्ड पर नहीं आएगी तो एक सदस्य को बैठ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कोई मैम्बर दस पन्द्रह मिनट तक बोलता रहे तो उसका मतलब क्या यह नहीं है कि वह हाउस का टाईम जाया करता है। रिकार्ड पर भी कोई बात आ नहीं रही है लेकिन फिर भी वह बोलता ही जा रहा है। यही 15 मिनट कोई दूसरा मैम्बर बोलता तो हाउस को कुछ फायदा होता।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: ये लोग बार बार मेरा समय नष्ट कर रहे हैं अगर फिर भी मुझे समय नहीं दिया जाता तो हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मोहम्मद असलम खा, और कैप्टल अजय सिंह यादव सहित सदन से वाक-आउट कर गये)।

वर्ष 1990-91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री किरपा राम पुनिया: चेयरमैन साहब, अगर प्रोसीडिंग्स इसी तरह से चलेगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो बोलते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता।

श्री सभापति: उनको (चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह) सफ़ि नैनट टाईम दिया गया है।

श्री किरपा राम पुनिया: चेयरमैन साहब, यह कोई उचित बात नहीं है। इस तरह से हाउस का काम नहीं चलेगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: टाईम लिमिटेड है और यह टाईम सब के लिए एक जैसा है। जितना उनका टाईम बनता था वह उनको दे दिया गया था।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): चेयरमैन सर, पुनिया साहब ने अभी कहा कि इंटरप् ांज हो रही है ओर इस तरह से काम नहीं चलेगा। लेकिन जब चेयरमैन बार बार कह दे कि टाईम समाप्त हो गया है और कोई बात रिकार्ड पर नहीं आएगी और फिर भी कोई मैम्बर 15 मिनट तक बोलता रहे तो उसका क्या फायदा है? जब कोई चीज रिकार्ड पर आनी ही नहीं है तो उनको खुद ही बैठ जाना चाहिए।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): सभापति महोदय, पुनिया जी ने जो यह बात कही वह बिल्कुल ठीक है इंटरप् ांज या भाोर भाराबा नहीं होना चाहिए। जब इधर से लोग बोल रहे थे तो सभापति जी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अत्री जी खडे होकर बीच में बोल रहे थे तब पुनिया साहब को कुछ नजर नहीं आया (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: पूनिय साहब, आप बैठिए। मक्खन सिंह जी आप भुरु करें।

श्री मक्खन सिंह (पुंडरी): सभापति जी, आपने मुझे बजट के बारे में बालने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है यह बजट लोगों की भावनाओं को जानते हुए बहुत अच्छा पेश किया है और इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सभापति जी वर्ष 1990-91 का बजट सात सौ करोड़ रुपए का बजट है जोकि चालू वर्ष के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है यह बहुत सराहनीय कार्य है। कर न लगाने का कारण यह है कि हरियाणा में बहुत ही प्रगति मिली काम हुए हैं और इसलिए अब किसी कर की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री औम प्रकाश चौटाला ने निर्णय लिया है कि हर गांव के अन्दर दिसम्बर, 1990 तक पीनेका पानी पहुंचा दिया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय काम है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने 108.70 करोड़ रुपए नहर व बाढ़ नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराए हैं। यह बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमें पानी की जरूरत है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कोई भी खाल ठीक नहीं करवाया था। जितने भी खाल खराब थे उनकी कांग्रेस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने भी हमारे इलाके में कोई

ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने केवल अपने क्षेत्र में ही काम किया। सभापति जी, मेरा जीरी का एरिया है इसलिए वहां पानी की बहुत जरूरत है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र के एरिया के अन्दर जितने भी खाल है उनको पक्का करने का काम शुरू किया जाए। मेरे हलके में चोरबठी से फरल मादनर जो मंजूर हुआ है उसको बनाया जाए। मेरे हलके में मोहना माईनर है जो पक्का है लेकिन उसकी लाइनिंग ठीक नहीं और इस कारण अगले गांव में पानी नहीं पहुंचता। मैं लगातार पिछले तीन साल तक प्रयास करता रहा हूं कि इस माईनर को ठीक कराया जाए लेकिन अभी तक वह ठीक नहीं किया गया है। सभापति जी, हमारा जीरी का एरिया है और अगर वहां पानी का प्रबन्ध बहुत अच्छा हुआ जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है।

सभापति जी, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। बिजली के मद में वर्ष 1990-91 के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1987 में चौधरी देवी लाल ने चौबीस घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था और आज तक चल रहा है। मेरे हलके में 132 केवी0 का कौल गांव में एक सब-स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, मेरी प्रार्थना है कि उसको जल्दी पूरा किया जाए। बिजली की ठीक सप्लाय होने ट्यूबवैल का काम ठीक हो जाएगा और पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। मेरी इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इसको जल्दी से पूरा किया जाए। जिससे कि लोगों को बिजली अधिक से अधिक मिल

सके। आजकल हर गांव को पूरी और चौबीस घंटे बिजली मिल रही है इससे ज्यादा सराहनीय काम ओर कोई नहीं हो सकता। जब कांग्रेस का भासन था तो लोगो को बिजली नहीं मिलती थी लेकिन आजकल वह बिजली घर है और वही बिजली है लेकिन लोगो को पूरी बिजली मिल रही है। पता नहीं अब वह बिजली कहां से आ गई ओर पहले क्यों नहीं थी। सभापति महोदय, चौधरी देवी लाल ने गन्ने का चालीस रुपए मूल्य देकर बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस भासन के अन्दर एक रुपए की बढौतरी को लेकर यमुनानगर में ऐजीटे ान किया गया था।

(इस समय सभापतियो की सूची की एक सदस्या, श्रीमती सुशमा स्वराज, पदासीन हुई)।

सभापति महोदय, उस समय गन्ने का मूल्य एक रुपया भी सरकार ने नहीं बढने दिया लेकिन चौधरी देवी लाल जी के आते ही किसान को उसका ड्यू हक मिला और उसके गन्ने की कीमत 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गयी जिससे मेहनतक ा किसान को काफी राहत महसूस हुई। इस वक्त हरियाणा के अंदर किसानो को गन्ने की सब से अधिक कीमत दी जाती है। इसके बावजूद भी भाहबाद भूगर मिल को दे ा में पहला और सोनीपत को तीसरा स्थान प्राप्त करके हमारा हरियाणा अग्रणी रहा है। मेरा अपनी सरकार से यह प्रार्थना हैकि जहां चौधरी देवी लाल जी के वक्त में गन्ने का मूल्य बढाया गया है वहां कैथल के भूगर मिल

की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए और उसे जल्दी ही चालू करवाया जाए।

इससे आगे मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए 800 रुपये प्रति माह या 30 रुपये 80 पैसे प्रतिदिन मजदूरी फिक्स कर दी है। कृषि क्षेत्र के लिए 31 रुपये 80 पैसे न्यूनतम मजदूरी हमारी सरकार ने निश्चित की है जोकि उत्तरी क्षेत्र में सब से अधिक है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। यह सरकार का एक बड़ा सराहनीय कदम है।

सभापति महोदया, अब मैं परिवहन तथा संचार व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने नई बसें खरीदने के लिए लगभग 40.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। नई बसें खरीदने के बाद कई नये रूट्स पर, जगह जगह पर, बसें चलाने का सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है, वह बड़ा ही सराहनीय है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और सरकार को आमदनी भी होगी। यह एक समय की मांग थी जोकि सरकार पूरी करने जा रही है इसके साथ साथ मेरी यह सरकार से रिक्वैस्ट है कि जब नई बसें आए तो उन में से कुछ बसें कैथल डिपो पर भी भेजी जाएं। वहां के लोगों की भी काफी देर से यह मांग चल रही है।

सभापति महोदया, इससे आगे मैं शिक्षा से सम्बंधित कुछ बातें कहना चाहूंगा अगले वर्ष 100 स्कूल प्राइमरी से मिडल

व 50 स्कूल मिडल से हाई में अपग्रेड करने का प्लान है जोकि बड़ा ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। इस तरह स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना आवश्यक था। मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हाबडी व साकरा गांव के स्कूलों को भी 10 जमा 2 में अप-ग्रेड किया जाए और बारना और जडौला हाई स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत करवाई जाए। उनकी हालत बहुत खस्ता है। यह डिमांड उस इलाके के लोगों की बहुत देर से है। इसके साथ साथ राजकीय प्राइमरी स्कूल कमोदा व धराडसी को मिडल स्कूल का दर्जा दिया जाए।

सभापति महोदया, हमारी सरकार ने जो बुढापा पेंशन स्कीम चलायी है वह अपने आप में ही एक बेजोड स्कीम है ओर पूरे राष्ट्र भर में इस स्कीम की बदौलत हरियाणा को एक विशेष स्थान मिला है।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनता की अंशदान की राशि को बढ़ाकर सरकार ने दो गुण कर दिया है। यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि सरकार ने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए कर्ज की राशि को एक लाख से बढ़ाकर अठ्ठाई लाख रुपये कर दिया है। कर्मचारियों को 27 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वह भी बहुत सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों में काफी खुशी की लहर आई है। जो टैक्स भी सरकार ने नहीं लगाया, यह भी एक बड़ा काम किया है।

सभापति महोदया, हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया बजट पे ा किया है। महेन्द्र प्रताप सिंह जी इसकी आलोचना कर रहे थे, उनको ऐसा करते हुए * * * * * आनी चाहिए थी। पहले जब भी कांग्रेस सरकार ने अपना बजट पे ा करना होता था तो लोग चिन्तित हो जाते थे। वे डरते थे कि कल को बजट पे ा होगा और चीजों के भाव और बढ़ जाएंगे। आज लोग खु ा है क्योंकि हमने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। सभापति महोदया, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री किरपा राम पुनिया (बडौदा—अनुसूचित जाति):

सभापति महोदया, आज सदन में 1990—91 के बजट पर चर्चा हो रही है। सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और अगले वर्ष में काम करने के प्रोग्राम को तो सामने रखा ही गया है लेकिन इसके साथ साथ उसके बारे में यह विचार विम र्ण करने की भी अति आवश्यकता है कि सरकार की कार्य प्रणाली या कार्य भौली कैसी है। क्योंकि बोलने के लिए समय की पाबन्दी लगी हुई है इसलिए मैं चन्द मुद्दों पर ही चर्चा करना उचित समझता हूँ। सब से पहले मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान के बारे में जिक करुंगा कि सरकार के काम करने की तरीका कैसा है, किस तरह से सरकारी म िनरी का उपयोग किया जाता है यह भी अर्ज करुंगा पिछले दिनों से मेहम के उप चुनाव के बारे में काफी चर्चा हो रही है। चारों तरफ वहा हुई घटनाओं का विराध किया गया। कालिंग अटैन् ान

मो इंज के जरिए, स्टार्ड क्वै चंज के जरिए यह मामला उठाया गया। अखबारो में भी इस बारे में काफी आया। मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह बहुत भार्मनाक घटना घटी है। वहां पर बहुत भारी हिंसा का नंगा नाच हुआ। वहां पर बहुत सारे नौजवान मारे गए। इस बात का फैसला तो सरकार द्वारा बैठाए गए आयोग से करना है कि उन घटनाओ के लिए कौन दोशी था लेकिन जैसे पता चला है कि किस तरह से इसकी भूमिका पहले ही बन चुकी थी वह निन्दनीय है। मुख्य मंत्री जी भायद इस बात के लिए मुझे क्षमा करेंगे और उत्तेजित नहीं होंगे। 1987 में विधान सभा के चुनाव होने के बाद यहां पर लोक दल और बी० जे० पी० की सरकार बनी उसको बाद ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया गया। उसके बाद जो भी उप चुनाव हुआ चाहे वह फतेहाबाद था, करनाल का था, तावडू का था या फरीदाबाद पार्लियामेंटरी कांस्टिचूएंसी का था, हर जगह िाकायत रही, अखबारो में भी और लोगो में भी कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। हरियाणा के भांती प्रिय लोगो ने 1987 के चुनावो के बाद पहली बार हिंसा का मुंह देखा। पहली बार 6 लोग मारे गये थे और बहुत सारे जखमी हुए थे। इन बातो को लेकर जब अखबारो में जिक्र आया तो उल्टा अखबार वालो को दोश दिया गया कि उन्होने इस तरह का माहौल पैदा किया। मुख्य मंत्री जी मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि प्रैस हमारी फोर्थ ऐस्टेट है और उनका यह काम है कि असलियत को लोगो के सामने रखे। हमने 1987 के चुनावो से पहले जब न्याय युद्ध भुरु किया था, उस

समय यही प्रैस वाले थे जिन्होंने चौधरी देवी लाल और हमारी पार्टी को सारे न्याय युद्ध में इतना भारी उंचा चढाया था। उसी का नतीजा था कि इतना भारी बहुमत हमारी पार्टी को मिला था। आज हरियाणा में एक बहुत गलत और भार्मनाक बात की गई है और उसके लिए प्रैस वालों को दोषी ठहराया जा रहा है। मैं प्रैस वालों को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने हर तरह की कठिनाई का सामना करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके सही जानकारी प्राप्त की और उस जानकारी को उन्होंने जनता तक पहुँचाया। कई प्रैस वालों के सिर फूटे। एक को 19 टाँके आए और एक को 14 टाँके आए। प्रैस वालों की गाड़ियाँ चैक की गईं। उनको वहाँ जाने से रोका गया और उनके कैमरे छिन लिए गए। इतना कुछ होने के बाद प्रैस वालों को दोषी ठहराना उचित नहीं है उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। प्रजातंत्र को कामयाब करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सभापति महोदया, 27 तारीख को पाँच बजे तक बड़े भाँतिपूर्ण ढंग से पोलिंग हुआ कोई विवादास्पद नहीं मिली और कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं थी। वह का प्रबन्ध इन लोगों ने इतना भानदार कर दिया था कि उस दिन वहाँ पर चिड़िया तक नहीं फड़क सकती थी। वहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस की डिप्लायमेंट थी, सारा हरियाणा तो क्या सारे हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा पुलिस की तैनाती की मिसाल सुनने में नहीं आई। वहाँ पर चार डी० आई० जी० रैंक के आफिसर, 15 एस० पी० रैंक के, 40 डी० एस० पी० रैंक के और 15-20 हजार पुलिस के सिपाही तैनात

थे और इसके साथ साथ यह भी चर्चा है कि वहां पर 10 हजार ग्रीन ब्रिगेड के आदमी भी तैनात थे। मेहम के उप चुनाव में इतना भानदान ढंग अपनाया गया था कि उसको यदि हिटलर भी कब्र में सुनेगा तो वह भी भार्मा जाएगा। जिस ढंग से महम मे फासिस्ट सिस्टम अपनाया गया उसकी मिसाल हिन्दुस्तान मे तो क्या सारी दूनिया में नही मिलेगी। सभापति महोदया, 26 तारीख को भाम को ही विपक्ष के उम्मीदवारो की आजाद उम्मीदवारो की और उनको कार्यकताओ की पकड धकड भुरु हो गई थी। हर पोलिंग स्टे इन के सामने नाका बंदी हो गई थी। बैरियर लगने के बाद पुलिस को क्लीयर आदे ा थे, बकायदा प्रिचिंग की गई थी, इस बात की रिपोर्ट इंडिपेंडैन्ट इनीर् एटिव के लोगो ने भी दी है और सबने यह कहा है कि हर पोलिंग स्टे इन के सामने नाका बंदी की हुई थी, बैरियर लगाए हुए थे, पुलिस वालो को स्पष्ट आदे ा थे कि आनंद सिंह डांगी और दूसरे उम्मीदवारो को वहां पर घुसने न दिया जाए, उनके किसी व्हीकल को न घुसने दिया जाए। उन बैरियर्ज पर वे चाहे पुलिस के आदमी थे और चाहे ग्रीन ब्रिगेड के आदमी थे उनकी बूथ कैप्चरिंग की जिम्मेदारी लगाई हुई थी। उनको कमल के फूल का नि गान दिया हुआ था। वे कमल का फूल चाहे हाथ पर लगाकर पोलिंग बूथ मे जाते थे या अपनी जेब पर लगा कर जाते थे, सीधे पोलिंग बूथ में घुस जाते थे, उनको कोई रोक-टोक नही थी। वे बैलट पेपर पर ठप्पा लगाकर चले जाते थे। जो हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट थे उनको गिरफ्तार करके एक तरफ बैठा दिया गया था। सभापति महोदया,

यह 27 तारीख की बात थी और 28 तारीख को वहां पर हिंसा इस तरह की हुई जो बहुत ही भार्मनाक है। वहां पर जो हिंसा हुई, वह क्यों हुई, कैसे हुई इस बात पर भी सन्देह जाता है। मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में यह ब्यान भी दिया था कि मुझे अपनी हार को जीम में बदलना आता है। (गोर)

सभापति महोदया: पूनिया साहब आपने 12 बज कर 50 मिनट पर बोलना भुरु किया था और अब 12 बज कर 59 मिनट हो गए है लेकिन आप केवल मेहम के बारे में ही बोल रहे है। बजट पर आपने एक भी बात नहीं कही है। आप कृपा करके बजट पर बोले।(गोर)

श्री किरपा राम पुनिया: सभापति महोदया, महम का मामला मै समाप्त कर देता हूं।

श्री बनारसी दास चौ गाला: सभापति महोदया, पुनिया साहब को केवल महम ही महम नजर आता है, उनको नीलाखेडी क्यों नहीं नजर आता? (गोर)

13:00 बजे

श्री किरपा राम पुनिया:सभापति महोदया, मै महम का मामला यही पर छोड देता हूं। (विध्न) अब मै इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता।

यहां पर 1987 के चुनावो से पहले 2-3 बातो का बहुत जिक्र आया था और लोगो से वह वायदा किया गया था कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, हम ताना गाना समाप्त करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, गरीब जनता को पूरी तरह से इन्साफ देंगे और परिवारवाद को समाप्त करेंगे। ये सारे वायदे हमने जनता के साथ किए थे। मगर बदकिस्मती की बात यह है यह हमारे प्रेस वाले भाई नाराज है या ख्वामखाह लोगो का दिमाग खराब है तो रोजाना अखबारो में चर्चा रही है कि पुलिस की भर्ती में पैसा खया गया है। इस बारे में चौधरी देवी लाल जी ने कहा भी था कि गृह मंत्री सम्पत सिंह जी ने गलत काम किया है। इसके बाद इस संबंध में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था लेकिन बाद में इनको सुलह सफाई हो गई थी, इस तरह से यह मामला खत्म हो गया था वह अलग बात है। इसी तरह से चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे गुडगांव की बात हो या भामलात जमीन की बात हो या म्युनिसीपल कमेटीकी जमीन खरीदने की बात हो, इनका कुछ कच्चा-पक्का ब्यौरा मेरे पास है। लेकिन मैं उसका यहां पर जिक्र करना नहीं चाहता। मगर इस बात की चर्चा हमें आ रही है कि भामलात की जमीने बहुत सस्ते भाव पर लेकर दिल्ली के कालोनाइजर्ज को खरीदवादी है और इसमें बहुत बडा घपला हुआ है। इस बात की चर्चा बहुत होती है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या आपके पास कोई मिसाल है?

श्री किरपा राम पुनिया: मेरे पास बहुत मिसाले है (विघ्न)।

मुख्य मंत्री (औम प्रका 1 चौटाला): आपने हरिजनो के नाम पर जो जमीन ले रखी है, उसका भी जिक्र कर दो।

श्री बनारसी दास गुप्ता: सभापति महोदया, मैं इनकी एक मिसाल बता देना चाहता हूँ। (विघ्न)

सभापति महोदया: बनारसी दास जी आप बैठिए। इन्हें बोलने दे। आप अपनी मिसाल उस समय दे लेना जब आपको बोलने का समय मिले।

श्री किरपा राम पुनिया: सभापति महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि जो बात मैं भूला हुआ था, उसको सी० एम० साहब ने मुझे याद दिला दिया। पिछले सै। एन में इन्होंने बड़े मटक मटक कर कहा था कि मैं सीधा कर दूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा और पुनिया साहब का खाता खोल दूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको पूरी छूट देता हूँ कि 25 साल की गई हरियाणा सरकार की नौकरी के दौरान, जितने साल भी मैं मंत्री रहा और मंत्री बनने के पहले या बाद में भी जितनी मर्जी आये आप तसल्ली कर लें। अगर किरपा राम पुनिया की एक बात भी गलत साबित हो जाये तो किरपा राम पुनिया राजनीति छोड़ देगा। (विघ्न)

श्री बनारसी दास चौ टाला: आप पहले वाल्मिकियो की जमीन को तो छोड़ दे। राजनीति की बात तो बाद में आती है। (विघ्न)

श्री किरपा राम पुनिया: सभापति महोदया, पिछले सै ान में बोलते हुए इन्होंने मेरे बारे में 4-5 चीजों का जिक्र किया था। इन्होंने उस समय बोलते हुए मेरे बारे में एक कामधुनू भैंस का जिक्र किया था और कहा था कि जब पुनिया सरकारी नौकरी में आया था तो इसके पास सिर्फ एक 600 रुपए की भैंस थी। इन्होंने उस समय मेरे उपर बड़े व्यंग्य कसे थे और बड़े कटाक्ष भी किए थे। मैं इनका बताना चाहता हूँ कि जिस किसी भाई ने भी तरक्की की है वह किसी न किसी तरह से की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिसने भी तरक्की की है क्या वह जमीन जायदाद अपनी मां के पेट से लेकर आए थे? हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई स्टेज तरक्की करने की आती है। मैं औम प्रका ा चौटाला से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बताएंगे कि जो आज के दिन इनकी यह स्थिती है यह सदियों से है? (विघ्न)

चौधरी औम प्रका ा चौटाला: सदियों से नहीं है हमारी यह स्थिती तो पीढियों से चली आ रही है। (विघ्न) अत्री जी जो काम आपने किया है क्या आपकी पीढी में भी पहले किसी ने किया था? (विघ्न)

श्री किरपा राम पुनिया: मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने तरक्की की है लेकिन गलत साधनों से तरक्की नहीं की। कोई लूट-खसोट करके तरक्की नहीं की। जायज तरीकों से और जो जायज साधन हैं उनको इस्तेमाल करके यदि कोई तरक्की करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सभापति महोदया, पिछली बार यहां सदन में बोलते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत ही गैर जिम्मेवाराना तरीके से बहुत ही गलत भावों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने बोलते हुए कहा था कि राजनीति में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अराजनीतिक तत्व और कुछ अपराधिक तत्व आ गए हैं और कुछ ऐसे लोग जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है चोर दरवाजे से इस हाउस में भी आ गए। चोर दरवाजे से कौन आया है उस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। सभापति महोदया, हम इलैक्ट्रॉन जीत कर आए हैं। असामाजिक तत्व क्या होता है। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री ही जानते हैं। अपराधिक तत्व क्या होता है इस बारे में इनके नजरिये की बाबत मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पुनिया ने एक अफसर को चोट मारी थी जिसकी रिपोर्ट दर्ज है, इसलिए पुनिया अपराधिक तत्व है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी घड़ियों की समगलिंग में पकड़े गये थे। (व्यवधान)

सभापति महोदया: बनारसी दास जी आप बैठिये, सदन के नेता खड़े हैं। (विधन) बनारसी दासजी आप पहली बार चुन कर आए हैं इसलिए आपको भायद सदन की परम्परा का ज्ञान नहीं है

कि जब सदन के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी दूसरा सदस्य खड़ा नहीं रहता है।

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: सभापति महोदया, पिछले सत्र में भी यह प्रसंग उठा था और मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था कि मेरे खिलाफ घड़ियों के मामले का केस दर्ज हुआ था। उसकी बकायदा इन्कवायरी हुई थी और इन्कवायरी के बाद मुझे बरी किया गया था। पुनिया साहब के किस्से भी मैं मौका आने पर बताऊंगा।

सभापति महोदया: पुनिया साहब, अब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए। आप अब तक 16 मिनट ले चुके हैं।

श्री किरपा राम पुनिया: आदरणीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 1978 के केस में उन्हें बाइज्जत रिहा किया गया था। (विधन) सभापति महोदया, जहां तक मुझे मालूम है ये बाइज्जत रिहा नहीं हुए थे। मेरे पास सूचना है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना हुआ था। उन्होंने अपील की थी। अपील के बाद जुर्माना 2 हजार से घटा कर एक हजार रुपया किया गया था। (व्यवधान एवं भाोर)

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं डिजनीलैंड का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा जिसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिवैल्प कर रहा है। अमेरिका में लॉस एंजल्स में जो डिजनी वर्ल्ड बना है वह 2000 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। (विधन) हमारे इस मकसद के

लिए 28000 एकड़ भूमि एक्वायर की जा रही है। हमारी हरियाणा सरकार 28 गावों को उजाड़ रही है। जो जमीन एक्वायर की जानी है उसके लिए एक लाख रुपये एकड़ के हिसाब से कम से कम 3 सौ करोड़ रुपये चाहिए है। सभापति महोदया, 600-700 करोड़ रुपये का तो हरियाणा का टोटल बजट है फिर यह 300 करोड़ रुपया कहां से आएगा? (विधन) हरियाणा सरकार का टोटल प्लान बजट 600 करोड़ रुपये प्रति साल का है। इस प्रकार तो कई सालों का बजट कम्पलीट जमीन को खरीदने में ही खर्च हो जाएगा। जब तक मुख्य मंत्री महोदय हरियाणा को टैक्स फ्री स्टेट बनाकर देंगे तब तक 50 साल का बजट तो करीब करीब भूमि खरीदने पर ही खर्च हो जाएगा। इसलिए यह काम स्टेट के लिए कर पाना सम्भव नहीं है। यह सारा काम तो विभिन्न पार्टियों को ठेके पर देना पड़ेगा। फौरेन कन्ट्रीज़ की फर्म यहां आएँ और पैसा खर्च करेंगी। जब फोरन कम्पनियां पैसा खर्च करेंगी तो जो इन्कम होगी वह भी सारी की सारी हरियाणा सरकार को नहीं मिलेगी इन्हीं विदेशी कम्पनियों को जाएगी। यह कहना कि डिजनीलैंड बनाकर हरियाणा का मालामाल कर देंगे यह लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। (व्यवधान)

सभापति महोदया: अब आप एक मिनट में खत्म कीजिए क्योंकि आपने काफी समय पहले ही ले लिया है।

श्री किरपा राम पुनिया: सभापति महोदया, आज के दिन वैसे भी हमारे सामने बहुत से और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें

प्रायरिटी दिये जाने की आवश्यकता है। एस0 वाई0 एल0 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के लिए 15 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि साथ ही साथ सरकार यह भी चाहती है कि इस साल में यह मुकम्मल हो जाए। अभी तो सैंकडो करोड रुपया खर्च होना है। बहुत सारे ऐसे प्रोजैक्टस है जो वैल्फेयर के है। उनके लिए पैसे का प्रावधान करना ज्यादा जरुरी है। 300 करोड रुपये का प्रावधान तो हमारे काबू की बात नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली का कौलोनाइजर इस जमीन को कौडियो के भाव से खरीदेगा और वह मालामाल हो जायेगा। हजारो करोड रुपया उन लोगो को इस जमीन से आएगा। मुझे तो किसी ने एस्टीमेट बताया था कि वे कौलोनाइजर पांच हजार करोड रुपया मुनाफा कमाएंगे।

अब मैं आखिरी बात भाडयूल्ड कास्टस की वैल्फेयर के बारे में अर्ज करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया: आपने 12:50 पर बोलना भुरु किया और अब एक बज कर दस मिनट हो गये है। इसलिए अब आप वाइंड अप करिए।

श्री किरपा राम पुनिया: अभी वाइंड अप करता हूं। भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज की वैल्फेयर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यहां हाउस में खासतौर पर रिकटमेंट के बारे में चर्चा होती है। चाहे पुलिस में कांस्टेबलो की भर्ती हो, चाहे एस एस एस बोर्ड से कन्डक्टर्ज, क्लर्कस और ड्राइवर्ज के

नाम आने की बात हो वही से जितने नाम आने चाहिए थे उतने नहीं आये। वहां पर बड़ी भारी कमी रही है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) जहां तक ओवर आल टोटल पोर्जी इन का सवाल है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यह सूचना हरियाणा गवर्नमेंट की पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिस्टिकल विभाग द्वारा दी गई है इसके मुताबिक क्लास वन में टोटल अधिकारी 1697 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस के 73 है और बैकवर्ड क्लासिज के 37 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस का 237 का भार्टफाल है और बैकवर्ड क्लासिज का 29 का भार्टफाल है। क्लास टू में टोटल अधिकारी 7464 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस के 358 है और बैकवर्ड क्लासिज के 231 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस का 1173 का भार्टफाल है और बैकवर्ड क्लासिज का 538 का भार्टफाल है। इसी तरह से क्लास थ्री में टोटल सरकारी मुलाजिम 163571 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस के 16848 है और बैकवर्ड क्लासिज के 12415 है। इनमें भाडयूल्ड कास्टस का 15982 का भार्टफाल है और बैकवर्ड क्लासिज का 3754 का भार्टफाल है।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाइंड अप करें।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय यहां हाउस में मौजूद है इसलिए उनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। हो सकता है उनके ध्यान में न हो। वैसे तो वे बहुत बड़े राजनैतिक व्यक्ति है और बहुत जागरुक भी है, हरियाणा के मुख्य मंत्री है, उन्हें इनकी सी० आई० डी० देती रहती होगी

क्योंकि इनकी पुलिस बहुत ऐफिं 1यंट है लेकिन जब श्री कम्बोज के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो जाये तो उसे एक मिनट में ही गिरफ्तार कर लिया गया और अगर किसी वर्कर या मिनिस्टर के खिलाफ दर्ज हो जाता है तो महीनो कोई कार्यवाही नहीं होती है। श्री कम्बोज के बच्चो को भी गिरफ्तार कर लिया। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन अफसरों ने उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ इन्होंने क्या ऐक्शन लिया है। पंजाबी भाईयो के खिलाफ पोस्टर्ज छपे। उन पोस्टर्ज छापने वालो के खिलाफ अन्डर सैक्शन 153-ए के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया। क्या ही अच्छा होता कि केस दर्ज होने के साथ साथ कांस्प्रेसी की सैक्शन भी साथ ही लगा देते ताकि सब कुछ कवर कर लिया जाता। जहां तक विकटेमाइजे सैक्शन की बात है, उस बारे में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे साथी यहां बैठे हैं। जो जनहित मोर्चे के एम0 एल0 एज0 हैं उन पर झूठे केस बनाये जाते हैं। हमारे साथी मुन्नी लाल को थ्रीट दी जाती है कि तुम्हारी कोठी गिरा देंगे। इसी तरह से वासुदेव भार्मा, योगे 1 भार्मा, और डी डी अत्री को थ्रीट किया जा रहा है। किसी की बीवी को तीन सौ किलोमीटर तक ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारा कोई मिलने वाला है तो उसे पिदे सी0 आई0 डी0 लगा कर उस पर झूठे केस बनाये जाते हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, विकटेमाइज किया जाता है। मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, कभी यह न कहे कि सूचना नहीं मिली। मैंने डी0 ओ0 लैटर 11 होम मिनिस्टर साहब

को लिखा था और उसकी कापी मुख्य मंत्री जी को भेजी थी कि हरियाणा सरकार ने हमारे जनहित मोर्चे के लोगो से सिक्क्योरिटी विदड्रा कर ली है। उनके गनमैनज् को विदड्रा कर लिया है। यह बात मै आपके नोटिस में ला रहा हू। मुझे डी0 ओ0 लैटर लिखे हुए आज तीन महीने हो गये है। इनकी तरफ से अभी तक तीन महीने में डी0 ओ0 का कोई उतर नहीं आया। श्री मुनी लाल, श्री योगे । भार्मा, श्री लछमन दास कम्बोज, श्री हरि सिंह सैनी, श्री वासुदेव भार्मा आदि से गनमैन विदड्रा कर लिए है। कभी ऐसा न हो कि ग्रीन ब्रिगेड के लोग इन को रास्ते में पकड कर हमला कर दें।

Mr Speaker: Do not presume these things

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल सही बात है। इस तरह की हरकते हो चुकी है। इन भाब्दो के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मै अपना स्थान लेता हू।

श्री िव प्रसाद(अम्बाला भाहर): अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो बजट रखा गया है, जिसको कर मुक्त बजट कहा जा रहा है, इसमें घाटा भी है। खर्चे में कमी करके, कुछ छापे लगाकर और करो में जो चोरी होती है उसकी रिक्वरी करके उस घाटे को पूरा करने के लिए कहा गया है। मै तो इस बारे में केवल एक दो बातें ही कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि जो हमने खर्च कम करने के लिए कहा है इस बारे में आम जनता को पता लगना चाहिए कि सरकार ने कौन कौन से खर्चे कम किये है ताकि लोगो

को जो हमने इस बात का वि वास दिलाया है इस बारे में हमारे प्रति उनका वि वास बन सके। दूसरे यह बात ठीक है कि हरियाणा सरकार में अनपढता के कारण बड़ी चिंता है और गांव गांव तक शिक्षा का प्रचार हो, उस दृष्टी से पिछले वर्ष भी हर विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, और हाई से 10 जमा 2 स्कूल अपग्रेड किये गये हैं। चालू वर्ष के दौरान भी 175 के लगभग अलग अलग स्तर के स्कूल अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। महिलाओं की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा के लिए सौ के लगभग विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस तरह का भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शिक्षा शिक्षा ही है, चाहे वह सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है। अगर हम बोर्ड के रिजल्ट को सामने रखकर देखें तो उसमें से हम अगर प्राइवेट स्कूलों के परिणाम को माईनस कर दें तो सरकारी स्कूलों की जो परसेंटेज आती है वह बहुत कम है। प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक काफी देर से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। मगर उनकी बात की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। अन्त में उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 21-2-1990 को उनके हम को फैसला दे दिया है। सरकार ने भी कुछ उनको अब वि वास दिलाया है कि जून तक आपको पहली किस्त देंगे जिसमें मैडिकल अलाउंस, सी0 सी0 ए0, हाउस रेंट और ग्रैचुअटी ऐटसैट्रा भामिल है। मेरा कहना यह है कि जो स्कूलज प्राइवेट मैनेजमेंट है, उसको बुलाकर

पहले बातचीत कर ली जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यापको को अपनी बात मनवाने के लिए सडको पर आना पडे यह प्रदे 1 के हितमे भी नही है। साथ ही एक बात और मै कहना चाहता हूं। अभी बोलते हुए बहन सुशमा जी ने कहा था कि कालेज और स्कूलो की ग्रान्ट में कुछ अन्तर है। कालेजिज को हम 95 प्रति 100 ग्रान्ट देते है लेकिन स्कूलो को 75 प्रति 100 ग्रान्ट देते है। एक बात हमने यह देखी है कि प्राइवेट स्कूलो में फीस मनमाने ढंग से ली जाती है जबकि वह फीस उनकी आय में नही दिखाई जाती। मै यह बात दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम उनको 95 परसेंट ग्रान्ट दे दे तो भायद सरकार को बहुत कम बजट इस पर खर्च करना पडे। वह इसलिए क्योकि प्राइवेट स्कूलो वाले जो फीसे लेते है, अगर वह सरकार ऐप्रूव कर देगी तो वह फीस से आने वाली आय भी उसमें शामिल हो जायेगी। मै यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से 95 प्रति 100 ग्रान्ट अगर यह सरकार देगी तो इसका क्रेडिट सरकार को जाएगा कि कालेजिज के मुकाबले में इस ने स्कूलो को भी 95 प्रति 100 ग्रान्ट दी है। जिस तरह से कालेज के प्रोफैसर्ज को ट्रेजरी से तनखावाह दी जाती है, प्राइवेट स्कूलो के अध्यापको को भी ट्रेजरी से या बैंकस की मार्फत तनखावाह दी जाएगी। इस तरह से जो प्राइवेट स्कूलो में तनखावाह कम मिलती है और छः छः महीने तक तनखावाह मिलती ही नही है, वह समस्या भी लगभग समाप्त हो जाएगी। पिछले दिनो स्कूलो को अपग्रेड करने की बात आई थी। मै इसके साथ ही साथ अपने हल्के का भी जिक्र करता रहूंगा। पिछली बार मैने बोलते हुए कहा था कि

अम्बाला भाहर में और अम्बाला छावन में कोई भी सरकारी कालेज नहीं है और उस समय बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप तो 10 जमा 2 की बात करते हैं, मैं तो वहां पर कालेज बनाना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया था। मेरी प्रार्थना है कि अम्बाला भाहर में लडकियों का एक कालेज हर हालत में बनाया जाना चाहिए ताकि यह कडिट इस सरकार को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में मैडिकल कालेज खोलने के बारे में कुछ अडचने बताई जाती हैं। जैसे आबादी की भात या कुछ और भाते हैं जिन्हे केन्द्रीय सरकार पूरे हुए बिना मैडिकल कालेज खोलने की परमिशन नहीं देती। इसमें अगर दिक्कत है तो वहां पर कम से कम इंजीनियरिंग कालेज अवश्य खोल दिए जाए क्योंकि अम्बाला एजूकेशन का सैन्टर है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय, पंजोखो गए थे और वहां पर स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ था। वे स्कूल को बहुत कुछ देकर आए। चार दीवारी के लिए पैसा दिया और दो कमरों को बनाने के लिए रुपया देकर आए थे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पंजोखेडा को 10 जमा 2 का स्कूल बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में जो स्टाफ की दिक्कत है उस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में स्टाफ की जो पोस्टस रिक्त हैं वह पहले बच्चों की संख्या के आधार पर होती हैं लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसके बाद बच्चों की संख्या के मुताबिक पोस्टस की इजाजत नहीं मिलती। जैसे पी0 के0 आर0 जैन सीनियर सैकेण्डी

स्कूल, अम्बाला है। उसमें छब्बीस अध्यापक हैं जिनकी मंजूरी है और बत्तीस ऐसे हैं जिनकी मंजूरी नहीं है। जब 26 का स्टाफ मंजूर था उस वक्त 750 विद्यार्थी थे और अब 2500 विद्यार्थी हैं। इसी स्कूल में कुछ टीचर तो ज्यादा तनखाह ले और चूकी मैनेजमेंट को ग्रांट नहीं मिलती इसलिए वह मैनेजमेंट उस स्कूल के बाकी टीचर्स को कम तनखाह दे तो यह अन्तर मन में आता पैदा करता है। जब एक ही क्वालिफिकेशन के काम करने वालों में कुछ को कम तनखाह मिले और कुछ को ज्यादा मिले तो मन में असंतोश रहता है। इसलिए इस मतभेद को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि जैसे ही सरकार के पास टीचर्स की संख्या बढ़ाने के बारे में मांग आए उस डिमाण्ड के मुताबिक उसको मंजूरी मिल जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है। कांग्रेस भासन में लोगों के साथ एक धोखा हुआ, अब इस सरकार को उस धोखे को खत्म करना चाहिए। बात यह थी कि नगरपालिकाओं के मकानों की जब हाउस टैक्स की असैसमेंट हुई तो उसका फैसला करते समय पहले जनता पार्टी के भासनकाल में 120 रुपये जो एनुअल रेंटल वैल्यू थी वह कांग्रेस के भासनकाल में छः सौ रुपये कर दी गई। कांग्रेस के भासन काल में उनको यह कहा गया कि सौ रुपया पर मंथ की माफी दे देंगे। जिन लोगों के मकानों पर टैक्स लगा और जब वे इसका फैसला कराने गए तो मकान मालिकों को यह कह दिया गया कि सौ रुपये महीने का टैक्स माफ

कर दिया है लेकिन तीन चार महीने के बिल उनके पास हाउस टैक्स के चले गए। लोगो ने कहा कि ये हमारे पास कैसे आ गए। उनको कहा कि नहीं एक हजार सालाना रैन्टल वैल्यू का फैसला किया है। सौ रुपए महीने के हिसाब से तो बारह सौ रुपया होता है। एक हजार और बारह सौ रुपएके बीच में जिन मकानो के मालिको पर हाउस टैक्स लग गया, वे अपील नहीं कर सकते थे क्योंकि एक महीने का अपील का समय होता है। अपील का समय भी निकल गया और लि उनको पास आ गए। आज के युग में तो एक हजार या 1200 रुपए कोई मायने नहीं रखते। मैं सरकार से कहूंगा कि ये बहुत छोटे मकान है जिनके उपर यह टैक्स लगा दिया है। मेरी प्रार्थना है कि इसकी जो सीमा है वह बढ़ाकर दो सौ रुपए महीने के हिसाब से एक साल की रैन्टल वैल्यू जो 2400 रुपए बनते है, टैक्स से माफी दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों सरकार ने बहुत से प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोले है ताकि लोगो को सुविधा हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बाला के अस्पताल का रिा लान्यास फरवरी, 1980 में हुआ था। आज दस साल हो गए, ग्याहरवां साल भुरु हो गया है लेकिन उस अस्पताल की हालत किसी से छिपी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस वर्ष में हर हालत में वह हस्पताल पूरा करना चाहिए क्योंकि आस पास के सारे लोग वहां इलाज कराने आते है। मुख्य मंत्री महोदय, पंजोखेडा गए थे। वहां

के लोगो की डिपाण्ड थी कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोला जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने लोगो से कहा था कि वहां प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खुल जाएगा। पंचायत ने वहां पर जमीन दे दी है। मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी का आ वासन पूरा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन के बारे में कहना चाहता हूं। प्रो० सम्पत सिंह जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला बना दिया गया है और दिल्ली से वाया कुरुक्षेत्र वीडियो कोच बस भुरु कर दी है। मैं कहना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है लेकिन कोई वीडियो कोच बस अम्बाला भाहर होकर नहीं आती और सवारियो को अम्बाला छावनी जाकर वीडियो कोच पकडनी पडती है। अम्बाला भाहर इस लाभ से वंचित है। अगर डिलक्स और वीडियो कोच, जो चण्डीगढ से दिल्ली जाते है और दिल्ली से चण्डीगढ आते है, उनको अम्बाला भाहर के बस स्टैण्ड के एक दरवाते से लाकर दूसरे दरवाजे से निकाल दिया जाए और इस तरह से अम्बाला छावनी से इसको जोड दिया जाए तो अम्बाला भाहर के लोग बस स्टैण्ड पर डीलक्स बस का लाभ उठा सकते है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और अम्बाला भाहर जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है उसको हर हालत में डिलक्स तथा वीडियो कोच के साथ जोडने की कृपा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बलदेव नगर कैम्प के पास, भाहर के साथ साथ

हाउगि बोर्ड कालोनी बन गई है और वहां की आबादी भी बहुत बढ़ गई है जिस कारण से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चण्डीगढ़ से दिल्ली व दिल्ली से चण्डीगढ़ आने जाने वाली बसें वहां पर रुक कर जानी चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। पिछली बार भी मैंने इस बारे में जिक्र किया था लेकिन बसों के वहां न रुकने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः सरकार इस ओर अवय ध्यान दें। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी प्रार्थना की थी कि बलदेव नगर कैम्प के पास भाहर के साथ एक मिनी लोकल बस स्टैण्ड बन जाए तो बेहतर रहेगा जिससे आस पास के लोगों के बसों में यात्रा करने में काफी सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं सरकार से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बलदेव नगर कैम्प में अगर एक डी० एफ० एस० ओ० का आफिस खोल दिया जाए तो किसानों को काफी सुविधा रहेगी। जो किसान अपना अनाज बेचने के लिए वहां जाएंगे उनको वहां पर ही पेमेंट हो जाएगी। इसके लिए उन्हें दायें बाएं नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि स्पेस तौर पर वहां के लिए एक डी० एफ० एस० ओ० की पोस्ट किएट की जाए।

इसी तरह से अम्बाला भाहर के अन्दर जो 66 के० वी० का सब-स्टेशन सरकार लगाने जा रही है उसको भीघ से भीघ

इंस्टाल किया जाए। पैं इन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि किसी 75 रुपए मासिक और किसी को 100 रुपया मासिक पैं इन मिलती है। इस डिसपैरिटी को समाप्त करके सभी की पैं इन 100 रुपया मासिक कर दी जाए। चाहे कोई विकलांग है, चाहे कोई वृद्ध है। सभी को 100 रुपए मासिक पैं इन मिलती चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो काफी हेरा फेरी होने का अन्दे गा हो सकता है जो लोग 75 रुपये मासिक पैं इन पाते हैं, वे 100 पैं इन की चेश्ठा करेंगे और जो कम उम्र के लोग हैं, वे अपनी उम्र ज्यादा लिखवा कर हेराफेरी से ज्यादा पैं इन प्राप्त करना चाहेंगे। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि सभी को एक समान पैं इन मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव से पहले हर पार्टी अपना घोशणा पत्र घोशित करती है। वर्ष 1987 के चुनाव में बी० जे० पी० ने व दूरी पार्टी ने अपना घोशणा पत्र घोशित किया। जनता दल ने जो पहले लोकदल थी, उन्होंने भी अपना घोशणा-पत्र जारी किया था।

श्री अध्यक्ष: मास्टर जी आपका केवल एक मिनट ही रह गया है।

श्री िव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलते हुए थोडा ही समय हुआ है। दूसरे तो 24-25 मिनट तक बोलते रहे। खैर, अध्यक्ष महोदय, अगला प्वायंट मैं यह कहने जा रहा हूं कि

जो हाउसिंग बोर्ड कालोनिज है या अर्बन एरियाज में प्लॉटस दिये गये हैं, उनके उपर ऐन्हांसड् प्राईस का जो सिलसिला है, बस बारे में सरकार ने कहा है कि एक कमेटी बनेगी ओर वह कमेटी नो-प्रोफिट ओर नो लॉस के आधार पर यह फैसला करेगी और जब तक कमेटी का फैसला नहीं होगा तब तक किसीके पास ऐन्हांसमेंट प्राईस का नोटिस नहीं जाएगा लेकिन हुआ क्या कि वह कमेटी बनी नहीं और लोगो के पास ऐन्हांसमेंट प्राईस के नोटिस भेजे गये है। अम्बाला के अन्दर एक एक प्लॉट पर तीन तीन बार ऐन्हांसड प्राईस नोटिस भेजा गया है। पहली बार 83 में, दूसरी बार 85 में और तीसरी बार 88 में। हमारे सामने स्पीकर साहब, ऐसे बहुत से केसिज आते है। होता क्या है कि हम एक आदमी की जमीन एक्वायर करते है और वह सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में चला जाता है। अगर सरबार जमीन एक्वायर करते समय ही आस पास के इलाके की जमीनो की कीमतो का जायजा लेकर एक्वायर की गई जमीन की कीमतो को फिक्स करे तो लोगो में किसी प्रकार की कोई सरकार के प्रति दुर्भावना नहीं होगी या जनता के सलाह म विरा के साथ ही जमीनो की कीमतें फिक्स की जाएं तो जनता में किसी प्रकार का रोश नहीं होगा। लोग कोर्टस में नहीं जाएंगे और सब कुछ उनकी रजामन्दी के साथ ही तय हो जाया करेगा। मान लिजिएगा कि भुरु मे अगर सरकार की ओर से किसी को प्लॉट, जमीन या बना हुआ एक कमरे का मकान 31 हजार मे मिलेगा, दूसरी बार भायद उसे ज्यादा कीमत में मिलेगा और जब दो सालो के बाद हम कीमत

बढाकर भेजते है तो उतनी कीमत देना उस आदमी की भाक्ति से बाहर हो जाता है। न तो वह उस मकान को रख सकता है न छोड सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले ही जो प्राईस सरकार की ओर से फिक्स की जाए उसी के अनुसार ही पेमेंट ली जाए जिससे लोगो को किसी प्रकार की दुविधा में न फंसना पडे।

श्री अध्यक्ष: मास्टर जी आप का टाईम ओवर हो गया है अब हाउस कल सुबह नौ बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

13:30 बजे

(तत्प चात सदन भुक्क वार दिनांक 16-3-90 को प्रातः 9:30 बजे तक स्थगित हुआ)